



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 185]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2010

विषय :—भारत में कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित रक्षोपाय शुल्क संबंधी जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

सा.का.नि. 306(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं उसके सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 को ध्यान में रखते हुए;

प्रक्रिया

1. भारत में कास्टिक सोडा के संबंधित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के सतत खतरे से कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने हेतु भारत में कास्टिक सोडा के संबंधित आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत विहार कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था । इस बात से संतुष्ट होकर कि नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी कर ली गई थीं । सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत भारत में कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना दिनांक 20 अगस्त, 2009 को जारी की गई थी जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

2. सूचना की एक प्रति प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से भिजवाई गई थी। जांच शुरुआत सूचना की एक-एक प्रति सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों, जिनकी सूची निम्नानुसार है, को भी भिजवाई गई थी :—

घरेलू उत्पादक

क्र. सं	इकाई का नाम	फैक्ट्री का पता
(1)	(2)	(3)
1.	आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लि. (पूर्ववर्ती बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लि.)	घनश्याम कुंज, गढ़वा रोड, डाकघर-रेहला-822124 जिला-पलामू, (झारखंड) दूरभाष : 06584-262211/21/262488 फैक्स : 06584-262205 ई-मेल : shyam.gupta@adityabirla.com ajay.todi@adityabirla.com

2	आदित्य बिरला नूवो लि.	इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल - 362 266 (गुजरात) दूरभाष: 02876-245711 (ईपीबीएक्स) फैक्स: 02876-243220/243558 E-mail: irilveraval@adityabirla.com ajay.todi@adityabirla.com
3	अतुल लि.	डाकघर- अतुल- 396020 जिला-वलसाड (गुजरात) दूरभाष: 02632-233261 - 65 फैक्स: 02632-233619 / 375 ई-मेल: vasudev_koppaka@atul.co.in ; pradip_pisharody@atul.co.in
4	सेंचुरी रेयॉन (सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंड. लि. का एक प्रभाग)	मुर्बादि रोड, पो.बै. नं. 22, शहाद- 421 103 जिला-थाणे, महाराष्ट्र दूरभाष: 0251-2733670 / 79 फैक्स: 0251-2730064 ई-मेल: cenray@cenrayon.com saluthra@cenrayon.com
5	कैमफैब अल्कलीज लि.	ज्ञानानंद प्लसे, कालापेट पुडुचेरी- 605 014 दूरभाष: 0413-2655111 फैक्स: 0413-2655125 ई-मेल: chemfabalkalis@draoholdings.com
6	कैमप्लास्ट सन्मार लि. (कैमिस्टिक क्लोर डिविजन)	फैक्ट्री-I, प्लॉट-III, मेडूर डैम-636 402 जिला-सेलम (तमिलनाडु) दूरभाष: 04298-230381 - 85 फैक्स: 04298-230394 ई-मेल: sp1@sanmargroup.com फैक्ट्री-II मेलावन्जोर, गाँव कराइकल, संघराज्य क्षेत्र पुडुचेरी- 611 002 दूरभाष: 04365-256475 / 76 फैक्स: 04365-256473 ई-मेल: vr13@sanmargroup.com
7	डीसीएम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि. (कोटा एवं झगड़िया)	1. श्रीराम विनायल एंड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा-324 004 (राजस्थान) दूरभाष: 0744-2480991-98, 0744-2480011-17 / 2480907-08 फैक्स: 0744-2481131 ई-मेल: tejkrishen@dscl.com 2. श्रीराम अल्कली एंड कैमिकल्स, 749, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, झगड़िया-393 110 जिला-भरूच (गुजरात) दूरभाष: 02645-226021-23 / 224026-27 फैक्स: 02645-226037 ई-मेल: scmittal@dscl.com
8	डीसीडब्ल्यू लि.	डाकघर शाहुपुरम-628 229, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु दूरभाष: 04639-280231 / 439 / 014 / 281288 फैक्स: 04639-280611 ई-मेल: ttn_dcwshpm@sancharnet.in ;

9	दुर्गापुर कैमिकल्स लि.	हेनिमन सरणी, जिला बर्धवान, दुर्गापुर-713 215 प. बंगाल दूरभाष: 0343-2556668 / 2555762 फैक्स: 0343-2556667 ई-मेल: dcldgp@sancharnet.in akupadhyay@durgachem.com
10	जीएचसीएल लि.	गाँव सूत्रपद, तालुका बेरावल, जिला जूनागढ़- 362265 (गुजरात) दूरभाष: 02876-283401-3/283409-10/283551-3/ 280206 फैक्स: 02876-283483 / 283480 ई-मेल : tej@ghcl.co.in
11	ग्रेसिम इंड. लि. कैमिकल डिविजन	डाकघर बिरलाग्राम, नागदा-456 331 (मध्य प्रदेश) दूरभाष: 07366-246760-66 फैक्स: 07366-246176 / 246097 ई-मेल: ajay.todi@adityabirla.com ; Kailash.jhanwar@adityabirla.com
12	गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल लि.	(1) बड़ौदा यूनिट डाकघर पेट्रोकेमिकल्स-391 346 जिला-बड़ौदा (गुजरात) दूरभाष: 0265-2232681 / 701 / 183 / 2230085 / 3061200 / 6540463 फैक्स: 0265-2232130 / 2230032 ई-मेल: general@gacl.co.in marketing@gacl.co.in (1) दाहेज यूनिट डाकघर दाहेज, तालुका विघ्रा, जिला भरुच-392130 (गुजरात) दूरभाष: 02641-256315 - 17 फैक्स: 02641-256220 ई-मेल: mktddahej@gacl.co.in
13	गुजरात फ्लोरो कैमिकल्स लि.	12/ए, जीआईडीसी, दाहेज औद्योगिक क्षेत्र, विघ्रा तालुका, जिला-भरुच- 392 130 (गुजरात) दूरभाष: 02641-308062 फैक्स: 02641-308012 ई-मेल: jsbedi@gfl.co.in
14	हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स (प्रो. केशवराम इंड. लि.)	19, बैरकपुर ट्रंक रोड, खारदाह, डाकघर बलराम धर्म सोपान, कोलकाता-700116 दूरभाष: 033-25532879/5183, 25839545 / 77 फैक्स: 033-25533860, 25839218 ई-मेल: hhcl_fac@vsnl.net hhc_ho@vsnl.net factory@hhckil.com
15	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक्स कैमिकल्स लि.	हरचंदराय हाउस, 81, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई-400002 दूरभाष: 022-22014269 - 71 फैक्स: 022-22059533 ई-मेल: ravimadangeri@hoclindia.com

16	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पो. लि.	फैक्ट्री-I नगाँव पेपर मिल, डाकघर कागजनगर, जिला मोरीगाँव-782 413 (असम) दूरभाष: 03678-245900 - 10 फैक्स: 03678-245911 इ 13 ई-मेल: himanish@hindpaper.in adhikari@hindpaper.in फैक्ट्री-II कछार पेपर मिल, डाकघर पंचग्राम- 788 802 जिला हैलाकंडी (असम) दूरभाष:03845-273080 / 273086 / 273214-6 फैक्स: 03845-273130 ई-मेल: kacharya@hindpaper.in
17	एचजेआई- ओरिएण्ट पेपर मिल्स का प्रभाग (प्रो. ओरिएण्ट पेपर एंड इंड. लि.)	डाकघर अमलाई पेपर मिल्स, जिला-अनूपपुर-484 117 (मध्य प्रदेश) दूरभाष:07652-286563 / 178 / 179 फैक्स: 07652-286290 ई-मेल: hjigmmco@sancharnet.in hukum_113@rediffmail.com
18	जयश्री कैमिकल्स लि.	डाकघर जयश्री, जिला गंजम-761 025 (उड़ीसा) दूरभाष:06811-254319 / 20 / 36 / 254170 फैक्स: 06811-254384 ई-मेल: jclgm@jayshreechemicals.com
19	कनौरिया कैमिकल्स एंड इंड. लि.	क्लोर-अल्कली (वर्क्स)- रेनुकूट डाकघर रेनुकूट-231 217, जिला-सोनभद्र (उ. प्र.) दूरभाष: 05446-252044 / 55 / 75 फैक्स: 05446-252088 ई-मेल: renukoot@kanoriachem.com
20	लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लि.	एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301 030 (राजस्थान) दूरभाष: 0144-3202817 / 19 / 2881056 फैक्स: 0144-2881360 ई-मेल: jagtar.singh@lordschloro.com
21	मेघमणि फाइन कैम लि.	सीएच 1 तथा 2, जीआईडीसी दाहेज, डाकघर दाहेज-392 130 जिला भरुच, गुजरात दूरभाष: 02642-238025 फैक्स: 02642-238026 ई-मेल: mhania@meghmani.com dhruv.joshi@meghmani.com
22	निरमा लि.	कैमिकल कॉम्प्लेक्स, गाँव कालातलाव, तालुका एवं जिला भावनगर-364 313 दूरभाष: 0278-2885301 - 4 फैक्स: 0278-2885309 - 19 ई-मेल: nirma_kalatalav@nirma.co.in
23	एनआरसी लि.	मोहोन- 421 102 कल्याण के निकट, जिला-थाणे (महाराष्ट्र) दूरभाष: 0251-2270312-5 (9251 मुंबई से)

		फैक्स: 0251-2270316 (9251 मुंबई से) ई-मेल: nrcworks@vsnl.com ; nrcworks@bom7.vsnl.net.in ; dbsjindani@hotmail.com
24	पंजाब अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि.	नंगल-ऊना रोड, नयानंगल- 140 126 जिला-रोपड़, पंजाब दूरभाष: 01887-220750-53 फैक्स: 01887-220742 ई-मेल: pacinlgl@sify.com
25	रिलायंस इंड. लि.	डाकघर दाहेज, तालुका विघ्रा, जिला भरुच-392130 (गुजरात) दूरभाष:02641-282301 फैक्स: 02641-283081 ई-मेल: chappidi.babu@ril.com Jyotindra.m.shah@ril.com
26	सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.	डाकघर बिरलासागर, पोरबंदर-360 576 (गुजरात) दूरभाष: 0286-2242479-81 (3 lines) 0286-2205242 (Sales Deptt.) फैक्स: 0286-2245431 ई-मेल: gmmrkt@saukemindia.com sales@saukemindia.com
27	एसआईईएल कैमिकल कॉम्प्लैक्स (मवाना शुगर्स लि. की एक यूनिट-पूर्ववर्ती सीएल लि.)	चरत्रमपुर, गाँव खडौली, सरदारगढ़, डाकघर राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब-140 401 दूरभाष: 01762-228540 - 48 फैक्स: 01762-225403 ई-मेल: info@sielchemical.com
28	सोलरिस कैमैक इंड. लि. (क्लोर-अल्कली तथा फॉस्फेट व्यवसाय)	यूनिट: कारवार, बिनागा कारवार-581307 जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक दूरभाष: 08382-230535 / 230638 फैक्स: 08382-230468 ई-मेल: umesh.shenoy@solarischemechemtech.com
29	श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलाइड कैमिकल्स लि.	गोंडिपारला, कुनूल- 518 004 (आंध्र प्रदेश) दूरभाष: 08518-280006-8, 280053 फैक्स: 08518-280098 ई-मेल: sraacmktg@tgvmail.net sraacengg@yahoo.co.in sraaclab@rediffmail.com
30	तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. (भारी रसायन प्रभाग) (पूर्ववर्ती: एसपीआईसी लि.)	मनाली एक्सप्रेस हाईवे, मनाली चेन्नई- 600 068 तमिलनाडु दूरभाष: 044-25941870 फैक्स: 044-25941332 ई-मेल: tplisd@sancharnet.in ravindran@tnpetro.com
31	टाटा कैमिकल्स लि.	मीठापुर- 361 345, जिला ओखामंडल, जामनगर (गुजरात) दूरभाष:02892-665991-98. फैक्स: 02892-223361

32	दि आंध्रा शुगर्स लि. (कवुर/सर्गोडा)	सर्गोडा- 534 318 जिला प. गोदावी (आंध्र प्रदेश) दूरभाष: 08811-253418 / 28 फैक्स: 08813-231218 ई-मेल: info.kvr@theandhrasugars.com
33	द त्रावणकोर कोचीन कैमिकल्स लि.	पो. बैंग सं. 4004, उद्योग मण्डल, पो.ऑ. कोच्चि- 683 501 (केरल) दूरभाष.: 0484-2545011-20 / 2545583 फैक्स: 0484-2546564, 2545583 ई-मेल salestcc@vsnl.net marketing@tcckerala.com mail@tcckerala.com
34	तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	हार्बर कंस्ट्रक्शन रोड एसपीआईसी नगर तूतीकोरिन- 628 005 दूरभाष. 0461-2355612 - 13 / 2355615 - 16 फैक्स: 0461-2355376 ई-मेल: ttn_ank@sancharnet.in headworks@tacfert.com
35	यूनाइटेड फॉस्फोरस लि.	750 जीआईडीसी, पो. बा. सं. 9, झगड़िया- 393 110 जिला-भरुच, गुजरात दूरभाष. 02645-226011 - 15 फैक्स: 02645-226017

आयातक

- क. अभय कैमिकल्स लि., 150 गायत्री चैम्बर्स, आर सी दत्त रोड, अल्कापुरी, बड़ौदा-390005, गुजरात
- ख. अल्ब्राइट विल्सन कैमिकल्स लि., फिनिक्स हाउस, " ए " विंग, चौथा तल, 462 सेनापति बापत मार्ग, लोअर पैरल (प.) मुंबई-400013
- ग. अरविन्द मिल्स लि., नरौदा रोड, अहमदाबाद-380025, गुजरात
- घ. बिरला सेल्यूलोज लि., बिरला धाम, खारच, कोसाम्बा, आरएस 374120, जिला-भरुच, गुजरात
- ड. सेंट्रल पल्प मिल्स लि., नेहरू हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- च. दीपक नाइट्राइट लि., 4/12, जीआईडीसी कैमिकल्स कॉम्प्लेक्स, नंदेसारी-391340, गुजरात
- छ. गोदरेज सोप्स लि., ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विब्रोली (पू.), मुंबई-400049
- ज. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि., पी. ओ. नर्मदा नगर-392015, भरुच, गुजरात
- झ. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि., पी.ओ.-फर्टिलाइजर नगर, बड़ौदरा, गुजरात
- ञ. इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोप. लि., पी.ओ.-कस्तूरीनगर-382483

- ट. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., गुजरात रिफायनरी, पी.ओ.-जवाहर नगर, बड़ोदरा, गुजरात
- ठ. जयसिंथ डाइकैम लि., 301, सुमेर केन्द्र, पाण्डुरंग बढकर मार्ग, वरली, मुंबई-400018
- ड. लिंक फार्मा लि., बी-2, छठा तल, रामकृष्ण चैम्बर्स प्रोडक्टिविटी रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390005, गुजरात
- ढ. मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि., 188/184, फेज-11, जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाता, अहमदाबाद-382445, गुजरात
- ण. नर्मदा कैमेच्योर पेट्रोकेमिकल्स लि., दूसरा तल, स्काइलाइन बिल्डिंग, भरुच रेलवे स्टेशन के पास, भरुच, गुजरात
- त. निरमा लि., निरमा भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात
- थ. पैब कैमिकल्स (प्रा.) लि., सूर्य किरण कॉम्प्लैक्स, पहला तल, ओल्ड पेड्रा रोड, पो. बैग सं. 4059, बड़ौदा-390005, गुजरात
- द. रामान्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लि., ग्राम बड़बोधन-395005, तालुक कोलपार, जिला-सूरत, गुजरात
- ध. रुबामिन लि., सिनर्जी हाउस, सुभानपुरा बड़ौदा-390023, गुजरात
- न. सबैरो ऑर्गेनिक्स लि., ए-302, फिनिक्स हाउस, तीसरा तल, 462, सेनापति बापत मार्ग, वरली (पू.), मुंबई-400013
- प. टौरेंट गुजरात बायोटेक लि., श्री राम चैम्बर सर्किट हाउस के सामने, आर सी दत्त रोड, बड़ौदा-390005, गुजरात
- फ. ट्रांसपैक सायलॉक्स इंडस्ट्रीज लि., कालाही एटलांडा रोड, बड़ोदरा-390012, गुजरात
- ब. नेशनल अल्यूमीनियम कं. लि., नाल्को भवन, ई-37, साइट बी, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.
- ब. सायनाइड्स एंड कैमिकल्स कं., प्रोप. हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कॉर. लि. कॉर्प लि., 65, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
- भ. डेमोसा कैमिकल्स लि., 105, ए मित्तल टॉवर्स, 210, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
- म. हित्यु इंड. लि., प्लॉट सं. 306/2, फेज-11, जीआईडीसी, वापी, गुजरात
- य. श्रीरामचन्द्र स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि., ग्राम-विजयपुर, तहसील-वेल्लारी, मुरादाबाद, उ. प्र.
- र. लिब्रा फोम्स एस बी डिस्ट्रीब्यूटर्स लि. का प्रभाग, ई-37, साइट-बी, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.
- ल. अदांनी विल्मर लि., नेवीनल टायन्ड, मुंद्रा-कच्छ, गुजरात
- व. अदांनी एक्सपोर्ट्स लि., अदांनी हाउस, श्रीमली सोसायटी, मावरंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात
- श. दौराला ऑर्गेनिक्स लि., हिमालय हाउस, कस्तूरबा गाँधी रोड, नई दिल्ली
- ष. विलाग इंड. प्रा. लि., प्लॉट सं. 306/3, फेज-11, जीआईडीसी, वापी, गुजरात
- ह. श्रीरामचन्द्र स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि., ग्राम-विजयपुर, तहसील-वेल्लारी, मुरादाबाद, उ. प्र.

- क्ष. लिब्रा फोम्स एस बी डिस्ट्रीब्यूटर्स लि. का प्रभाग, ई-37, साइट-बी, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.
- त्र. दौराला ऑर्गेनिक्स लि., हिमालय हाउस, कस्तूरबा गाँधी रोड, नई दिल्ली, पी/एल नायापल्ली, भुवनेश्वर-751013, उड़ीसा
- ज्ञ. हरीश कुमार एंड कं., 23, अनंत बिल्डिंग, 21, एस गाँधी मार्ग, मुंबई-400002, सी जे शाह एंड कं., 105, बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-21
- कक. हिन्दुस्तान लिवर लि., हिन्दुस्तान लिवर हाउस, 165/166, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई- 400020
- खख. हिन्दुस्तान लिंक एंड रेजिन्स लि., बिलखिया हाउस, मुक्तानंद मार्ग, छाला, वापी, गुजरात
- गग. मै. वेदान्ता एल्युमिनियम लि., वाया विस्वानपुर, पो.ऑ. लांगीगढ़, 766027 जिला-कालाहांडी, उड़ीसा
- घघ. एल्युमिनियम एसोसिएशन आफ इंडिया, 118, पहली मंजिल, एकेड, 18, एम.जी. रोड, बंगलौर-560 001 वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, नाल्को, वेदान्ता एंड भारत एल्युमिनियम कं.

निर्यातक

- डड. असाहीमास कैमिकल्स पीटी, 9वाँ तल, समिटमास I, जेआई, जेंद, सूदीरमन केएवी, 61-62, जकार्ता, 12190, इंडोनेशिया
- चच. पीटी पैब्रिक केरतास, जिवि किमिया टीबीके, प्रधान कार्यालय बिल्डिंग ए, जेआई, राया सुराबाया-मोजोकेर्तो केएम. 44, मोजोकेरतो 61301, जावा तिमोर, इंडोनेशिया
- छछ. पीटी सल्फाइंडो आदियुसाहा पीटी. सल्फाइंडो आदियुसाहा, 14वाँ तल, रातु प्लाजा, ऑफिस टॉवर, जेआई जिद, सुदीरामन, केएवी 9, जकार्ता जकार्ता, 102702, इंडोनेशिया
- जज. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके, बी-11 प्लाजा, मिनारा 11, लांताई 7, जेआई, एमएच, तामरिन, नं. 51, जकार्ता-10350, इंडोनेशिया
- झझ. फार्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पो. 201, तुंगहुआ नॉर्थ रोड, ताइपेई, ताइवान
- ञञ. डॉव कैमिकल डॉव हेलास एस ए लेवरियोन साइट टॉरिकोन लेवरियोन टीके 19500, ग्रीस
- टट. सॉल्वे फ्लूओर जीएमबीएच ब्रुनिंगस्ट्रास 50 जिप कोड-डी-65926, फ्रेंकफर्ट एम मेन जर्मनी
- ठठ. बेयर एजी बेयर मेटिरियल्स साइंस, एजी कम्यूनिकेशंस, बिल्डिंग के-12, कासर-विल्हेम-एल्ली-51368, लिवर कसेन जर्मनी
- डड. बीएएसएफ एजी जेडओआई-डी-100 डी-67056, लुडविग्सहेफेन, जर्मनी एनीकेम एसपीए पियाजेल मैटे 100144, रोम, इटली
- ढढ. कतर विनायल कं., क्यूएससी, पो.बॉ. सं. 24440, दोहा, कतर
- णण. हन्डुआ कैमिकल कॉर्पो. 100-797, हन्डुआ बिल्डिंग, 1, जुंग-कु, सिओल, कोरिया गण.

- तत. डीसी कैमिकल्स लि., ओरिएण्टल कैमिकल बिल्डिंग, 50, सोगोंग-डॉंग जुंग-गु सिओल, कोरिया गण.
- थथ. शंघाई क्लोर अल्कली कैमिकल्स वू रोड, सं. 4747, शंघाई सिटी-200122, चीन जन. गण.
- दद. सिनोपैक किली पेट्रोकेमिकल कं. लि., किलुआफिस बिल्डिंग, हाइटेक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन, जिबो, शेन्डॉंग, चीन जन. गण.
- धध. वुहान गोल्डन फॉर्च्यून टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड कं. लि., इंटरनेशनल इंटरप्राइज सेंटर, सं. 2#, गुआनशान रोड, वुहान, हुबई, चीन
- नन. तियान्जिन केयि कैमिकल फैक्टरी, सं. ई-7-205, विन्हाई फाइनेंस जोन, सं. 20, गुआंगचांग ईस्ट रोड, टेडा-तियान्जिन, चीन
- पप. तियान्जिन जेबियर इंटरनेशनल कं. लि., 21सी, वायटिंग गुआन, सं. 22, छा अक्सांश मार्ग, हेडोंग जिला तियान्जिन, चीन
- फफ. मै. ट्राइकोन एनर्जी लिमिटेड, 777 पोस्ट ओआक बिल्डिंग, सूइट 650 हाउस्टन, टेक्सास, 77056, यू एस ए
- बब. मै. बेसिक कैमिकल सोल्युशन फॉर ईस्ट पीटीई लि. 51, गांधी प्लाजा, # 21-08/09, सिंगापुर-308900
- भभ. मै. विनयथाई पब्लिक कं. लि., 14वां तल, यीन टावर, 3656/41 रामा IV रोड, कलोनजेटोनी, बैंकॉक 10110, थाईलैंड

निर्यातक राष्ट्र

- क. यूरोपीय संघ
ख. जर्मनी
ग. ग्रीस
घ. इंडोनेशिया
ङ. चीन जन. गण.
च. कतर
छ. कोरिया जन. गण.
ज. सऊदी अरब
झ. ताइवान
ञ. थाइलैंड
ट. अमेरिका

3. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों/आयातकों तथा निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भी प्रेषित की गयी थीं और उनसे 30 दिन के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. निर्धारित समयावधि के भीतर जाँच समाप्त करने के लिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाए जाने के अनुरोध स्वीकार किए गए और तदनुसार संबंधित पक्षकारों को सूचित किया गया।

5. जाँच शीघ्र पूरी करने के बाद प्रारंभिक जाँच परिणाम 15 अक्टूबर, 2009 को जारी किए गए थे । महानिदेशक (रक्षोपाय) ने घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने हेतु मूल्यानुसार 20% (बीस प्रतिशत) की दर से रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के उपशीर्ष सं. 2815 के अंतर्गत वर्गीकृत कास्टिक सोडा के भारत में आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की थी । प्रारंभिक जाँच परिणामों के आधार पर दिनांक 4.12.2009 की अधिसूचना सं. 131/2009-सी.शु. के तहत 4 दिसंबर, 2009 को 15% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था । प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क, जब तक उसे पूर्व में रद्द, अधिकांश या संशोधित न किया जाए, 3 मार्च, 2010 तक वैध है ।

6. एक सार्वजनिक सुनवाई 8 दिसंबर, 2009 को आयोजित की गई थी, जिसका सूचना 30 अक्टूबर, 2009 को भेजी गई थी । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले समस्त हितबद्ध पक्षकारों से सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी । अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया था ।

7. एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई 28 जनवरी, 2010 को आयोजित की गई थी । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले समस्त हितबद्ध पक्षकारों से सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियम, 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी । अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया था ।

8. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों में या उत्तरों में व्यक्त किए गए समस्त विचारों की जाँच की गई थी और उन पर उचित निर्धारण करने में ध्यान दिया गया है

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों में या उत्तरों में व्यक्त किए गए समस्त विचारों की जाँच की गई थी और उन पर उचित निर्धारण करने में ध्यान दिया गया है । चूंकि अनुरोध करने वाले पक्षकारों की संख्या काफी थी, इसलिए उनके तर्कों तथा उनसे उत्पन्न मुद्दों पर संक्षिप्तता को बनाए रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के विशिष्ट नाम का उल्लेख करके कार्यवाही की गई है ।

10. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों और मौके पर जाकर किया गया था । इसके अलावा, लागत संबंधी

आंकड़ों का सत्यापन और लागत लेखाकार द्वारा उसका प्रमाणन भी किया गया था । सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।

घरेलू उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

आवेदकों के विचार

11. भारतीय उत्पादकों की संयुक्त क्षमता उत्पाद की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है और इन आरोपों में कोई आधार नहीं है कि देश में पर्याप्त उत्पादन के अभाव में आयात आवश्यक बन गए थे । इसके प्रतिकूल आयातों में वर्तमान वृद्धि का एकमात्र कारण काफी कम कीमतें हैं ।

12. इस बात की पुष्टि की गई है कि 11 से अधिक देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण कई देशों से विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

13. अनेक आयातकों तथा निर्यातकों ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है । जिन देशों के विदेशी उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है, उन देशों से हुए आयात का हिस्सा कुल आयातों का मात्र 14% है । वेदांता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है जबकि उन्होंने भारतीय उत्पादकों द्वारा उन्हें सामग्री की आपूर्ति न किए जाने के बारे में आरोप लगाया है जिसकी वजह से उन्हें आयात करने पड़े थे । ये आरोप किसी साक्ष्य के अभाव में निराधार ही हैं ।

14. आयातों में वृद्धि और आयात कीमत में गिरावट इतनी अधिक हुई है कि भारतीय उत्पादक अभूतपूर्व कीमत कटौती करने के लिए बाध्य हुए हैं । इसके अलावा, कास्टिक सोडा के कम कीमत पर हुए आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में भारी गिरावट हो रही है ।

15. घरेलू उत्पादकों के मौके पर एवं संविदा बिक्री के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संवर्धित आयात से घरेलू उद्योग की मौके पर बिक्री प्रभावित हुई है । संविदा बिक्री पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

16. सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित आयात कीमत वह वास्तविक कीमत नहीं है, जिस पर वस्तु का निर्यात किया गया है ।

17. हरीमन कैमसल्ट लि. के अनुसार उत्तरी अमरीका, यूरोप और चीन में भारी बेरी क्षमता है ।

18. आयात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । अप्रैल से सितंबर, 09 के बीच औसत मासिक आयात 51586 मी.ट./माह के हुए हैं ।

19. आयात की संभावित आवक से घरेलू बाजार प्रभावित होगा । उन्होंने हरीमन कैमसन्ट लि. की आवधिक पत्रिका क्लोर-अल्कली से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ।

20. सितंबर,-दिसंबर, 2008 के आस-पास अप्रत्याशित परिस्थितियां रही हैं जिनकी वजह से उत्पाद की वैश्विक मांग में गिरावट आई है । क्लोरीन में मांग में वृद्धि के कारण कास्टिक की मांग बढ़े बिना अमरीका में सी यू की अचानक वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप कास्टिक की कीमतों में गिरावट आई ।

21. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समस्त अनिवार्य विशेषताओं अर्थात् भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, विपणन एवं वितरण तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में आयातित वस्तु के समनुरूप है ।

22. कास्टिक सोडा के भारतीय उत्पादकों के प्रोफाइल का स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :-

	उत्पादन (मी.ट.)	भारतीय उत्पादन में हिस्सा(%)	प्रति कंपनी उत्पादन (मी.ट.)
5 कंपनियां	590627	36	118125
13 कंपनियां	1114397	68	85723
शेष उद्योग	544746	32	24761
कुल उद्योग	1659143	100	47404

23. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 5 कंपनियों का हिस्सा लगभग 36% था । ये वे कंपनियां थीं जिनका अलग-अलग उत्पादन काफी अधिक था और जिनका सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन का 36% बनता था । इसी वजह से याचिकाकर्ता ने उनके बारे में सूचना प्रदान की । तथापि, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने और अधिक कंपनियों के बारे में सूचना चाही और तदनुसार उन शेष कंपनियों के बारे में सूचना प्रदान की गई जिनका अलग-अलग उत्पादन काफी अधिक था । इस प्रकार समस्त कंपनियों का सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन का 68% था । शेष कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनका अलग-अलग उत्पादन काफी कम है ।

24. आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में वृद्धि हुई है । इसके अलावा आयातों में भारत में उत्पादन तथा भारत में खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है । प्रस्तुत समर्थकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कास्टिक सोडा के आयातों में समग्र रूप में वृद्धि प्रदर्शित हुई है और यह वृद्धि तीव्र एवं काफी अधिक है और यह हाल की अवधि में हुई है । वर्ष 08-09 ति.4 तथा 09-10 की ति.1 और ति.2 में बिक्री, उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में वृद्धि हुई ।

25. गंभीर क्षति की मौजूदगी या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण के संगत कारक हैं - आयात वृद्धि की दर, संवर्धित आयातों द्वारा लिया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार। प्रस्तुत तिमाही आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से और भारत में मांग में तेजी से गिरावट आई और परिणामतः भारत में मांग में आयातों के बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई जिसमें क्षमता उपयोग भी घट गया है। इन सभी कारकों से घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति का पता चलता है।

26. घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हो रही थी। तथापि, 2008-09 की ति.3 में बिक्री में तेजी से गिरावट आई। यद्यपि, उसके बाद भी उसमें वृद्धि होती रही है, तथापि वे पूर्ववर्ती स्तर से अभी भी काफी कम हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है। यद्यपि उत्पादन में 2008-09 की ति.2 तक वृद्धि होती रही तथापि, यह 08-09 की ति.2 में दर्ज स्तर से काफी कम है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

27. यद्यपि 08-09 की ति.3 में लाभप्रदता में आई गिरावट का कारण मंदी एवं कीमतों तथा लाभप्रदता में आई वैश्विक गिरावट को माना जा सकता है तथापि, लाभप्रदता में उसके बाद इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को चालू वर्ष की ति.2 में वित्तीय घाटा उठाना पड़ा जिसकी वजह संवर्धित आयात है।

28. स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए रोजगार से यह पता चलता है कि रोजगार में गिरावट आई है जबकि क्षमता बढ़ी है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। यद्यपि घरेलू उद्योग लाभप्रदता को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है, तथापि लाभप्रदता में उसके बाद 08-09 की ति.2 में सुधार होने के बाद भारी गिरावट आई है।

29. विदेशी उत्पादकों के पास पर्याप्त बेशी क्षमता है। इस बेशी क्षमता में इस उत्पाद में किए गए भारी निवेश तथा विचाराधीन उत्पाद के पूंजी गहन स्वरूप के कारण गिरावट आने की आशा नहीं है अतः विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि वे संभव सीमा तक उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करें। इसके परिणामस्वरूप अत्यंत कम कीमत पर भारत को उन्होंने भारी मात्रा में निर्यात किया है। यह वास्तविकता कास्टिक सोडा की कीमतों में 1000 अम.डॉ. से लेकर 75 अम.डॉ. प्रति मी.ट. तक की आई गिरावट से स्पष्ट हो जाती है।

30. बिक्री कीमत के साथ उत्पादन लागत की तुलना से यह पता चलता है कि 2007-08 की ति.4 में एक घटना को छोड़कर जब उत्पादन लागत हमेशा बिक्री कीमत से कम रही है, बिक्री कीमत अब घटकर उत्पादन लागत से भी कम हो गई है। इसके अलावा, बिक्री कीमत मंदी की पराकाष्ठा में भी उत्पादन लागत से अधिक रही है परंतु अब मांग में वैश्विक और

घरेलू रूप से वृद्धि हो रही है तथा उद्योग में विश्वव्यापी सुधार हो रहा है । भारतीय उत्पादकों के लिए कास्टिक सोडा की कीमत में गिरावट इतनी अधिक हुई है कि वह उत्पादन लागत के स्तर से भी कम हो गई है ।

31. गंभीर क्षति अन्य कारकों की वजह से नहीं हुई है । उत्पाद पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू है और घरेलू उद्योग को पूर्व में निर्धारित पाटन एवं क्षति की सीमा तक अनुचित पाटन से सुरक्षा प्रदान की गई है । इसके अलावा, खपत की पद्धति में परिवर्तन, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी विकास तथा निर्यात निष्पादन जैसे कारकों आदि से कोई क्षति नहीं हो रही है । इस बात के मद्देनजर एकमात्र तर्कसम्मत निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को क्षति कम कीमत पर हुए संवर्धित आयातों के कारण हुई है । संवर्धित आयातों और परिणामी गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विधिवत स्थापित हुआ है ।

32. जहां तक व्यवहार्य समायोजन योजना के लिए किए गए प्रयासों का संबंध है, घरेलू उद्योग की योजना मरकरी सैलों को मैम्बरेन सैल में परिवर्तित करने की है इसकी वजह से विद्युत की खपत में कमी आएगी, लवण उत्पादकों के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण लवण की कीमत में कमी आएगी, भाड़ा लागत कम होगी, उत्पादकता में सुधार होगा, उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग होगा, क्लोरीन के उपयोग/क्लोरीन के प्रभावी निपटान में वृद्धि होगी, क्षमता का विस्तार होगा आदि । विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के ये आरोप कि समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है, निराधार हैं । कई मामलों में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने यह व्यवस्था दी है कि उपर्युक्त विशेषताओं को शामिल करते हुए कोई समायोजन योजना एक व्यवहार्य योजना है ।

33. 20% का रक्षोपाय शुल्क लगाने पर भी उसका प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् एल्युमिनियम एवं कागज तथा लुग्दी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि प्रदत्त आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कास्टिक सोडा पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद भी सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह दावा कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण प्रयोक्ता उद्योग की स्थिति बिगड़ जाएगी, तथ्यरहित और पूर्णतः अपुष्टिकृत है ।

34. जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कि पाटनरोधी एवं रक्षोपाय, दोनों शुल्कों को उसी क्षति के निवारण हेतु एक साथ दो बार लगाया गया है । अपेक्षा यह की जाती है कि इन दोनों शुल्कों को इस ढंग से लागू/प्रचालित किया जाए जिससे राहत दो बार प्रदान न की जा सके । यह सिद्धांत महानिदेशक (रक्षोपाय) ने कई अन्य मामलों में पहले ही लागू किया है ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवेदकों के उत्तर

35. देश आत्मनिर्भर है - भारतीय उत्पादकों की संयुक्त क्षमता देश में उत्पाद की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है ।

36. पाटन पहले से ही किया जा रहा है - घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति इस पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हुई है क्योंकि वह बेंचमार्क से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है और कई नए स्रोतों से आयात होने की सूचना मिल रही है। अनेक आयातकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली का कोई उत्तर बाजार नहीं दिया है। जिन्होंने उत्तर दायर किया है उनका हिस्सा कुल आयातों का मात्र 14% बनता है। आयात में वृद्धि और आयात कीमत में गिरावट के कारण भारतीय उत्पादक कीमत में अभूतपूर्व कमी करने के लिए बाध्य हुए हैं। कास्टिक सोडा के कम कीमत पर हुए आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है।

37. मौके पर बिक्री एवं संविदा बिक्री तुलना: संवर्धित आयातों की खपत वस्तुतः उन ग्राहकों द्वारा की जा रही है जो कास्टिक सोडा की खरीद मौके पर कर रहे हैं। अब तक संवर्धित आयातों के कारण संविदा बिक्री के संबंध में कीमत में अत्यधिक क्षति नहीं हो रही है। उस समय संवर्धित आयातों का प्रभाव मौके पर बिक्री के बाजार में अधिक देखा गया था। मौके पर बिक्री बाजार में आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है।

38. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि प्रमुख वैश्विक बाजारों, जिनमें अमरीका, एशिया और यूरोप शामिल हैं और ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, कास्टिक सोडा की कीमतों में अचानक और तेजी से गिरावट आई है।

39. विभिन्न देशों से जिस कीमत पर सामग्री का निर्यात किया जा रहा है और जिस कीमत पर भारत में सीमाशुल्क निकासी हेतु सामग्री की सूचना दी जा रही है, उन दोनों कीमतों के बीच भारी अंतर को किसी संबद्ध व्यय तथा लाभ द्वारा पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है।

40. भारत में आयात की मात्रा न केवल हाल की अवधि में आयातों के संबंध में अपितु, पूर्ववर्ती स्तर के संबंध में भी अभूतपूर्व है।

41. अगस्त और सितंबर, 2009 के महीनों के लिए हरीमन कैमसल्ट की रिपोर्टों में सूचित भारत में कास्टिक सोडा के प्रत्याशित/संभावित आयात उन आयातों की तुलना में अधिक रहे हैं जिनकी सूचना पहले दी जा चुकी है। इसके अलावा, अधिकांश पोतलदान अमरीका से हुए थे।

42. अप्रत्याशित परिस्थितियां

43. अक्टूबर 2008 : क्षमता में वृद्धि, कम निर्यात जिसकी वजह से कास्टिक सोडा की मांग में वृद्धि हुई, अमरीका के बाद चीन से बेशी मालसूची, कीमतों पर वृद्धि का दबाव, संयंत्र रख रखाव, उत्पादन में गिरावट और यू.के. में मालसूचियां, क्लोरीन की कम मांग देखी गई।

44. नवंबर 2008 : कास्टिक सोडा की सपाट मांग, बिनायल, लुग्दी एवं कागज तथा पी वी सी क्षेत्र की ओर से कम उठाव, एशियाई आयातों के कारण अधिक आपूर्त तटीय बाजार,

यू.के. में भी क्लोरीन की मांग में गिरावट देखी गई, क्लोर-अल्कली संयंत्रों में उत्पादन में कटौती, उत्तरी अमरीका में भी घरेलू बाजार में कम मांग की वजह से पी वी सी निर्यातों में वृद्धि देखी गई ।

45. फरवरी, 2009 : अमरीका में कास्टिक उत्पादन रिकॉर्ड सबसे कम स्तर पर पहुंच गया । कीमत में गिरावट से पूर्व अपनी उच्च कीमत वाली मालसूचियों की ओर बढ़ने के उत्सुक कीमत टैंक मालिकों पर गिरावट का दबाव, आयातों में वृद्धि और निर्यातों में गिरावट, यू.के. में अनिवार्य घटनाओं के कारण कास्टिक की अधिक आपूर्ति देखी गई, कास्टिक सोडा के उत्पादन में सुधार के कारण अमरीका में मालसूचियों में वृद्धि हुई ।

46. मार्च, 2009 : मांग से अधिक कास्टिक सोडा की अधिक आपूर्ति विश्व भर में कास्टिक सोडा के खपत क्षेत्रों से कम उठाव निर्यात बाजार में अमरीकी कास्टिक की अत्यंत कम मांग, एशिया से कम कीमत के ठोस कास्टिक द्वारा उनकी मांग की आपूर्ति ।

47. अप्रैल, 2009: कास्टिक सोडा की मांग में आगे और गिरावट तथा यूरोपीय बाजार में कास्टिक सोडा की अधिक आपूर्ति, यू.के. में कास्टिक की मालसूची में वृद्धि, क्लोरीन की मांग में भारी गिरावट ।

48. मई, 2009 : क्लोरीन की कीमत में घोषित वृद्धि, पूर्वोत्तर में कास्टिक सोडा की मांग में अत्यधिक कमी, कीमत में कमी करने का दबाव, कम उत्पादन के बावजूद कास्टिक सोडा का स्टॉक अब तक के सबसे उच्च स्तर पर रहा, जिससे मांग में अत्यधिक गिरावट आई । यद्यपि मांग कमजोर रही तथा कीमतें दबाव में बनी रहीं, तथापि, पिछले कुछ महीनों में निर्यात कार्यकलाप में वृद्धि हुई है, क्लोरीन के उत्पादन में गिरावट आई है ।

49. जुलाई, 2009 : जुलाई में बाजारी मूल तत्वों में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया; पिछले वर्ष के इसी समय की तुलना में खपत कम रही, यद्यपि, माल सूची उच्च बनी रही, तथापि यू के के उत्पादकों ने निर्यात बाजार में सक्रियता बनाए रखी, विश्व भर के अधिकांश कास्टिक सोडा बाजारों में आपूर्ति मांग से अधिक बनी रही, पश्चिमी तट पर घरेलू कीमतों में भारतीय रूपए की तुलना में 17000- 18000/डीएमटी की मामूली गिरावट आई जिसमें कम कीमत की आयातित सामग्रियों से प्राप्त कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कर एवं डिलीवरी शामिल नहीं है । यह सूचना दी गई है कि अमरीका से 50, 000 एल एम टी के अनेक आयातित पार्सल जुलाई में आ रहे हैं जिनकी कीमत 170-190 डॉलर/डीएमटी सी एफ टी है । ये पार्सल एल्यूमिना और साबुन उत्पादकों तथा सामान्य वितरण के लिए नियत हैं । चीन और मध्य पूर्व से होने वाले आयात वस्तुतः गायब रहे ।

50. वर्तमान मामले में आवेदन अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा भारतीय उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है । गंभीर क्षति से संबंधित सूचना डी एस सी एल, झगादिया; डी सी सी एल, कोटाड़; ग्रासिम इंड लि.; गुजरात अल्कलीज, बड़ोदा; गुजरात अल्कलीज, दहेज द्वारा उपलब्ध कराई गई थी । याचिका दायर

करने के बाद महानिदेशक ने और कंपनियों से सूचना प्रदान करने का निदेश दिया । अतः कनोरिया; इंडियन रेयन; बिहार कास्टिक; डी सी डब्ल्यू; एस आई ई एल; गुजरात फ्लूरो कैमिकल्स लि.; आई पी सी एल तथा पी ए सी एल ने भी अपेक्षित सूचना दायर की । इस प्रकार इन समस्त कंपनियों का सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन का 68% बनता है ।

51. कास्टिक सोडा के आयात में समग्र वृद्धि हुई है जो वर्ष 2008-09 में 1,86,347 से बढ़कर 2009-10 में बढ़कर 309,333 हो गए । आयातों में भारत में बिक्री, उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है ।

52. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है क्योंकि आयात वृद्धि दर काफी अधिक है । भारत में मांग में भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई है और आयातों के हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, रोजगार में तीव्र गिरावट का सामना किया है ।

53. विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमताओं का होना । (स्रोत : सी सी ए ओ एन द्वारा प्रकाशित हरीमन कैमसल्ट लि. तथा क्लोर अल्कली मासिक रिपोर्ट)

54. भारतीय बाजार में कास्टिक सोडा के आयातों से घरेलू उद्योग के लिए कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

55. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई, बिक्री कीमत अब घटकर उत्पादन लागत से भी कम हो गई । इन गिरावटों के कारण को भारत में आयात कीमत में गिरावट और विश्व बाजार में कास्टिक सोडा की कीमत में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है ।

56. यद्यपि, ई सी यू की लागत में मार्च, 2009 के बाद गिरावट आई, तथापि लाभप्रदता में इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ ।

57. लगाई गई पूंजी पर आय में भी गिरावट देखी जा रही है ।

58. कारणात्मक संबंध की पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि संवर्धित आयातों से इतर कारकों के आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । जहां तक बेशी क्षेत्र में नई क्षमताएं शुरू करने का संबंध है, याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय उत्पादक पश्चिम में स्थित संयंत्रों से पूर्व एवं दक्षिण में कास्टिक सोडा की बिक्री कर रहे हैं । कास्टिक सोडा अब रेल एवं समुद्री मार्ग द्वारा भेजा जा रहा है । अतः स्थानीय मुद्दे अब भारतीय उत्पादकों को समूचे देश में कास्टिक सोडा की बिक्री से वंचित नहीं कर रहे हैं ।

59. **समायोजन योजना :** याचिकाकर्ता ने एक व्यवहार्य समायोजन योजना उपलब्ध कराई है जो उत्पादन लागत, मौजूदा उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग, बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु क्षमता विस्तार, क्लोरीन के प्रभावित निपटान पर केंद्रित है ।

प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बिन्दुवार उत्तर

60. **पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं किया जा सकता:** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8(ख) और 9 क(1) के विश्लेषण में उस स्थिति में पाटनरोधी शुल्क या रक्षोपाय शुल्क न लगाने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं मिलता है जब दूसरा शुल्क मौजूद हो । फिनोल के मामले में भी रक्षोपाय शुल्क पहले से लागू था और पाटनरोधी शुल्क भी लागू किया गया था ।

61. **याचिका में आरोपित कमिया :** महानिदेशक ने जांच शुरूआत की सूचना में यह पाया कि याचिका विधिवत प्रलेखित थी और जांच की शुरूआत हेतु न्यायोचित थी ।

62. याचिका में आयातों की मात्रा, मूल्य और कीमत के बारे में पर्याप्त सूचना निहित थी ।

63. **एल एम टी तथा डी एम टी:** याचिकाकर्ता ने इस बात पर विचार करने के बाद आयात मात्रा का निर्धारण किया है कि निकासी न किए गए समस्त आयात सौदे संभवतः केवल तरल रूप में आयात की मात्रा से संबंधित हैं और इन्हें डी एम टी में परिवर्तित नहीं किया गया है जबकि संशोधित आंकड़ों से आयातों में भारी वृद्धि का पता चलता है । यह अनुरोध किया गया है कि महानिदेशक को सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए जिसके लिए आवश्यक सत्यापन किया जाना चाहिए । ऐसे सत्यापन भारतीय पक्षकारों तक सीमित होना जरूरी नहीं है और इन्हें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू किया जा सकता है ।

64. **समायोजन योजना से संबंधित सूचना राहत के स्वरूप और मात्रा के निर्धारण हेतु संगत और आवश्यक है ।** इस आशय के निर्णय हेतु यह संगत और जरूरी नहीं है कि क्या रक्षोपाय जांच की जाए या नहीं ।

65. **याचिकाकर्ता ने क्लोरीन के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जिससे भारतीय उद्योग की सही स्थिति का आकलन कठिन हो गया है :**

66. यह विवरण तथ्यतः गलत है । पूर्ण सूचना प्रदान की गई है । किसी भेदभाव के बिना यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित हो तो याचिकाकर्ता उसे प्रदान कर देगा ।

67. **आयात के आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच अपेक्षित है क्योंकि अधिकांश सौदों में आयात के आंकड़ों में उत्पाद का प्रकार वर्गीकृत नहीं है:** याचिकाकर्ता ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना प्रदान की है ।

68. संवर्धित आयातों, बिक्री तथा उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के बारे में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग आंकड़े : महानिदेशक रिकॉर्ड में उपलब्ध विभिन्न सूचना को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उचित सूचना पर विचार कर सकते हैं। महानिदेशक कोई न्याय निर्णयन प्राधिकारी नहीं है। महानिदेशक ने अनेक स्रोतों से सूचना मांगी है और उनकी ओर से अपने खुद के निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित है।

69. क्लोरीन के लिए लागत संबंधी सूचना प्रदान नहीं की गई है : पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है।

70. ई सी यू के संबंध में याचिका में कोई सूचना निहित नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं : इन तर्कों में कोई औचित्याधार नहीं है। यद्यपि यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद ई सी यू आंकड़े प्रदान किए हैं, तथापि यह नहीं माना जाता है कि ये तथ्य और विधिक स्थिति से हटकर हैं। इसके अलावा, मात्र इस तथ्य से उनकी असत्यता की पुष्टि नहीं होती है कि सूचना बाद में प्रदान की गई है।

71. "प्रति ई सी यू प्राप्त राजस्व" पर विचार किया जाना चाहिए। केवल कास्टिक सोडा की कीमत गलत है : घरेलू उद्योग ने वस्तुतः बिक्री कीमत, उत्पादन लागत तथा कास्टिक सोडा के लाभ/हानि एवं ई सी यू उत्पादन, ई सी यू बिक्री प्राप्ति तथा ई सी यू लाभ/हानि लागत के संबंध में सूचना प्रदान की।

72. नियमों में कीमत विचारणीय नहीं है : जहां तक संवर्धित आयातों का संबंध है, कीमत विचारणीय है।

73. सार्वजनिक फाइल में समग्र घरेलू उद्योग के लिए कोई समेकित सत्यापन आंकड़ा नहीं है : ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है।

74. प्राधिकारी ने जांचोत्तर अवधि के आंकड़ों (यथा ई सी यू बिक्री प्राप्ति) के संबंध में चुनिन्दा आंकड़े लिए हैं परंतु घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार दर्शाने वाले हाल के आंकड़ों को अलग रखा है ; यह तर्क निराधार है। वस्तुतः रक्षोपाय मामले में जांच अवधि जैसा कोई मुद्दा नहीं होता है। द्वितीयतः प्राधिकारी ने प्रथम तिमाही के आंकड़ों और तत्पश्चात मासिक आंकड़ों पर विचार किया है। ऐसा विचार जांच परिणाम में सुसंगत है और कानूनन संगत है।

75. अमरीका लैम्ब मामले का संदर्भ : सक्षम प्राधिकारी हाल के आंकड़ों पर अनन्यतः विश्वास नहीं कर सकते परंतु इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि आंकड़े समूची जांच अवधि के संदर्भ में दिए गए हैं।

76. याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि प्राधिकारी को सर्वाधिक ताजा आंकड़ों पर ही विश्वास करना चाहिए। वस्तुतः यदि समूची अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाए तो इससे आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति की पुष्टि हो जाती है।

77. ए एम ए आई के काउंसिल ने यह अनुरोध किया है कि आयात की मात्रा और कीमत से संबंधित आंकड़े गलत हैं : प्रवेश बिल कानूनी दृष्टि से एक स्वीकार्य दस्तावेज है और इस प्रकार इस पर आयात की मात्रा और कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा सकता है। यह सिद्ध करने के लिए प्रवेश बिल का महज प्रस्तुतीकरण अपर्याप्त है कि वस्तु का वस्तुतः आयात इन कीमतों पर किया गया था। आयातक को यह सिद्ध करते हुए कीमत की वास्तविकता सिद्ध करनी चाहिए कि ये कीमतें प्रचलित बाजारी कीमतों से तुलनीय हैं।

78. क्षमता उपयोग में गिरावट क्लोरीन की माल सूची में अत्यधिक बाधा के कारण आई है : घरेलू उद्योग को विगत में क्लोरीन के कम उठाव के कारण उत्पादन कम करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। वस्तुतः आम तौर पर क्लोरीन की कीमत कास्टिक सोडा की कीमत द्वारा नियंत्रित होती है और इनका सामान्यतः आंतरिक संबंध है। तथापि, वर्तमान अवधि में कास्टिक सोडा और क्लोरीन दोनों की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

79. कीमत कटौती गलत आंकड़ों पर आधारित है। विद्युत लागत के सही आंकड़े वर्ष 2008-09 में 4.705 रूपए प्रति कि. वा. घं. है : विद्युत की लागत कीमत कटौती से संबंधित नहीं है। कीमत कटौती घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयात कीमत से संबंधित है जबकि विद्युत लागत उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है।

80. विद्युत पर पंजाब विद्युत बोर्ड द्वारा लगाया गया असामान्य प्रतिबंध क्षमता उपयोग में कमी के लिए जिम्मेवार है : पी ए सी एल, वित्तीय परिणाम सित., 09 : यह तर्क निराधार है। इस अवधि के दौरान ग्रासिम के उत्पादन की तुलना से यह पता चलता है कि ग्रासिम के उत्पादन में परिवर्तन उक्त परिवर्तन की तुलना में काफी अधिक हुआ है जिसकी वजह याचिकाकर्ता द्वारा इंगित आयात हैं।

81. आयातों से इतर कारकों के कारण क्षमता उपयोग कम रहा है। अन्यथा तटवर्ती इकाइयों ने कम क्षमता उपयोग किया होता : यह तर्क तथ्यतः गलत है। डी सी एम श्रीराम में क्षमता प्रभावित हुई है जिसमें क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि इन पक्षकारों के तर्क सही होते तो कास्टिक सोडा की कीमतें उत्तरी भारत में कम नहीं हुई होतीं। कास्टिक सोडा का आयात मुख्यतः तटीय क्षेत्र में किया जाता है तथापि कास्टिक सोडा की कीमत में वृद्धि हुई और आयात तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तनों के कारण उत्तर भारत में भी गिरावट आई।

82. यदि आयातों में वृद्धि क्षति का कारण है तो यह वृद्धि गिरावट से पूर्व होनी चाहिए थी न कि इसक प्रतिकूल : वस्तुतः आयात उक्त गिरावट से पूर्व हुए हैं जैसा कि माहवार मात्रा की प्रवृत्ति से देखा जा सकेगा।

83. नाल्को के पास अत्यधिक लंबित आयात ऑर्डर हैं जिनकी कीमत बैंच मार्क पाटनरोधी दरों से काफी अधिक है, रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से लगभग 4, 768 रुपए पी डी एम टी की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा । इस प्रकार सार्वजनिक हित प्रभावित होगा : उपर्युक्त सूचना से सार्वजनिक हित के अभाव की पुष्टि होती है । इसके विपरीत पिछले वर्षों में एल्युमिनियम उद्योग की आसमान छूती लाभप्रदता से स्पष्टतः एल्युमिनियम उद्योग पर नगण्य प्रतिकूल प्रभाव की पुष्टि होती है । भारतीय उत्पादकों ने नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता की लाभप्रदत स्थिति देखी है ।

84. संवर्धित आयातों की प्रवृत्ति संगत क्षति अवधि की गिरावट की प्रवृत्ति की समसामयिक नहीं है : यह तर्क तथ्यतः गलत है । प्रथमतः संवर्धित आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट एक समान अवधि में आई है । द्वितीयतः प्रति परेषण आयात की मात्रा को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि तत्काल परवर्ती अवधि में आयातों का कुछ प्रभाव देखा जाए ।

85. क्लोरीन में घाटे के कारण कास्टिक में क्षति नहीं हुई है : यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि क्लोरीन एक सह-उत्पाद है और कास्टिक सोडा के प्रचालनों की लाभप्रदता का निर्धारण क्लोरीन के लिए छूट/क्रेडिट के उपरांत किया जाना चाहिए । इसका पालन वर्तमान मामले में भी किया गया है ।

86. लाभ में गिरावट क्षमता उपयोग में कमी के कारण आई है : वस्तुतः इसे हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । तथापि, जैसा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है और जैसा कि महानिदेशक द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों में स्वीकार्य किया गया है, लाभप्रदता में गिरावट मुख्यतः कास्टिक सोडा की बिक्री कीमत में गिरावट के कारण आई है ।

87. वेदान्ता डाक मुद्दा : अपने तर्कों में वेदान्ता ने घरेलू उद्योग को भेजे गए कुछेक ई-मेलों का हवाला दिया है । तथापि, उसने उस कंपनी का नाम नहीं बताया है जिससे पूछताछ की गई है और न ही वेदान्ता ने महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा इस संबंध में जोर देने पर भी कुछेक भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से कंपनी को मिले उत्तरों के बारे में कोई सूचना प्रदान की है ।

88. वेदान्ता द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के मद्देनजर याचिकाकर्ता एसो. ने उन भारतीय उत्पादकों को पत्र लिखा, जिनसे वेदान्ता ने संपर्क किया था । चूंकि वेदान्ता द्वारा संपर्क किए गए भारतीय उत्पादकों की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं है, इसलिए उन भारतीय उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि उनके बारे में याचिकाकर्ता एसो. ने यह अनुमान लगाया था कि उन्हें वेदान्ता से पूछताछ प्राप्त हुई है ।

89. भारतीय उत्पादकों को हुई समस्याएं : आपूर्ति की सहमत तारीख के बावजूद कंपनी ने साख-पत्र खोलने में विलंब किया । ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुष्टिकृत मात्रा का ऑर्डर देने के बावजूद कंपनी ने सामग्री की खरीद में विलंब किया अथवा पुष्टिकृत क्रय आदेश को रद्द कर दिया ।

90. इस प्रकार की बड़ी अपेक्षा के बावजूद वेदान्ता ने घरेलू स्रोतों से कच्ची सामग्री की खरीद हेतु कोई खास प्रयास नहीं किया। इसके प्रतिकूल वेदान्ता का समग्र दृष्टिकोण अत्यंत आकस्मिक प्रतीत होता है जैसा कि कंपनी को स्वयं प्राप्त पूछताछ से पता चलता है।

1. ऑर्डर अंत सूचना पर दिए गए।
2. इस आशय के साक्ष्य हैं कि वेदान्ता द्वारा सस्ते आयातों के बहाने घरेलू उत्पादकों के साथ कीमत के बारे में अत्यधिक मोलभाव किया जा रहा है।
3. इस आशय के साक्ष्य हैं कि लिखित पत्राचार के जरिए प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भी वेदान्ता ने भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए प्रस्तावों का कोई उत्तर नहीं दिया है अथवा निर्णय लेने में देरी की है और वह भी उस बाजार में जो वर्तमान में अस्थिर है।

91. आयात कीमत : कोरियाई सीमाशुल्क के माह वार आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा जाएगा कि मात्राएं समान होने पर भी कीमतों में काफी अधिक अंतर है। याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी है कि एक कीमत एफ ओ बी है और दूसरी सी आई एफ। तथापि, अंतर संबद्ध भाड़े की तुलना में काफी अधिक है।

92. संवर्धित आयात तथा अद्यतित अवधि के लिए आंकड़े : अर्जेन्टीना फुटवियर मामले को देखते हुए यह आवश्यक बन जाता है कि हाल की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए अद्यतित अवधि के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

93. सी आर आई एस आई एल रिपोर्ट: संगत अवधि में कास्टिक सोडा के आयातों में भारी वृद्धि देखी गई थी।

94. आयात कीमत के कारण घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

95. इसी समय उत्पादकों ने उत्पादन सीमित कर दिया है - इस संबंध में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि कास्टिक सोडा (अथवा इस मामले में आम तौर पर किसी अन्य वस्तु) का उत्पादन दो कारणों द्वारा शासित होता है - (i) ग्राहकों से पुष्टिकृत ऑर्डर; तथा ऑर्डर की आशा में उत्पादन (जिसे "माल सूची के लिए उत्पादन" के नाम से भी जाना जाता है)। याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि पुष्टिकृत ऑर्डरों और प्रत्याशित आर्डरों के लिए उत्पादन के अनुपात में अवधिक दर अवधि अंतर होता है। यद्यपि भारतीय उत्पादकों ने पुष्टिकृत ऑर्डरों के मामले में उत्पादन कभी भी अधिक नहीं किया है तथापि कास्टिक सोडा का उत्पादन पुष्टिकृत ऑर्डरों के बिना किया गया जिसका स्वाभावित रूप से नियंत्रण बाजारी स्थितियों पर होता है।

96. प्रकाशित परिणामों से गिरावट का पता नहीं चलता है: याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वर्तमान प्रयोजनार्थ प्रकाशित परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ।

क. प्रकाशित परिणाम खंड विशेष के संबंध में हैं जबकि जांच विचाराधीन उत्पाद के बारे में है ।

ख. कास्टिक सोडा में भी विचाराधीन उत्पाद केवल तरल रूप में है । ठोस रूप में कास्टिक सोडा वर्तमान जांच के दायरे में नहीं आता है ।

97. पांच आरोपित सौदों के आधार पर मूल्य की गलत घोषणा से संबंधित घरेलू उद्योग का आरोप महानिदेशक, रक्षोपाय के समक्ष नहीं लगाया जा सकता, जिनके पास उक्त आरोप की सत्यता निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है: याचिकाकर्ता ने महानिदेशक से इस मामले की जांच करने के लिए नहीं कहा है । याचिकाकर्ता ने महानिदेशक का ध्यान केवल आयातों की सही मात्रा और मूल्य को सिद्ध करने की ओर आकर्षित किया है क्योंकि यह वर्तमान निर्धारण के लिए प्रत्यक्षतः प्रासंगिक है ।

98. वैश्विक रूप से क्लोर-अल्कली व्यापार में काफी पूर्व से 2-3 वर्ष की समय सीमा में पांच चरणीय चक्रीय पद्धति अपनाई जा रही है : वर्तमान स्थिति के प्रतिकूल पूर्व में किए गए अनुरोधों के अनुसार कास्टिक सोडा के आयातों में इतनी अधिक वृद्धि नहीं देखी गई है जितनी कि अब देखी गई है । जहां भारतीय उत्पादकों ने सामान्य बाजारी स्थितियों को देखा है, वहीं भारतीय उत्पादकों की चिंता आयातों में अचानक एवं पर्याप्त वृद्धि के बारे में है, जिसकी वजह से घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

99. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित 13 विनिर्माताओं में से केवल 3 विनिर्माताओं ने यह पुष्टि की है कि उन्हें कोई घाटा हुआ है : गंभीर क्षति के निर्धारण हेतु महानिदेशक के लिए "समग्र घरेलू उद्योग" पर विचार करना अपेक्षित होता है । महानिदेशक के लिए अलग-अलग इकाइयों पर विचार करना अपेक्षित नहीं है । यदि यह स्वीकार किया जाता है कि एक कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो इसका तात्पर्य यह है कि समेकित आंकड़ों में किए गए उल्लेख के अनुसार शेष घरेलू उद्योग ने खराब प्रदर्शन किया है ।

100. अप्रैल, 2008 से जून, 2009 की अवधि के दौरान आयातित कास्टिक सोडा तरल की 130 आयात परेषणों में से प्रतिवादी ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि :

- I. 130 प्रविष्टियों में से लगभग 10% के साथ छेड़-छाड़ की गई है और ये गलत है ।
- II. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना में आयात की मात्रा 22% कम थी ।

III. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना में आयात कीमत 28.80% अधिक है ।

101. याचिकाकर्ता ने अब आई बी आई एस से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, जो संलग्न है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने कोई सूचना नहीं छिपाई है। इससे आगे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि महानिदेशक के समक्ष याचिकाकर्ता पाक साफ है और हितबद्ध पक्षकार अपनी ओर से कोई पर्याप्त प्रयास किए बिना महानिदेशक को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

102. वार्षिक रिपोर्टों के जो आंकड़े अगोपनीय हैं, उन पर गोपनीय रूप में विचार किया गया है: याचिकाकर्ता ने वार्षिक रिपोर्टों के बारे में किसी गोपनीयता का दावा नहीं किया है, वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों ने बार-बार वार्षिक रिपोर्टों का हवाला दिया है।

103. मांग-आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए आयात स्वाभाविक हैं : याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना से यह पता चलता है कि भारतीय उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमता है जिसका उपयोग कम हो रहा है।

104. अवसरवादी लागत एवं लाभ का निर्धारण : क्लोरीन को एक सह उत्पाद तथा उपोत्पाद मानना : यह इस तथ्य की प्राधिकारी को बेहतर जानकारी है कि कास्टिक और क्लोरीन उपोत्पाद हैं। वस्तुतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना से इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि होती है। इसके अलावा, चूंकि कास्टिक सोडा की बिक्री प्राप्ति और ई सी यू प्राप्ति दोनों पर विचार किया गया है, इसलिए इस संबंध में अधिक कुछ नहीं बचा है।

105. आई बी आई एस के आंकड़ों पर भरोसा : आई बी आई एस के आंकड़े भरोसोमंद आंकड़े हैं और इनका उपयोग रक्षोपाय शुल्क की जांचों में विभिन्न घरेलू उद्योगों ने व्यापक रूप से किया है। इन आंकड़ों का उपयोग पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी किया जा रहा है और उन पर विश्वास किया जा रहा है। समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आई बी आई एस के मूल आंकड़ों तथा परिकलित आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है और उन्हें समस्त पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है।

106. 12 बी ओ ई के मामले में सामान्यीकरण की पद्धति के बारे में : यद्यपि, हमने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त तर्क के अनुसार आयात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तथापि हमारा अनुरोध है कि इन आंकड़ों को सांख्यिकी पद्धति के अनुसार सामान्यीकृत किए जाने की जरूरत है क्योंकि इनमें असामान्य विपथन प्रतीत होती है।

107. कास्टिक विनिर्माता अंतिम प्रयोक्ताओं को आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है: प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार लुग्दी एवं कागज उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें बड़ी मात्रा में कास्टिक सोडा की खपत होती है। तथापि, उन्होंने जांच में हिस्सा लेने/विरोध करने का निर्णय नहीं लिया है। यदि कास्टिक सोडा के विनिर्माता इन क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर

आपूर्ति करने में समर्थ नहीं होते तो इस स्थिति में उन्होंने जांच में हिस्सा लिया होता और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विरोध किया जाता। सभी अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति है जो कास्टिक सोडा के उपयोक्ताओं का 80% बनता है।

108. अधिकांश एल्युमिनियम फैक्टरियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। हिन्डाल्को घरेलू अधिप्राप्ति से कास्टिक सोडा की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। नाल्को भी घरेलू अधिप्राप्ति द्वारा ही अपनी लगभग पूरी आवश्यकता की पूर्ति करता है। वेदांत का दावा है कि वह अपनी लगभग पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति आयातों के द्वारा करता है (यह उल्लेख करना तर्क संगत होगा कि बाल्को और माल्को केवल घरेलू स्रोतों से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे)। कास्टिक सोडा की अधिप्राप्ति की ये पद्धतियां पिछले कुछ दशकों से यथावत बनी हुई हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई थी तो घरेलू उपभोक्ताओं ने आयातों का सहारा लिया था जिसके परिणामस्वरूप बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता के बाद भी बिक्री एवं उत्पादन में कमी आई थी। अतः यह तर्क कि घरेलू उद्योग आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है सही नहीं है।

मिश्र अरब गणराज्य की टिप्पणियां

109. उत्पाद के मिश्री आयातों का हिस्सा नगण्य है। मिश्र के आयात लागू किए जाने वाले किसी रक्षोपाय के दायरे में नहीं आएंगे।

यूरोपीय संघ की टिप्पणियां

110. जांच शुरू नहीं की जानी थी क्योंकि रक्षोपाय हर मूल के आयातों को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे पाटनरोधी और सब्सिडी रोधी उपायों के विपरीत उचित आयातों को लक्षित करते हैं; तथा उपाय लागू करने हेतु डब्ल्यू टी ओ के अपेक्षित मानक अत्यंत उच्च होते हैं। यह जांच गंभीर क्षति के किसी पर्याप्त साक्ष्य के बिना शुरू की गई थी और बढ़ते हुए आयातों के साथ कोई भी कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सका था।

111. प्रारंभिक जांच परिणाम किसी वास्तविक साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।

112. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 4 तथा भारतीय कानून में रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का तात्पर्य समग्र रूप से उन उत्पादकों से है जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है जबकि शिकायतकर्ता उद्योग का हिस्सा घरेलू उत्पादन में केवल 35% है।

113. आयोग ने अनुरोध किया था कि जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा यह विश्लेषण केवल शिकायतकर्ता की स्थिति अथवा समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों की स्थिति के आधार पर किया जाए।

114. भारतीय जांचकर्ता प्राधिकारी आयातों और क्षति संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण तिमाही आधार पर "उस सम विशेष पर विद्यमान किसी अंतर, यदि कोई हो, के प्रभाव को समाप्त करने" के लिए करते हैं। तथापि, वर्षों के आधार पर किए गए विश्लेषण को तिमाही के आधार पर किए गए विश्लेषण से प्रतिस्थापित करने के जांचकर्ता अधिकारी के निर्णय के संबंध में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

115. कोई गंभीर क्षति मौजूद नहीं है क्योंकि बढ़ते हुए आयातों द्वारा घरेलू बाजार का जो हिस्सा ले लिया गया था वह बमुश्किल 1% से अधिक था अर्थात् वर्ष 2005-06 में 61.98% से वर्ष 2008-09 में 60.79%।

116. वर्ष 2009-10 की तिमाही हेतु आयातों की 14,574 रुपए/डीएमटी की कीमत पूर्ववर्ती वर्ष की औसत के अनुरूप है।

117. घरेलू उत्पादकों तथा 13 चुनिन्दा घरेलू उत्पादकों दोनों के लिए जनवरी तथा जून, 2009 के बीच बिक्री और उत्पादन में वृद्धि हुई थी।

118. जांच अवधि के अंत में भी क्षमता उपयोग अत्यधिक उच्च बना हुआ है।

119. वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2007-08 में वार्षिक आधार पर विचार किये गये औसत लाभ में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

120. जनवरी-जून, 08 की अवधि में कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादकता स्थिर बनी रही तथा उत्पादकता में मामूली वृद्धि हुई।

121. कारणात्मक संबंध का कोई विश्लेषण नहीं हुआ है। भारतीय उत्पादकों का घरेलू हिस्सा समग्र रूप से अब भी 90% से अधिक बना हुआ है और यह प्रदर्शित करना कठिन होगा कि बाजार हिस्से में केवल 10% का हिस्सा रखने वाले आयातों से किस प्रकार गंभीर क्षति हो सकती है।

122. आयातों से इतर कारकों जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि का भी घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है परंतु उसके प्रभाव का सावधानीपूर्ण विश्लेषण नहीं किया गया है।

123. आवेदकों के अतिरिक्त संबंधित पक्षकारों के हितों की भी डब्ल्यू टी ओ नियमों के अनुसार जांच की जानी चाहिए।

124. अनंतिम उपाय लागू करने की शर्तें अत्यंत कठोर हैं तथा इसके लिए अत्यंत संवेदनशील स्थितियां मौजूद होना अपेक्षित है, जिनका विधिवत औचित्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

125. विभिन्न ई यू देशों से किए जाने वाले आयात पहले ही पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन हैं और किसी "दोहरे उपचार" को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

इंडोनेशिया की टिप्पणियां

126. पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है अतः रक्षोपाय लागू करना अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैये का प्रतीक है ।

127. कुल खपत में भारतीय घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पहले ही 90-93% है । अतः आयातों को एक मामूली बाधा माना जाना चाहिए ।

128. कोई अप्रत्याशित रुख नहीं देखा गया है क्योंकि आयातों में वृद्धि आयात शुल्क में कमी के कारण हुई है । (वर्ष 2004-05 में 20% से वर्ष 2008-10 में 7.5%)

129. कोई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा मौजूद नहीं है क्योंकि क्षति का निर्धारण डी जी एस जी द्वारा आंकड़ों के चुनिंदा विश्लेषण के आधार पर किया गया है । वर्ष 2008-09 की पहली तथा दूसरी तिमाही में पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि हुई और वह शेष वर्ष के लिए स्थिर बनी रही ।

130. वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान क्षमता में मांग की तुलना में वृद्धि हुई ।

131. वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग तथा 13 उत्पादकों, दोनों की घरेलू बिक्री में लगातार वृद्धि होती रही है ।

132. इंडोनेशिया से आयात 3% से कम है और इसलिए इसे रक्षोपाय से अलग रखा जाना चाहिए ।

कोरिया गणराज्य की टिप्पणियां

133. आयातों में हुई वृद्धि आकस्मिक नहीं है बल्कि एक सतत रुझान का परिणाम है ।

134. अप्रैल, 2008 से जारी वी कर्व हेतु मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है ।

135. क्षमता उपयोग में गिरावट, हाल में हुआ कोई परिवर्तन नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति है जो वर्ष 2005 से जारी है ।

136. रोजगार को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।

137. क्षमता तथा मांग के बीच संबंध में तार्किक साक्ष्य का अभाव है ।

मैक्सिको की टिप्पणियां

138. किसी भी संबंधित अवधि में मैक्सिको के आयात कुल आयातों के 0.1% से भी कम रहे हैं ।

139. उन विकासशील देशों से, जो डब्ल्यू टी ओ के सदस्य हैं, संयुक्त रूप से किए गए आयातों का हिस्सा विश्लेषित प्रत्येक पांचों अवधियों तथा समग्र रूप से उस पूरी अवधि में कुल आयातों के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

ताईवान की टिप्पणियां

140. ताईवान को विकासशील देश माना जाता है और ताईवान के निर्यातों को जांच अवधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ताईवान से निर्यात का हिस्सा मामूली है ।

141. अन्य देशों से किए जाने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है ।

142. ताईवान से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने हेतु कोई पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है ।

थाईलैंड की टिप्पणियां

143. जांच प्रारंभ करने की सूचना के पश्चात की किसी अवधि से संबंधित किसी आंकड़े पर विचार नहीं किया जा सकता है और अतः जांच अवधि केवल जून, 2009 तक ही निर्धारित की जा सकती है ।

144. कोई क्षति मौजूद नहीं है क्योंकि अधिकांश क्षति संकेतकों (उत्पादन, बिक्री, उत्पादन क्षमता) में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और अन्य क्षति कारक (जैसे लाभप्रदता और बाजार हिस्सा) संपूर्ण अवधि में सकारात्मक अथवा स्थिर बने हुए हैं । गंभीर क्षति संबंधी डी जी (एस जी) के जांच परिणाम उपलब्ध आंकड़ों के चयनात्मक विश्लेषण पर आधारित हैं ।

145. कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है क्योंकि क्षति, आयातों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है । चूंकि वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के बीच कुल खपत में आयातों का हिस्सा 10% से कम रहा है ।

146. यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से कास्टिक सोडा के वृद्धिकारी आयातों अथवा विशेष रूप से थाईलैंड से आयातों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है ।

मै. बेसिक केमिकल्स सोल्यूशन्स फार ईस्ट प्रा.लि. तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर लि. तथा अन्य के निवेदन

147. आवेदकों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (धारा 8 ख (6)(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होना चाहिए अर्थात् अन्य बातों के साथ-साथ भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का उनका समग्र उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। वर्तमान याचिका 5 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई है जिनका भारत के संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में समग्र हिस्सा केवल 34% है जिसे किसी भी प्रकार से कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। याचिका दायर करने हेतु प्रारंभिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए डी जी (एस जी) ने स्वतः ही 13 विनिर्माण इकाइयों के आंकड़े एकत्र किए हैं जो कुल घरेलू उत्पादन का 65% बनती हैं। इस प्रकार से कार्य करते हुए डी जी ने घरेलू उद्योग की ओर से कार्रवाई की है और ऐसे कृत्य को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। डी जी को हॉट रोल्ड कॉइलों/शीटों/स्ट्रिप्सों से संबंधित अपने जांच परिणामों के आधार पर इस आवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

148. आवेदक अप्रत्याशित घटनाक्रमों के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप आयातों में कथित वृद्धि का दावा किया गया है कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

149. किसी उद्योग का आत्मनिर्भर होना या न होना, रक्षोपाय की उपयुक्तता का निर्धारण करने के आधार नहीं हैं।

150. भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग तथा आपूर्ति के बीच गंभीर भौगोलिक असंतुलन है। कास्टिक सोडा के प्रमुख उपभोक्ता देश के पूर्वी तट पर अवस्थित हैं जबकि आपूर्तिकर्ता पश्चिमी तट पर प्रचालन करते हैं। निम्न तालिका में क्षेत्रवार उत्पादन क्षमता का विवरण प्रस्तुत है -

क्षेत्र	कुल क्षमता (टीपीडी)	क्षमता वितरण(%)	संयंत्रों की सं.	क्षमता का रेंज (टीपीडी)
पूर्व	1147	13	8	40-365
पश्चिम	4615	52	16	40-800
उत्तर	1171	13	4	235-335
दक्षिण	1943	22	9	110-375

151. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि देश के पूर्वी तट पर संस्थापित क्षमता चार क्षेत्रों में सबसे कम है। यद्यपि प्रमुख एल्यूमिनियम खनन फर्मों के वहां प्रचालनरत होने के कारण मांग वहां सबसे अधिक है। अतः समग्र भारतीय क्षमता के उच्च होने के बावजूद घरेलू उद्योग

पूर्वी तट पर स्थित कास्टिक सोडा के प्रमुख उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पूरा करने में असमर्थ हैं ।

152. वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि वृद्धिकारी आयातों से इतर कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 92% पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन था । अतः पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन आयातों की मात्रा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कथित क्षति का मूल कारण वस्तुओं का पाटन है न कि बढ़ते हुए आयात ।

153. एक ही उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क एक साथ लगाने का कोई आर्थिक तर्काधार नहीं है । दोनों ही मामलों में घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति का खतरा मौजूद होना चाहिए । इसके अलावा, दोनों की मामलों में जांचकर्ता प्राधिकारी को क्षति संबंधी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लगभग समान आर्थिक मानदंडों पर विचार करना पड़ा है । वर्तमान मामलों में डी जी ए डी द्वारा लागू पाटनरोधी उपायों से पाटित आयातों द्वारा पहुंची क्षति को पहले ही समाप्त किया जा चुका है । मौजूदा पाटनरोधी उपायों के अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि दोनों शुल्क लगाए जाते हैं तो यह एक ही क्षति के लिए आवेदकों को आवश्यकता से अधिक सुरक्षा प्रदान करने जैसा होगा ।

154. याचिका में आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां हैं । आयातित वस्तुओं की मात्रा को एल एम टी इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए आवेदकों ने किसी स्पष्टीकरण के बिना अपनी इच्छानुसार परिवर्तन हेतु कारकों का चयन किया है ।

155. दिनांक 15 अक्टूबर, 09 की प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना रक्षोपाय नियमों के नियम 8 और 9 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है ।

156. डी जी सी आई एस द्वारा रखे गए आंकड़ों के आधार पर, आयातों में किसी प्रकार की उल्लेखनीय और अत्यंत वृद्धि नहीं हुई है । बाजार हिस्से में बढ़े हुए आयातों के हिस्से के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि समग्र घरेलू उद्योग ने (संपूर्ण भारतीय उत्पादन पर विचार करते हुए) वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में बाजार हिस्से का केवल 2% गंवाया है । बाजार हिस्से में केवल 2% के बाजार हिस्से की हानि को धारा 8 ख (6)(ग) के साथ पठित करार के अनुच्छेद 4.1 (क) के अर्थों के भीतर गंभीर क्षति नहीं माना जा सकता है ।

157. 13 चयनित इकाइयों तथा संपूर्ण घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्रियों में वर्ष 2006-07 के स्तर की तुलना में वर्ष 2008-09 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है । यह वृद्धि 14% तक दर्ज की गई है । प्रारंभिक जांच परिणाम की तालिका 24 के अनुसार संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2006-07 की तुलना में समान अवधि में अर्थात् 2008-09 में केवल 2% की वृद्धि हुई है । अतः यद्यपि मांग में केवल 2% की वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग के बिक्री स्तर में 14% की वृद्धि हुई है, अतः क्षति के मौजूद होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

158. चुनी गई 13 इकाइयों के उत्पादन में वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 19% की वृद्धि हुई है ।

159. क्षमता उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । घरेलू उद्योग (13 इकाइयाँ) ने वर्ष 2006-07 के स्तर की तुलना में वर्ष 2008-09 में अपनी क्षमता को 21% तक बढ़ाया है जबकि उसी अवधि के दौरान मांग में केवल 13% की वृद्धि हुई है ।

160. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कास्टिक सोडा उद्योग आवर्ती प्रकृति का है । अतः वित्त वर्ष 09-10 की प्रथम तिमाही में लाभ में गिरावट से उद्योग की लाभप्रदता की प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । पूर्व में भी उद्योग को लाभ में अत्यधिक गिरावट का सामना करना पड़ा है जब आयातों में कोई कथित वृद्धि नहीं हुई थी ।

161. रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्योंकि यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 में कर्मचारियों की संख्या में 2135 से बढ़कर वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही में 2166 हो गई है । अतः इस आधार पर भी कोई क्षति नहीं हुई है ।

162. संबंधित उत्पाद के बढ़ते हुए आयात तथा गंभीर क्षति अथवा क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है ।

163. अन्य देशों में बेशी निर्यात क्षमताओं से संबंधित दावे पूर्ण रूप से साक्ष्य रहित हैं । अगस्त, 2008 के बाद उत्तरी अमरीका, यूरोप तथा चीन में बेशी क्षमता में वृद्धि के साथ बाद के महीनों में आयातों में अत्यधिक गिरावट देखी गई है । वास्तव में आयातों की मात्रा नवंबर-दिसंबर, 2008 में शून्य स्तर पर पहुंच गई थी । अतः बेशी क्षमता में वृद्धि के बावजूद भी संबंधित उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है ।

164. इलेक्ट्रो-कैमिकल इकाई प्राप्त (ई सी यू प्राप्ति) में वृद्धि हुई है । क्लोरीन की कीमतों में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । वास्तव में जुलाई, 2009 में क्लोरीन की कीमतें अक्टूबर, 2008 के कीमत स्तर से अधिक थीं । ई सी यू प्राप्ति के आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

165. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना और कुछ नहीं केवल अतिशयोक्ति युक्त विवरण हैं जिसमें इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है कि यह समायोजन किस प्रकार किया जाएगा । चूंकि 95% इकाइयाँ पहले ही मेम्ब्रेन सेल प्रक्रिया पर कार्य कर रही हैं अतः उत्पादन लागत और विद्युत खपत में और कमी करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन सेल प्रौद्योगिकी में न्यूनतम बिजली खर्च होती है ।

166. यह मानते हुए कि आयातों की कीमत कम है जिससे कीमत कटौती हो रही है, पाटनरोधी कानून आयातों की बढ़ती मात्रा और परिणामी कीमत प्रभाव दोनों का ही निपटान

करता है । इसी कारणवश विश्व भर के, विशेष रूप से यू एस ए, कनाडा, जमैका इत्यादि के जांच अधिकारी दोनों उपायों को एक साथ लागू करने के पक्ष में नहीं हैं । यदि रक्षोपाय शुल्क लागू करने का प्रस्ताव किया जाता है तो यूरोपीय आयोग की पद्धति, मौजूदा पाटनरोधी अथवा सब्सिडी रोधी उपाय को निरस्त करने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें रद्द करने की होती है । जमैका का पाटनरोधी तथा सब्सिडी आयोग दोनों शुल्कों के एक साथ लगाए जाने की स्थिति में केवल उसी शुल्क को लागू करता है जो उन दोनों में उच्च हो ।

167. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि यदि कास्टिक सोडा के आयातों पर केवल 20% रक्षोपाय शुल्क भी लगाया जाता है तो इन क्षेत्रों के अंतिम उत्पादों की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एल्यूमीनियम तथा कागज एवं लुग्दी उद्योग के सारणीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । दिलचस्प यह है कि एक बार फिर घरेलू उद्योग ने इन सारणियों के मनमाने आंकड़े हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि घरेलू उद्योग ने साबुन उद्योग की कीमतों पर प्रभाव को सुविधापूर्वक नजरअंदाज कर दिया है ।

168. यदि कास्टिक सोडा पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह संबंधित उत्पाद के आयातकों और प्रयोक्ताओं पर दोहरे अर्थदण्ड लगाए जाने के बराबर होगा । इससे आम जनता के लिए कास्टिक सोडा आधारित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी । कास्टिक सोडा का उपयोग रसायन, पेपर, साबुन तथा धातु उद्योग में किया जाता है । आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु इन उद्योगों को लाभकारी कीमतों पर कास्टिक सोडा की आपूर्ति करना आवश्यक होता है । अतः रक्षोपाय शुल्क लागू करना पुनः सार्वजनिक हित के विपरीत होगा ।

मै. ट्राईकॉन एनर्जी लि., यू एस ए; हन्वा केमिकल कार्पोरेशन कोरिया जन.गण., फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन ताईवान तथा अन्यो के निवेदन

169. आवेदक व्यापार उपचार उपायों के अभ्यस्त प्रयोक्ता हैं । 11 देशों से कास्टिक सोडा के आयात पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगाया जा चुका है । अतः रक्षोपाय लागू करने की आवश्यकता नहीं है । यदि आवश्यक हो तो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क उपायोग की समीक्षा की जा सकती है ।

170. समग्र आयातों में चीन और इंडोनेशिया का हिस्सा 60% है । आवेदक रक्षोपाय के बजाए केवल इन दो देशों से पाटनरोधी शुल्क के संशोधन हेतु डी जी ए डी को आवेदन कर सकते थे ।

171. भारत में कास्टिक तथा क्लोरीन की केवल कुछेक एकीकृत यूनिटें हैं । भारतीय उत्पादकों ने अपने क्लोरीन बिक्री प्रचालनों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिसके अभाव में क्षति का विश्लेषण करना व्यवहारिक नहीं है ।

172. रक्षोपाय महानिदेशक ("महानिदेशक") द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क संस्तुत किए जाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि आवेदकों को कोई क्षति नहीं हुई है और अनंतिम शुल्क के अधिरेपण का औचित्य सिद्ध करने हेतु कोई महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं हैं।

173. कास्टिक सोडा की मांग 4.9% की सीएजीआर से वर्ष 2007-08 में 2.27 मी.टन से बढ़कर 2012-13 में 2.90 मी.ट. हो जाने की संभावना है। कास्टिक सोडा क्षमता केवल 3.9% की सी ए जी आर से वर्ष 2007-08 में 2.74 मी.ट. से बढ़कर 2012-13 में 3.317 मी.ट. हो जाने की संभावना है। तथापि, कास्टिक सोडा उत्पादन, जो क्लोरीन की मांग के कारण बाधित हुआ है, वर्ष 2007-08 में 2.16 मी.ट. से बढ़कर 2012-13 में 2.75 मी.ट. हो जाने की संभावना है। आपूर्ति और मांग की विषमता को आयातों के जरिए पूरा किए जाने की संभावना है।

174. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा नियम 6 में उल्लिखित जांच को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। नियम 9 में निहित महत्वपूर्ण परिस्थितियों के मामले में जांच को शीघ्रता से पूरा करने में भी महानिदेशक से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि शीघ्रता को "तत्परता पूर्वक दक्षता के साथ कार्यवाही करने" के रूप में परिभाषित किया गया है।

175. महानिदेशक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से बंधे हुए हैं।

176. यह प्रदर्शित करने के लिए कि आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार किया गया, आवेदकों ने आई बी आई एस आंकड़ों के साथ प्रयुक्त विधि का ब्यौरा नहीं दिया है। आवेदकों से उनके द्वारा प्रस्तुत आयात के ब्यौरे विशेष रूप से एल एम टी को डी एम टी में परिवर्तित करने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

177. मात्र 35% के भारतीय उत्पादन वाले आवेदन को इस जांच के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। प्रारंभिक जांच परिणाम अर्थात् अर्जेन्टीना पोल्ट्री मामले में दिया गया संदर्भ पाटनरोधी शुल्क से संबंधित है। रक्षोपाय हेतु साक्ष्य संबंधी मानक अपेक्षाकृत काफी अधिक है।

178. एच आर क्यायल मामले में दिनांक 08-12-2009 के अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक ने स्वयं उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा में समर्थकों की अवधारणा को मान्यता नहीं दी जाती है। तथापि इस मामले में जांच की शुरुआत के उपरांत समर्थकों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अतः यह अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार न रखने वाले तदर्थ समर्थकों को शामिल करने के बजाए महानिदेशक द्वारा घरेलू उद्योग से घरेलू उद्योग के बायरे को पुनः परिभाषित करने का अनुरोध किया जाना चाहिए था।

179. आवेदक एसोसिएशन ने जानबूझकर केवल उन्हीं उद्योगों को शामिल किया है, जिनकी स्थिति से घरेलू उद्योग की क्षति अत्यधिक हो सकती हो ।

180. जांच अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत की अवधि को शामिल करने हेतु अर्जेन्टीना फुटवियरमामले की व्याख्या सही नहीं है । महानिदेशक द्वारा जांच अवधि की तुलना में हाल की अवधि अर्थात् जांच अवधि से ठीक पहले की अवधि में आयातों की प्रवृत्ति की जांच भी की जानी चाहिए, जैसा कि यू एस- स्टील रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया है । महानिदेशक ने स्वयं कार्बन ब्लैक मामले में जांच की शुरुआत के बाद नए साक्ष्य को स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया था । फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलियॉल मामले में भी महानिदेशक, रक्षोपाय की वैचारिक स्थिति यही थी । अतः इस मामले में जांच अवधि को आवेदन में उल्लिखित अवधि से बढ़ाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

181. संबंधित नियमावली के अनुसार वस्तुओं की कीमत रक्षोपाय जांच में कारक नहीं होती। यदि वर्धित आयात को छोड़कर कोई अन्य कारक जैसे कम कीमत गंभीर क्षति का कारण हो तो यह मामला पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक को भिजवाया जाना चाहिए ।

182. वैश्विक मंदी, जिसने पूरे विश्व में सभी उद्योगों को प्रभावित किया था, को रक्षोपाय के प्रयोजनार्थ अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं माना जा सकता । अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में पैनल ने संभावित क्षति पर विचार करते समय टैकिला प्रभाव (लैटिन अमेरिकी आर्थिक मंदी) को दायरे से बाहर रखा था ।

183. घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है क्योंकि इसने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2 (क) में सूचीबद्ध अधिकांश कारकों के संबंध में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है ।

184. निर्यातक देश में बेशी क्षमता की मौजूदगी रक्षोपाय जांच में प्रासंगिक कारक नहीं है ।

185. कुल आयात वर्ष 2008-09 में बाजार का केवल 9% है, अतः इसे घरेलू उद्योग को खतरा नहीं माना जा सकता ।

186. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अधिक बदलाव नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग क्लोरीन की 100% बिक्री कर रहा है और क्लोरीन के उत्पादन के अनुसार कास्टिक सोडा का उत्पादन विनियमित कर रहा है ।

187. वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण क्षमता उपयोग वर्ष 2008-09 में घट गया है, न कि वर्धित आयातों के कारण । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है ।

188. घरेलू उद्योग के लाभ में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है । वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में लाभ कम हैं, परंतु मात्र एक तिमाही के परिणाम से उद्योग की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता ।

189. घरेलू उद्योग को रोजगार तथा उत्पादकता के रूप में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है ।

190. क्षति निर्धारण में विदेशों की अतिरिक्त क्षमता पर विचार करना वैध नहीं है । इसके अलावा, अतिरिक्त क्षमता यू एस, चीन तथा यूरोप के पास है परंतु सभी देशों हेतु एक समान रक्षोपाय उपाय संस्तुत किए गए हैं ।

191. वर्ष 2007-08 में औसत त्रैमासिक निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2009-10 में औसत त्रैमासिक निवल बिक्री प्राप्ति अपेक्षाकृत अधिक है । यह दर्शाता है कि व्यवसाय का चक्रीय स्वरूप वास्तविक कारण है, न कि वर्धित आयात । सितंबर माह के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है ।

192. भारत में क्लोरीन की कीमत कम होने की जांच की जानी चाहिए । इसका कारण क्लोरीन का आबद्ध उपयोग किया जाना प्रतीत होता है । क्लोरीन की कम कीमत के कारण बाजार में बेचे जा रहे कास्टिक सोडा की लागत/कीमत बढ़ाकर बताई जा रही है ।

193. आर ओ सी ई में कमी की प्रवृत्ति कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण है और यह केवल क्लोर-एल्कली क्षेत्र तक सीमित नहीं है ।

194. कीमत, क्षति निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारकों में से मात्र एक कारक है और इसे क्षति विश्लेषण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । इसके लिए उचित प्राधिकारण डी जी ए डी है । जनवरी, 09 के बाद बिक्री में गिरावट का कारण वैश्विक मंदी है न कि वर्धित आयात । इसके अलावा वर्ष 07-09 तथा 06-07 की तुलना में वार्षिक उत्पादन वर्ष 08-09 में सर्वाधिक है ।

195. घरेलू उद्योग का उत्पादन क्लोरीन की मांग तक सीमित है, जो अंतिम प्रयोक्ता हेतु पर्याप्त नहीं है ।

196. घरेलू उद्योग को क्लोरीन की लागत निर्धारण का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए और कास्टिक सोडा की लागत निर्धारण तथा एन आई पी निर्धारण में इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

197. वर्धित आयातों व गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । क्षति के कारकों की जांच से ज्ञात होता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ तथा लाभप्रदता वर्धित आयातों से प्रभावित नहीं हुई है । घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण निम्नानुसार है :-

198. भारतीय बाजार में क्लोरीन की मांग तथा कीमत कम होना ।

199. नए ए एल संयंत्र की स्थापना स्थगित की गई है, इस प्रकार वर्ष 09-10 में मांग संभावित नहीं थी ।

200. जून माह में पानी की कमी के कारण उत्पादन में कटौती ।

201. क्लोर-एल्कली की मांग चक्रीय स्वरूप की है । चक्र इस समय अनुकूल नहीं है ।

202. प्रयोक्ता भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं जबकि घरेलू उद्योग पश्चिमी तट पर है । परिवहन लागत के कारण प्रयोक्ता आयात की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं ।

203. अनंतिम शुल्क हेतु कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है क्योंकि अधिकांश आर्थिक कारक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं ।

204. आवेदक का मर्क्युरी सेल से मेम्ब्रेन सेल में परिवर्तन का दावा भ्रामक और गलत है, क्योंकि भारत में स्थापित क्षमता के 93% में मेम्ब्रेन सेल है । मालभाड़ा लागत में कमी करना घरेलू उद्योग के हाथों में नहीं है । प्राप्तियों में सुधार का घरेलू उद्योग का दावा भ्रामक है क्योंकि डी जी ए डी से 10 वर्ष तक संरक्षण के बावजूद उन्होंने क्लोरीन की खपत हेतु कुछ नहीं किया है ।

205. आवेदकों ने क्लोरीन के महत्व पर जोर दिया है परंतु जनता के साथ कास्टिक के महत्व को नजरअंदाज कर दिया है । कास्टिक पर रक्षोपाय शुल्क कास्टिक उद्योग में बड़ी संख्या में कार्यरत कामगारों को प्रभावित करेगा ।

206. इसके अलावा, एक ही उत्पाद के संबंध में रक्षोपाय उपाय तथा पाटनरोधी उपाय हेतु आवेदन केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार नहीं है ।

207. क्राइसिल रिपोर्ट (क्राइसिल रिसर्च मई 2009) के अनुसार घरेलू उद्योग में मांग-आपूर्ति विषमता के कारण आयातों में वृद्धि होनी निश्चित है । यह बाजार की मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता का द्योतक है ।

208. आवेदकों ने स्वयं निवेदन किया है कि कास्टिक की कीमत में तेजी से गिरावट आई है, घोषित आयात कीमत वास्तविक नहीं है, संविदा तथा सर्पोट कीमत में अंतर है और पाटन किया जाता रहा है । आरोपों से ज्ञात होता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटन तथा प्रवचन जैसी अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण हुई है । रक्षोपाय नियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि यदि वर्धित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से क्षति हो रही है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण वर्धित आयातों को नहीं माना जा सकता और महानिदेशक द्वारा ऐसे मामलों को डी जी ए डी जैसे संबंधित प्राधिकारण को भिजवाया जाना चाहिए ।

209. लिखित निवेदनों, आवेदनों एवं प्रारंभिक जांच परिणाम में प्रस्तुत विभिन्न आंकड़ों में भिन्नता है ।

210. क्षमता उपयोग में वर्ष 06-07 की पहली तिमाही की तुलना में वर्ष 09-10 की दूसरी तिमाही में 25% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि तथा क्लोरीन अथवा इसके निपटान के विभिन्न साधनों के सीमित उपयोग के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । क्षमता उपयोग में गिरावट का आयातों से कोई संबंध नहीं है ।

211. सुनवाई उपरांत लिखित निवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा दर्शायी गई निवल बिक्री प्राप्ति तर्कहीन है । दिल्ली में दिसंबर, 2009 में बिक्री कीमत बहुत अधिक अर्थात् 25000/- रूपए प्रति टन थी ।

212. समायोजन योजना व्यावहारिक नहीं है और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का औचित्य सिद्ध नहीं करती ।

पी टी सल्विंडो एडियूसाहा एवं अन्य के निवेदन

213. याचिका तथा प्रारंभिक जांच परिणाम की समग्र जांच से ज्ञात होता है कि इनमें अपेक्षित उद्देश्य तथा गेट 1994 के अनुच्छेद XIX तथा डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय करार में यथापेक्षित वर्धित आयात, गंभीर क्षति, गंभीर परिस्थितियों, अप्रत्याशित घटनाक्रम, पुनःसंरचना योजना, कारणात्मकता तथा सार्वजनिक हित संबंधी विषयों, जिसकी पुष्टि डब्ल्यू टी ओ न्यायाधिकार द्वारा अनेक मामलों में की गई है, के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर आधारित संख्यात्मक विस्तृत विश्लेषण का अभाव है । इसके अलावा, इस मामले की शुरुआत तथा प्रारंभिक जांच परिणाम के संबंध में अनेक प्रक्रियागत त्रुटियां थीं ।

214. भारतीय घरेलू उद्योग तथा 13 चयनित कंपनियों के वार्षिकीकृत आंकड़े सभी आर्थिक मानदंडों के संबंध में स्वस्थ कार्य निष्पादन दर्शाते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं ।

215. समग्र घरेलू उद्योग अथवा 13 चयनित कंपनियों को कोई गंभीर क्षति अथवा बिक्री तथा उत्पादन के रूप में कोई उल्लेखनीय समग्र क्षति (त्रैमासिक आंकड़ों के आधार पर भी) नहीं हुई है ।

216. त्रैमासिक आधार पर आंकड़ों का चयनित विश्लेषण अप्रतिनिधिक है । यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को गलत और अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है ।

217. वर्धित आयातों एवं गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है, क्योंकि आयातों में वृद्धि क्षति से संबंधित कारकों में गिरावट के समय नहीं हुई थी ।

218. पाटनरोधी शुल्क लंबे समय से लागू रहने के संबंध में असंबद्ध कारकों का विश्लेषण नहीं किया गया है ।
219. रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।
220. उत्पादकता में सुधार हुआ है ।
221. क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।
222. घरेलू उत्पादकों और 13 चयनित घरेलू उत्पादकों दोनों की संस्थापित क्षमता में 2006-2007 में 2009-2010 तक लगभग 20% - 25% की वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता उपयोग में गिरावट केवल 2-6% है और यह केवल 2008-2009 तथा 2009-10 की पहली तिमाही में आई ।
223. घरेलू उद्योग को लाभ होता रहा है । डी एस सी एस (मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस), जो संबद्ध वस्तु के तीन शीर्षस्थ उत्पादकों में से एक है जिनका घरेलू उत्पादन में संयुक्त रूप से एक तिमाही हिस्सा है, की दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (जो आयातों में वृद्धि की कथित अवधि का भाग दर्शाती है) से भी यह देखा जा सकता है । इससे स्पष्ट है कि ई सी यू कीमतें अक्टूबर, 2008 तक बढ़कर 650 अम.डॉ. तक पहुंच गई थीं । वर्ष 2008 की अंतिम तिमाही में कीमतों में गिरावट आई, परंतु घरेलू मांग में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई । वर्ष 2009 में दिनांक 31.3.2009 को समाप्त पहली तिमाही में कीमतों में फिर उछाल आया । वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी के इस कार्यकलाप का निष्पादन उत्साहजनक रहा ।
224. भारतीय घरेलू उद्योग अपनी वर्चस्वकारी स्थिति के कारण बाजार पर नियंत्रण रखने में सफल रहा ।
225. घरेलू उत्पादकों का बाजार में अभी भी प्रमुख हिस्सा है जो 2006 से 2009 तक 81.71% से 98.63% रहा । वर्ष 2006 से 2009 तक घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 90% से भी अधिक बना रहा (वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तथा 2008-09 की दूसरी तिमाही को छोड़कर) । दरअसल 2008-2009 की तीसरी तिमाही में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा सर्वाधिक अर्थात् 98.63% तक पहुंच गया था ।
226. घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन क्षमता में वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2009-10 तक लगभग 20%-25% की उल्लेखनीय दर से वृद्धि की ।
227. वर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं, जैसा कि घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है ।

228. घरेलू उद्योग की 5 कंपनियां, जिनका कुल घरेलू उत्पादन में योगदान 30% है, आवेदक थीं। याचिका प्रस्तुत करने पर महानिदेशक, रक्षोपाय ने और अधिक कंपनियों की सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके लिए 8 अन्य कंपनियां सहमत थीं। कुल 13 कंपनियां कुल घरेलू उद्योग की 68% थीं। तथापि, जांच शुरूआत के समर्थन में 8 कंपनियों के समर्थन पत्र का कोई प्रमाण नहीं है। केवल यह वक्तव्य कि महानिदेशक, रक्षोपाय के प्रयोग हेतु 8 कंपनियों ने सूचना उपलब्ध कराई है, इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि 8 कंपनियों ने जांच शुरूआत में अपना समर्थन दिया है।

229. जनहित तथा गंभीर परिस्थिति का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया है। महानिदेशक, रक्षोपाय के लिए यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग की 13 कंपनियों के कुल घरेलू उत्पादन में से 30% से अधिक आबद्ध खपत हेतु है जो फ्लैक्स तथा अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए है।

230. घरेलू उद्योग ने सुनवाई उपरांत निवेदन में कम कीमत पर आयातों का मुख्य कारण के रूप में बार-बार उल्लेख किया है, जो सही नहीं है, क्योंकि कम कीमत पर आयातों की समस्या का निवारण पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण द्वारा किया गया है जो अधिकांश निर्यातक देशों पर लागू है।

231. घरेलू उद्योग ने इस समस्या के समाधान हेतु गलत साधन का उपयोग किया है। उनके अनुबंध में शामिल पहुंच कीमत में पाटनरोधी शुल्क, प्रहस्तन प्रभार तथा आयात संबंधी अन्य प्रभारों को शामिल नहीं किया गया है।

232. भारत में कास्टिक सोडा का किया जाता रहा आयात। महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा इस तथ्य का आकलन बढ़ती मांग की तुलना में किया जाना चाहिए और इस तथ्य को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए।

233. संभावित आयात आवक बाजार को प्रभावित करती हैं। माह अगस्त तथा सितंबर, 2009 की संभावित आयात आवक के बारे में महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा तारीख को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि यह जांच अवधि के बाहर है और इसे जांच शुरू किए जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

234. क्लोरीन में घाटे का संबंध कास्टिक सोडा की क्षति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

235. सार्वजनिक फाइल में रखे गए संकलित आंकड़ों में घरेलू बिक्री तथा उत्पादन को कम बताया गया है जैसा कि प्रति कर्मचारी उत्पादन अर्थात् उत्पादकता के आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

236. वर्ष 2009-10 में कास्टिक की मांग बढ़ी है। घरेलू उद्योग के पास बाजार मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार संवर्धित आयातों से ही मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटा गया था। आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है।

वेदांत एल्युमीनियम लिमिटेड (वी ए एल) द्वारा किया गया निवेदन

237. घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण आयात नहीं है, बल्कि भारत में कास्टिक सोडा लाई बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण किए गए हैं।

238. हमने पहले ही यह निवेदन किया है कि एक स्वतंत्र एजेंसी क्राइसिल ने अपनी वार्षिक समीक्षा में यह सूचना दी है कि आयात इस उद्योग में मांग-आपूर्ति में अनुमानित विषमता के कारण होंगे।

239. वेदांत एल्युमीनियम लिमिटेड ने कास्टिक सोडा की आपूर्ति हेतु घरेलू उत्पादकों से संपर्क किया था, परंतु उन्होंने आवश्यकता को पूरा नहीं किया। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने घरेलू विनिर्माताओं के साथ किए गए इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार में से अनेक पत्र संलग्न किए हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता में प्रचालनरत हैं और एक अतिरिक्त मी.टन के विनिर्माण की स्थिति में भी नहीं है।

240. आवेदन में दर्शाई गई तथा जांच शुरुआत और प्रारंभिक जांच परिणामों में स्वीकार की गई क्षमता बढ़ा कर बताई गई है और वह वास्तविक नहीं है।

241. ऑक्सो अल्कोहल्स के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच के मामले में रक्षोपाय बोर्ड ने शुल्क अधिरोपण हेतु डीजीएसजी की सिफारिश को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि घरेलू उद्योग ऑक्सो अल्कोहल की घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

242. कास्टिक सोडा के प्रत्येक 1 मी० टन के उत्पादन के लिए 0.89 मी० टन क्लोरीन का उत्पादन होता है। क्लोरीन की मांग कास्टिक सोडा की मांग के बराबर नहीं है। क्लोरीन की अपेक्षाकृत कम मांग के कारण उत्पादक उत्पादन स्तरों में कमी करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरीन के लिए सुरक्षित भंडारण नहीं है और उसे हवा में विमुक्त नहीं किया जा सकता है।

243. जांच की शुरुआत प्रारंभ से ही अमान्य है। आवेदन प्रस्तुत करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उत्पादन के केवल एक तिहाई हिस्से का उत्पादन करते हैं। रक्षोपाय शुल्क नियम, 1997 के नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदक के लिखित आवेदन के आधार पर जांच की शुरुआत के मामले में कुल उत्पादन के 60 % के संबंध में आंकड़े आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन से प्राप्त होने चाहिए। यथार्थ में लिखित आवेदन में केवल एक तिहाई घरेलू उत्पादकों

के संबंध में आंकड़े दिए गए थे। अतः मामले की शुरुआत त्रुटिपूर्ण और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के दायरे से बाहर है।

244. घरेलू उद्योग की समायोजन योजना ऐसी होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग का आंतरिक मामला हो जिस पर वे नियंत्रण कर सकें। घरेलू उद्योग की समायोजन योजना बाह्य कारकों पर आधारित है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

245. समायोजना योजना का पूर्वोदाहरण। फॉस्फोरस के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु वर्ष 1999 में यूनाइटेड फॉस्फोरस द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जिसके लिए दिनांक 15.9.99 को जांच शुरू की गई थी, के मामले में डीजीएसजी के अंतिम जांच परिणाम का पैरा 21 स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार है:

246. "यूपीआई/एससीआईएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह पाया गया है कि विद्युत लागत घटाने और उच्चतर उत्पादन कौशल प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित सभी उपायों से भी वे तीन वर्ष अर्थात्, वह अवधि जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अनुरोध किया गया है, के बाद भी आयातित पीले फॉस्फोरस की तुलना में लागत मित्ययी नहीं हो पाएंगे।"

247. यदि शुल्क लगाया जाता है तो यह प्रयोक्ता उद्योग के हित में नहीं होगा क्योंकि वे अपने उत्पादन के स्तर को घटाने या रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करके आयातित उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य होंगे।

248. कॉस्टिक की सौदा लागत को अस्वीकार करने या उसके संबंध में प्रश्न करने और आयातकों द्वारा कॉस्टिक सोडा की कीमत बढ़ा कर बताए जाने के आरोप की जांच करने के लिए डीजी रक्षोपाय उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। इसके लिए सही प्राधिकरण डीआरआई अथवा एफइएमए हैं।

249. अल्युमिना उद्योग के विस्तार के कारण उद्योग में कॉस्टिक सोडा लाई की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग अल्युमिना उद्योग की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

भारतीय एल्युमीनियम एसोसिएशन के अभ्यावेदन

250. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की आवश्यकता का निर्धारण करते समय जांच के एक अधिक कठिन मानक (पाटनरोधी जांच की तुलना में) अपनाए जाने की आवश्यकता है। एकमात्र उपचार उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती देना है।

251. रक्षोपाय शुल्क तब तक अनुमत्य नहीं है जब तक कि यूरोपीय संघ (ईयू) के 25 सदस्य देशों तथा 10 अन्य देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का निर्धारण न कर लिया जाए।

252. प्रारंभिक जांच परिणामों में उस पद्धति का कोई उल्लेख नहीं है जिसमें महानिदेशक ने लगभग 35 देशों से कौस्टिक सोडा के आयातों के विरुद्ध विद्यमान पाटनरोधी शुल्क पर विचार किया है, एएआई ने अपने दिनांक 5 अक्टूबर 2009 के पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया है।

253. इसके अतिरिक्त, महानिदेशक यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय पर इन आयातों के प्रतिकूल कीमत के कारण गंभीर कीमत-आधारित क्षति हुई थी जब कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद इन देशों से आयातों का वास्तविक पहुंच मूल्य निवल बिक्री आय से बहुत अधिक था।

254. अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को स्वयं को "घरेलू उद्योग" से संबंधित सूचना तक न कि अन्य भारतीय कंपनियों से संबंधित सूचना तक सीमित रखना चाहिए था।

255. "घरेलू उद्योग" की परिभाषा के संबंध में एएमआई के मत में लगातार परिवर्तन के बावजूद प्रारंभिक जांच परिणामों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.08.09 की जांच शुरूआत अधिसूचना के समय "घरेलू उद्योग" में शामिल छह अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों के आधार पर भी प्राधिकारी गंभीर क्षति के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे।

256. जांच अवधि के बाद तथ्यों का चयनात्मक रूप से आश्रय लेना अनुमत्य नहीं है। जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने जांच अवधि ("पीओआई") जनवरी-जून 2009 ली है। परंतु उन्होंने इसीयू बिक्री आय संबंधी एक ग्राफ में जुलाई, 2009 और अगस्त 2009 की सूचना को चयनात्मक रूप से शामिल किया है।

257. घरेलू उद्योग को वास्तविक "गंभीर क्षति" से "गंभीर क्षति के खतरे" पर आना क्षति संबंधी मामले की दुर्बलता दर्शाता है।

258. इसीयू संकल्पना का चयनात्मक रूप से फैलाव। प्रारंभिक जांच परिणामों में इस वास्तविकता को दर्शाए बिना इस पहलू पर चयनात्मक तरीके से विचार किया गया है कि क्लोरीन तथा कौस्टिक सोडा की कीमतों में प्रतिकूल संबंध हैं। प्रारंभिक जांच परिणाम में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली 13 कंपनियों की वित्त वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्त वर्ष 2009-10 की पहली दो तिमाही के लिए तिमाही रिपोर्टों में इस वास्तविकता को दर्शाया गया है और ये सभी रिपोर्ट "इलेक्ट्रो-केमिकल इकाई" ("ईसीयू") आधार पर कौस्टिक सोडा एवं क्लोरीन सहित क्लोर-एल्क्ली खंड के लिए उत्तम लागू दर्शाती हैं।

259. गैट के अनुच्छेद XIX तथा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार प्राधिकारी को "अप्रत्याशित घटनाक्रम" के संबंध में कोई एएमआई प्रस्तुतीकरण नहीं दिया गया है।

260. याचिका को तत्काल खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एएमआई ने प्राधिकारी को भ्रामक सूचना दी और अशुद्ध एवं गलत आंकड़े प्रस्तुत किए।

261. एएमआई का यह तर्क कि लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है, गलत है तथा जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित 13 विनिर्माताओं में से 12 विनिर्माता इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्याज एवं मूल्यहास पर विचार करने के बाद उनमें से केवल विनिर्माताओं को कोई घाटा हुआ है।

262. एएमआई अभ्यावेदनों पर विचार न किए जाने से प्रारंभिक जांच परिणाम विकृत हो गए हैं।

263. आयातों में आकस्मिक वृद्धि। यह वृद्धि आकस्मिक नहीं है। कास्टिक सोडा के आयातों में वर्ष 2003-04 से वृद्धि हो रही है। कुल उपभोग के प्रतिशत के रूप में भी आयात वर्ष 2003-04 में 4.1 % से बढ़ कर वर्ष 2007-08 में 6.8 % हो गया।

264. घरेलू उद्योग में रोजगार से संबंधित आंकड़े वृद्धिकारी प्रवृत्ति दर्शाते हैं जोकि केवल तभी संभव है जब घरेलू उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई हो।

265. बिक्री की लागत: यह निष्कर्ष कि भारत में ईसीयू की कम प्राप्ति से भारत में कॉस्टिक सोडा उद्योग अव्यवहार्य हो गया है, सही नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में एएमआई द्वारा प्रस्तुत सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है।

266. लगाई गई पूंजी पर कम आय आयातों में किसी वृद्धि के कारण नहीं है। बल्कि यह बढ़े हुए ब्याज तथा मूल्य ह्रास लागत के परिणामस्वरूप है।

267. प्राधिकारी ने यह पता लगाने के बाद भी कि अगस्त 2009 से आयात कीमतों के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आई है, 35 निर्यातक देशों से कॉस्टिक सोडा के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर विचार नहीं किया है।

268. बढ़े हुए आयातों से इतर कारकों से क्षति हो रही है।

269. कॉस्टिक सोडा के आयात और घरेलू उद्योग को कथित खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

270. वर्तमान मामले में कोई अति महत्वपूर्ण परिस्थितियां नहीं हैं।

271. प्राधिकारी ने एएआई के इस अभ्यावेदन को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से एल्युमीनियम उद्योग जोकि भारत में उभरता हुआ उद्योग है, की संभावनाओं को हानि होगी।

272. घरेलू उद्योग की कोई पुनर्गठन योजना नहीं है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से कॉस्टिक सोडा लाई के वास्तविक प्रयोक्ताओं की कीमत पर क्लोर-एल्कली विनिर्माताओं की अकुशलताओं को सब्सिडीकृत करने में सहायता मिलेगी। मर्करी सेल संयंत्रों की क्षमता कुल संस्थापित क्षमता के 9 से भी कम है और यदि ये सभी संयंत्र मेम्ब्रेन सेल प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू कर भी दें तो उसका प्रभाव मामूली होगा।

273. कॉस्टिक सोडा के आयात में वृद्धि किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण नहीं अपितु भारत में क्लोरीन की कम मांग के परिणामस्वरूप कॉस्टिक के कम उत्पादन के कारण है। इस मामले में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं हुआ है जोकि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार रक्षोपाय हेतु अनिवार्य अपेक्षा है।

274. दिनांक 05.10.2009 को उनके द्वारा प्रस्तुत 12 बी/ई की गलत मात्रा की दृष्टि से आयात आंकड़ों की शुद्धता संदिग्ध है। अतः घरेलू उद्योग के आयात आंकड़ों के सत्यापन के बिना दिनांक 15.10.2009 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया जाना अनुचित है और दिनांक 04.12.2009 की अनन्तिम शुल्क अधिसूचना जल्दबाजी में जारी की गई है।

275. डीजीएसजी कार्यालय के दिनांक 31.12.2009 के पत्र से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि एएआई द्वारा आयात आंकड़ों में दर्शायी गई विसंगति सही है अतः अन्य विसंगतियों की भी गहन जांच की जानी चाहिए।

276. ए ए आई ने दिनांक 5-10-2009 के पत्र के जरिए प्रारंभिक जांच परिणामों पर आपत्ति करते हुए 13 में से 12 प्रतिभागी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जो यह दर्शाती हैं कि उन्हें वर्ष 2008-09 में लाभ हुआ था और वर्ष 2009-10 की प्रथम और दूसरी तिमाही में भी वे लाभ की स्थिति में हैं। परंतु अभ्यावेदन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है। अतः कोई जांच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व लाभप्रदता, आरओईसी तथा ईसीयू प्राप्ति के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का समुचित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए।

277. जांच शुरुआत अधिसूचना में यह दर्शाया गया था कि मै. जीएसीएल नुकसान में चल रहा है लेकिन एएआई ने वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें लाभ दर्शाया गया है। अतः यह सही नहीं है।

278. डीआई की कुछेक भागीदार कंपनियों ने स्वयं बढ़े हुए आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों को लाभप्रदता में गिरावट का कारण माना है। उदाहरण के लिए आदित्य बिरला कैमिकल्स, ग्रासिम इंडस्ट्री तथा एसईआईएल कैमिकल कॉम्पलेक्स ने यह सूचित किया है कि

क्लोरीन की मांग में कमी के कारण निष्पादन प्रभावित हुआ है। मै0 पीएसीएल ने बिजली की उपलब्धता में कमी को इसका कारण माना है और ग्रासिम ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में पानी की कमी को इसके लिए जिम्मेदार माना है।

279. वर्ष 2008-09 में 4.705 रु0 प्रति केडब्ल्यूएच के रूप में दर्शाई गई बिजली की औसत लागत सही नहीं है। सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007-08 में बिजली की लागत 3.10 रु0 प्रति केडब्ल्यूएच थी और अक्टूबर 2009 की उनकी रिपोर्ट जिसमें उन्होंने 5 कॉस्टिक कंपनियों का विश्लेषण किया है, के अनुसार आबद्ध बिजली की लागत 2.70 रु0 केडब्ल्यूएच और खरीदी गई बिजली की लागत 3.40 रु0 प्रति केडब्ल्यूएच है।

280. 13 भागीदार कंपनियों में से 9 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिजली की औसत लागत केवल 3.5 रुप0 प्रति केडब्ल्यूएच है।

281. घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आयात के भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति अथवा बिक्री लागत के साथ की जानी चाहिए।

अन्य अनुरोध

282. किसी रक्षोपाय को लागू करने के लिए, आवेदक को संबद्ध वस्तुओं के आयात में आकस्मिक, तेज, हालिया तथा अत्यधिक वृद्धि, अप्रत्याशित घटनाक्रमों, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे की मौजूदगी, और आयातों में वृद्धि तथा गंभीर क्षति या उसके खतरे के बीच बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करना होगा।

283. रक्षोपाय कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आत्मनिर्भरता किसी रक्षोपाय को लागू करने का आधार नहीं मानी जा सकती है।

284. कॉस्टिक सोडा के प्रमुख उपभोक्ता देश के पूर्वी तट पर अवस्थित है जबकि आपूर्तिकर्ता पश्चिमी तट से प्रचालन कर रहे हैं। देश के पूर्वी तट की संस्थापित क्षमता चारों क्षेत्रों में से सबसे कम है जबकि प्रमुख एल्यूमीनियम खनन कंपनियों के प्रचालन के कारण वहां मांग सर्वाधिक है। इसीलिए उच्च कुल भारतीय क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग पूर्वी तट पर अवस्थित कॉस्टिक सोडा के प्रमुख उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पूरा करने में अक्षम है।

285. यहां घरेलू उद्योग का प्रमुख रूप से यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ कीमत रूप में होने के कारण निर्यातक बहुत कम कीमतों पर बिक्री करने में समर्थ हैं जबकि भारतीय आयातक संदर्भ कीमत के स्तर से अधिक कीमत दे रहे हैं। रक्षोपाय विधान के अंतर्गत

पुनः यह ऐसा आधार नहीं है जिसकी महानिदेशक जांच कर सकें। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत समुचित फोरम से संपर्क कर सकता है।

286. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कॉस्टिक सोडा के आयातों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क जारी हैं, महानिदेशक द्वारा रक्षोपाय शुल्क नियमावली के अनुबंध के पैरा 2 के आलोक में मौजूदा जांच में आगे की कार्यवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

287. घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत डब्ल्यूटीओ निर्णय पाटनरोधी मामलों से संबंधित है और रक्षोपाय संबंधी जांच में संगत नहीं है।

288. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु कीमत में गिरावट अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कीमतों में गिरावट का कारण आयातों में आकस्मिक वृद्धि होना चाहिए जो स्वयं अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हुई होती। कोई भी सुरक्षा केवल कीमतों में गिरावट के आधार पर नहीं दी जा सकती।

289. घरेलू उद्योग का दावा है कि संबद्ध वस्तु के कम कीमत पर आयातों में वृद्धि के कारण लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई है। इस दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने कुछ चुनिंदा कंपनियों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हमारा निम्नलिखित विश्लेषण यह सिद्ध करेगा कि ये दावे अनुचित, अप्रमाणिक तथा झूठे हैं। सर्वप्रथम हमें आंकड़ों के विश्लेषण हेतु कुल 13 कंपनियों में से 5 कंपनियों के चयन पर आपत्ति है। याचिकाकर्ता क्षति को दर्शाने के लिए केवल 5 कंपनियों का चयन नहीं कर सकता जबकि कुल 13 कंपनियां घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं।

290. डीआई प्रस्तुत आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि आयातों की मात्रा तथा मूल्य और घरेलू उद्योग के लाभों के बीच कोई संबंध नहीं है।

291. घरेलू उद्योग का दावा है कि संबद्ध वस्तुओं की मौके पर कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है और आयात अधिकांशतः मौके पर कीमत के आधार पर होते हैं। यह दावा गलत और अप्रमाणिक है तथा इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है।

292. घरेलू उद्योग अप्रत्याशित घटनाक्रमों के संबंध में कोई ठोस एवं तर्कसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है जो रक्षोपाय शुल्क हेतु किसी आवेदन के लए पूर्व-अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध के पृष्ठ 19 पर मुख्यतः निम्नलिखित दो बातों को अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में दर्शाया है:

क: सितंबर-दिसंबर 2008 के आस-पास घटित अप्रत्याशित घटनाएं जिनके कारण संबद्ध वस्तु की वैश्विक मांग में कमी आई

ख: क्लोरीन की मांग में आकस्मिक वृद्धि के कारण अमेरिकी बाजार में कॉस्टिक सोडा की अधिकता

293. यह बात कि उपर्युक्त दावे अपर्याप्त हैं, इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि वैश्विक रक्षोपाय के प्रयोजनार्थ केवल अमेरिकी बाजार में अधिकता को "अप्रत्याशित घटनाक्रम" नहीं माना जा सकता है। दूसरा यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित अधिकांश तथ्य उनके अपने दावे के विरुद्ध जाते हैं।

294. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के चयन के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

295. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात के आंकड़े अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हैं।

296. घरेलू उद्योग ने "गंभीर क्षति" के समर्थन में विभिन्न आर्थिक मानदंडों से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। हम यहां यह दोहराते हैं कि अमेरिकी-लैब मामले में अपीलीय निकाय के निर्णयानुसार रक्षोपाय विधान के अंतर्गत क्षति का मानक "अत्याधिक ऊँचा" तथा "कठोर" है।

297. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अपने हिस्से के संबंध में त्रैमासिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए पहली दो तिमाहियों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। हम महानिदेशक से पीओआई को जुलाई 2009 तक सीमित रखने और उसके बाद के सभी आंकड़ों को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

298. वित्त वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के आंकड़ों से पूरे वर्ष की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। वर्ष 2008-09 तक के आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2007-08 की तुलना में घरेलू उद्योग के हिस्से में मात्र 1.87 % की कमी आई है।

299. बाजार हिस्से में 1.87% के मामूली नुकसान को इस करार के अनुच्छेद 4.1 (क) तथा अधिनियम की धारा 8 ख (6) (ग) के अर्थ के भीतर गंभीर क्षति के अत्यधिक उच्च मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

300. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध के पृष्ठ 54 पर सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री के साथ-साथ 13 उत्पादकों की बिक्री की आंकड़े अलग-अलग तालिकाओं में दर्शाए हैं। सर्वप्रथम हम यह उल्लेख करते हैं कि सभी घरेलू उत्पादकों के लिए आंकड़े प्रारंभिक परिणामों के पृष्ठ 30 की तालिका 6 में दर्ज आंकड़ों से अलग हैं। प्रारंभिक परिणाम में वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री में 9% की वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध में प्रस्तुत आंकड़ों से उसी अवधि में बिक्री में 2% की गिरावट प्रदर्शित होती है।

301. बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा अन्य मानदंडों से अच्छी वृद्धि प्रदर्शित होती है।

302. रोजगार के स्तरों में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत वर्ष 2008-09 की तुलना में वित्त वर्ष 2009-10 की पहली दो तिमाहियों में सापेक्ष तथा औसत दोनों रूपों में रोजगार में वृद्धि हुई है।

303. प्रारंभिक परिणाम के पैराग्राफ 136 में महानिदेशक नोट करते हैं कि वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः इस आधार पर भी कोई क्षति नहीं हुई है।

304. घरेलू उद्योग का दावा है कि विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध बेशी क्षमता अत्यधिक चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण आयातों में और अधिक वृद्धि होगी। यह दावा पूर्णतः अप्रामाणिक है क्योंकि बेशी क्षमता तथा आयातों के बीच कोई संबंध नहीं है।

305. घरेलू उद्योग का दावा है कि कम कीमत पर आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है। यह दावा निम्नलिखित कारणों से गलत, अतार्किक और अनुचित है। थाइलैंड तथा मिस्र को छोड़कर सभी देशों से आयात संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं। अतः इस देश में कोई भी आयात डीजीएडी द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर नहीं हुआ है।

306. इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारकों के मूल्यांकन से "गंभीर क्षति" का तो दूर किसी भी क्षति का संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावा बाजार हिस्से में इस मामूली गिरावट को गंभीर क्षति का कारण नहीं माना जा सकता जिसके मानक "अत्याधिक ऊँचे" और कठोर हैं।

307. महानिदेशक द्वारा उन अन्य कारकों की जांच करना आवश्यक है जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है और इस प्रकार हुई क्षति आयातों का परिणाम नहीं मानी जाएगी। यहां हम यह दोहराते हैं कि क्षति, यदि कोई हो, वस्तुओं के पाटन के कारण हुई है और उस स्थिति में समुचित उपाय करने के लिए डीजीएडी समुचित प्राधिकरण है।

308. अन्य कारकों के मुद्दे पर अधिकांश घरेलू उद्योग के समक्ष आई क्लोरीन-मालसूची संबंधी कठिनाइयों का उल्लेख आवश्यक है। वस्तुतः हैरिमेन कैमसल्ट लि० की रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में भी कौस्टिक सोडा की मांग स्थिर रही है।

309. भारत में विशेष रूप से भारत के पश्चिमी तट पर मानसून के दौरान कौस्टिक सोडा का बाजार मंदा रहता है।

310. रक्षोपाय का अधिरोपण लोकहित में नहीं है।

महानिदेशक के जांच परिणाम

311. मामले संबंधी रिकॉर्डों, घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों तथा निर्यातक राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न पार्टियों द्वारा किए गए निवेदनों तथा उनसे उठने वाले मुद्दों पर जांच परिणामों में उचित स्थानों पर निम्नानुसार विचार किया गया है।

कास्टिक सोडा हेतु भारतीय बाजार : एक संक्षिप्त विवरण

312. **उद्योग की प्रकृति** : कास्टिक सोडा का विनिर्माण साधारण नमक के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। कास्टिक सोडा के उत्पादन के साथ-साथ, निर्धारित मात्रा में क्लोरीन का भी उत्पादन होता है। कास्टिक सोडा एवं क्लोरीन दोनों की ही वाणिज्यिक उपयोगिताएँ हैं और उन्हें विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) एक बहुपयोगी क्षार है। इसे मुख्यतः लुग्दी एवं कागज, एल्यूमिना, साबुन एवं प्रक्षालकों, पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण तथा रासायनिक उत्पादन आदि में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों में जल संसाधन, खाद्य, वस्त्र, धातु प्रसंस्करण, खनन, ग्लास विनिर्माण तथा अन्य शामिल हैं। कास्टिक सोडा, रसायनों की एक व्यापक रेंज के विनिर्माण हेतु भी एक आधारभूत फीडस्टॉक है। इसे प्रक्रियाओं में एक मध्यवर्ती तथा अभिकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिससे विलायकों, प्लास्टिकों, कृत्रिम फाइबरों, ब्लीच, आसंजकों, कोटिंग्स, शाकनाशियों, रंजकों, स्याही तथा भेषज आदि का उत्पादन होता है। इसको, अम्लीय अपशिष्ट स्ट्रीमों को निष्प्रभावी बनाने तथा ऑफ-गैसों से अम्लीय संघटकों को हटाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस उद्योगों में इसका प्रयोग हाइड्रोकार्बनों एवं ऑफ गैसों से अम्लीय तत्वों को हटाने के लिए किया जाता है। वस्त्र क्षेत्र में, इसका उपयोग कपास के रासायनिक संसाधन हेतु तथा कृत्रिम फाइबरों को रंगने के लिए किया जाता है। यदि कास्टिक सोडा अधिक मात्रा में मौजूद हो तो पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर इसका भण्डारण किया जा सकता है।

313. क्लोरीन, रसायन उद्योग की एक आवश्यक निविष्टि है। सभी हैलोजनों में से, क्लोरीन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है तथा सबसे सुकर रूप से इसका उत्पादन किया जा सकता है। 85% से अधिक भेषज उद्योग तथा रसायन उद्योग का आधे से अधिक हिस्सा क्लोरीन उद्योग पर निर्भर है। इन उत्पादों का प्रयोग अधिकांश रूप से औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं :

- क. स्वास्थ्य सुरक्षा
- ख. कृषि खाद्य
- ग. भवन निर्माण
- घ. वस्त्र
- ङ. परिवहन
- च. खाली समय में किए जाने वाले कार्यकलाप
- छ. सौंदर्य प्रसाधन

314. क्लोरीन का भण्डारण करना तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, उसकी प्रकृति के कारण कठिन है अतः इसका उपयोग मुख्यतः ऐसे स्थानों में किया जाता है जहाँ इसका उत्पादन विभिन्न अनुप्रवाहगामी इकाइयों जैसे वीसीएम (विनाइल क्लोराइड, मोनोमर, पीवीसी हेतु बिल्डिंग ब्लॉक) तथा प्लास्टिक पीवीसी (पॉलिविनाइल क्लोराइड) में किया जाता है। क्लोरीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य है।

315. चूँकि कास्टिक सोडा के उत्पादन को क्लोरीन के उत्पादन से अलग नहीं किया जा सकता है अतः उद्योग को क्लोर-अल्कली उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा दोनों की माँग, आपूर्ति तथा कीमत संबंधी परिवर्तनों से उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग :

316. कास्टिक सोडा को बड़ी संख्या में उद्योगों में सामान्य उपयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। कास्टिक सोडा उद्योग का विकास बहुत हद तक विनिर्माण क्षेत्र के समग्र विकास पर निर्भर है। विगत में लगभग 7% घरेलू माँग की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती थी। चीन, इंडोनेशिया, यूरोप, थाइलैंड, कतर तथा अमेरिका भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख राष्ट्र हैं। कास्टिक सोडा के निर्यात बाजार में भारत की स्थिति उल्लेखनीय नहीं है। भारतीय उत्पादक अपने उत्पादन के लगभग 1/2% का निर्यात करते रहे हैं।

317. भारत में संस्थापित उत्पादन क्षमता, उत्तरी अमेरिका की संस्थापित क्षमता का 20%, यूरोप का 22% तथा चीन का 12% है। भारत में बाजार के आकार में वृद्धि हो रही है और बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए संस्थापित क्षमता में भी उसी गति से वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में क्षमता एवं उत्पादन में क्रमिक वृद्धि के बावजूद भी, भारतीय कास्टिक सोडा का बाजार, वैश्विक कास्टिक सोडा बाजार के 5% से कम है।

रक्षोपाय जांच की आवश्यकता :

318. भारतीय क्षार विनिर्माता एसोसिएशन (एएमएआई) ने भारत में कास्टिक सोडा के बढ़ते आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के खतरे से कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में कास्टिक सोडा के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि बढ़ते आयात के कारण उनके उद्योग अव्यवहार्य हो गए हैं तथा उद्योग को घाटा हो रहा है। लाभप्रदता एवं बाजार हिस्से में घाटे से अपूरणीय क्षति हो रही है तथा घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से प्रथम दृष्ट्या गंभीर क्षति के खतरे/गंभीर क्षति का मामला प्रतीत होता है। अतः 20 अगस्त, 2009 को

जाँच शुरू की गई थी । जाँच के दौरान आवेदकों ने संवेदनशील स्थितियों के संबंध में विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लागू करने का अनुरोध किया ।

कास्टिक सोडा पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क:

319. 200 दिन के लिए 20% की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम 15 अक्टूबर, 2009 को जारी किए गए थे । केन्द्र सरकार ने 4.12.2009 की अधिसूचना सं. 131/2009-सी.शु. द्वारा 3 माह के लिए 15% की दर से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

जांचाधीन उत्पाद

320. जांचाधीन उत्पाद "सोडियम हाइड्रॉक्साइड" है जिसे क्षारीय स्वरूप में कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है । कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची I के उप-शीर्ष सं. 28151200 के तहत वर्गीकृत किया गया है । कास्टिक सोडा को रासायनिक तौर पर NaOH के नाम से जाना जाता है । कास्टिक सोडा एक झागदार, अत्यधिक क्षारीय, गंधहीन द्रव्य है जिसका विविध औद्योगिक क्षेत्रों में या तो कच्ची सामग्री के रूप में अथवा एक आनुषंगिक रसायन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है । इसका उपयोग लुग्दी एवं कागज, अखबार के प्रिंट, विस्कस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम, रूई आदि के विनिर्माण में किया जाता है । प्रारंभिक जांच परिणाम से यह पता चला है कि आयातित कास्टिक सोडा की तकनीकी विशेषताएं समान होती हैं, उनकी बिक्री समान विपणन माध्यमों से की जाती है तथा उन्हें एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है । अतः आयातित कास्टिक सोडा को, घरेलू रूप से उत्पादित कास्टिक सोडा के "समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" वस्तु माना जाता है ।

घरेलू उद्योग :

321. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे उत्पादकों से है-

जो भारत में समग्र रूप से समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादक हों अथवा

जिनका भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का कुल उत्पादन, भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है ।

322. वर्तमान मागले में कार्स्टिक सोडा के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने हेतु भारतीय अल्कली विनिर्माता एसोसिएशन (एएमएआई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत विहार, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने कुछेक ऐसी कंपनियों के आंकड़े प्रकट किए हैं जिनका हिस्सा भारतीय उत्पादन में 35% है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि "प्रमुख" का अर्थ 50% से अधिक नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने अर्जेंटीना-ब्राजील से कुक्कुट पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया है। तथापि आवेदक द्वारा दिए गए तर्क की वैधता पर अधिक विचार न करते हुए, रक्षोपाय जांच प्रारंभिक तौर पर, घरेलू उद्योग के रूप में 13(तेरह) विनिर्माता इकाइयों पर आधारित थी, जिनका हिस्सा, भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 60% से अधिक बनता है। 13 इकाइयों को "घरेलू उद्योग" मानते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे। ये विनिर्माण इकाइयाँ हैं :

क. मै. पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लि. (इकाई I तथा II), नंगल ऊ ना रोड नया नंगल, जिला-रोपड़, पंजाब

ख. मै. सिएल केमिकल कॉम्प्लेक्स (मवाना शुगर्स लि. की एक इकाई), ग्राम-खदौली, चरतरामपुर, राजपुरा, जिला-पटियाला

ग. मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., रसायन प्रभाग, पो.ऑ.-बिरलाग्राम, नागदा (म. प्र.)

घ. मै. गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि., दाहेज, पो.ऑ.-दाहेज, तवाग्रा, जिला-भरुच

ङ. मै. गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि., बड़ौदा, पो.ऑ.-पेट्रोकेमिकल्स, रनौली, बड़ौदा-391346

च. डीसीएम, श्रीराम, श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, डीएससीएल की एक इकाई, कोटा

छ. श्रीराम अल्कली एंड केमिकल्स, 749, जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, झगड़िया, जिला-भरुच, गुजरात-393110

ज. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., दाहेज, दाहेज विनिर्माण प्रभाग, पो.ऑ.-दाहेज, जिला-भरुच, गुजरात-392130

झ. मै. डीसीडब्ल्यू लि., साहूपुरम, जिला-तूतीकोरिन

ञ. इंडियन रेयॉन, आदित्य बिड़ला की एक इकाई, न्यूवो लि., जूनागढ़-वेरावल रोड, विरावल जिला-जूनागढ़, पिन-362012

ट. मै. गुजरात फ्लूरो केमिकल्स लि., प्लॉट सं. 12-ए, जीआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, दाहेज, भरुच, गुजरात

ठ. मै. कन्नौरिया केमिकल्स एंड इंड. लि., पो.ऑ.-रेणूकोट-231217, जिला-सोनभद्रा

ड आदित्य बिड़ला केमिकल्स (आई) लि. (पूर्व में मै. बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स), गढ़वा रोड, ग्राम एवं पो.ऑ.-रेहला, जिला-पलामू (झारखण्ड)

323. भारत के कुल उत्पादन में इन 13 विनिर्माण इकाइयों का हिस्सा पिछले तीन वर्षों में 60 से 71% के बीच रहा है :

324. हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान लिखित अनुरोधों और मौखिक अनुरोधों के जरिए अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। यह अनुरोध किया गया कि 35% से बहुमत नहीं बनता है। बहुमत का सामान्य अर्थ आधे से अधिक से होता है। ब्राजील से कुक्कुट पर अर्जेन्टीना-निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के मामले में पैनल की रिपोर्ट में उल्लिखित जांच परिणाम वर्तमान मामले में संगत नहीं है क्योंकि रक्षोपाय कानून तथा पाटनरोधी कानून अलग-अलग हैं। यह भी अनुरोध किया गया था कि जांच या तो केवल आवेदक की स्थिति पर या फिर कुल उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि आवेदक तथा घरेलू उद्योग एक तथा समान हैं। कुछ ने यह भी तर्क दिया था कि महानिदेशक को आवेदन में निहित तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए।

325. इस मुद्दे की जांच की गई थी "बहुमत" का शब्दकोषगत अर्थ "प्रमुख, गंभीर या अधिक"¹ से है। यह भी सच है कि जांच घरेलू उद्योग को हुई "गंभीर क्षति" या "गंभीर क्षति के खतरे" की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए की जाती है। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से समस्त घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (ख) में घरेलू उद्योग को उक्त उत्पाद के समग्र घरेलू उत्पादकों अथवा उन घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रमुख, गंभीर या अधिक साक्ष्य जो घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें दावे के साथ लगाया जाए।

326. इस प्रश्न का उत्तर सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1), रक्षोपाय नियम एवं रक्षोपाय करार की समग्र स्कीम में मिल जाता है कि क्या महानिदेशक को आवेदन में निहित तथ्यों तक सीमित रहना है। धारा 8 ख (1) में केन्द्र सरकार को आवश्यक समझी गई ऐसी पड़ताल करने के बाद रक्षोपाय शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। रक्षोपाय नियमों में महानिदेशक द्वारा "गंभीर क्षति" अथवा "गंभीर क्षति के खतरे" की मौजूदगी की जांच करने का

¹ दि कन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ करन्ट इंग्लिश (क्लेरेन्डन प्रेस, 1995) पृष्ठ 882

प्रावधान है। "पड़ताल"² शब्द का अर्थ "सूचना मांगने के कार्य" से है तथा "जांच"³ का तात्पर्य तथ्यों का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक तलाश करने या परीक्षण करने से है। "पड़ताल"⁴ शब्द का तात्पर्य सूचना या सत्यता का पता लगाने में किसी मामले का गहन परीक्षण करने से भी है। ब्लैक की लॉ शब्द कोश में "पड़ताल"⁵ को "प्रक्रियात्मक अथवा तथ्यात्मक सूचना के अनुरोध" के रूप में परिभाषित किया गया है।

327. रक्षोपाय करार की समग्र स्कीम तथा रक्षोपाय नियमों में तथ्यों का पता लगाने और उनकी जांच करने का भी प्रावधान है। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि महानिदेशक को आवेदन में उल्लिखित तथ्यों तक ही सीमित रहना है।

328. वर्तमान मामले में आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसो. ऑफ इंडिया (एमएआई) द्वारा दायर किया गया था। अल्कली मैन्यु. एसो. ऑफ इंडिया कास्टिक सोडा के समस्त घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन है अतः अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसो. ऑफ इंडिया रक्षोपाय नियमों के नियम 5(1) के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर करने हेतु सक्षम है। तथापि, आवेदक के उस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे घरेलू उत्पादक "घरेलू उद्योग हैं" जिनका सामूहिक उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 35% बनता है क्योंकि आवेदक द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया जा सका कि ये उद्योग प्रमुख, गंभीर या महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि इन उत्पादकों की सामूहिकता से समग्र उद्योग की प्रतिनिधिक स्थिति का पता चल सके।

329. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6)(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा हेतु दो विकल्प दिए गए हैं, प्रथमतः उत्पाद के समग्र घरेलू उत्पादकों को एक साथ लिया जाए और द्वितीयतः वे घरेलू उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। प्रथम विकल्प का एक अंतरनिहित लाभ यह है कि इसमें संबंधित उत्पाद के उद्योग के कार्य की पूर्ण स्थिति प्रदर्शित होती है। अतः जब "घरेलू उद्योग" के रूप में समग्र घरेलू उत्पादकों पर विचार करना व्यवहार्य होता है, तब समस्त घरेलू उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" मानना सर्वोत्तम विकल्प होता है। अतः कास्टिक सोडा के समस्त घरेलू

² पड़ताल (सं.) सूचना मांगने का कार्य। दि कन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 10वां संस्करण (भारतीय संस्करण) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

³ जांच सं. जांच का कार्य या प्रक्रिया; तथ्यों का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक तलाशी या परीक्षण

जांचात्मक (वि) कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी-कम्पलीट एंड अन एब्रिज्ड छठा संस्करण, 2003 © विलियम कॉलिन्स संस एंड के. लि, 1979, 1986 हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स 1991, 1994, 1998, 2000, 2003

⁴ पड़ताल

1. पड़ताल का कार्य

2. कोई प्रश्न, कोई घुछताछ

3. सूचना या सत्यता का पता लगाने में किसी मामले का गहन परीक्षण

इनका तात्पर्य जानकारी, आंकड़ों के असत्यता का पता लगाने से है; खोए हुए पोटलदान के बारे में पड़ताल दायर करना; उसकी मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए पड़ताल करना; उसके राजनीतिक कार्यकलापों की पड़ताल करना; कोई आपराधिक जांच; आरोपित पुलिस भ्रष्टाचार की जांच, वैज्ञानिक अनुसंधान

अमरीकन हैरीटैज® डिक्शनरी ऑफ दि इंग्लिश लैंग्वेज, चौथे संस्करण, कॉपीराइट 2000 हॉटन मिफलिन कंपनी। 2009 में अद्यतित।

हॉटन मिफलिन कंपनी द्वारा प्रकाशित

⁵ पड़ताल (1) अंतर्राष्ट्रीय कानून। तथ्य का पता लगाना (2) संसदीय कानून प्रक्रियात्मक या तथ्यात्मक सूचना का अनुरोध।

उत्पादकों को रक्षोपाय शुल्क नियम, 1997 की धारा 8 ख (6) (ख) (iii) के अर्थ के भीतर सामूहिक रूप से "घरेलू उद्योग" माना जाता है ।

जाँच की अवधि :

330. कुछ संबद्ध पक्ष ने यह तर्क दिया है कि जाँच अवधि जाँच शुरूआत के समय निर्धारित की जानी चाहिए और आंकड़ों का विश्लेषण केवल वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए ।

331. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम 2002, रक्षोपाय करार अथवा गैट के संगत अनुच्छेद XIX में इस आशय की विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि जाँच अवधि क्या होनी चाहिए । तथापि, अर्जेंटीना फुटवियर पर पैनल की रिपोर्ट में एवं अर्जेंटीना पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में जाँच अवधि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है ।

“ अर्जेंटीना-फुटवियर के आयातों पर रक्षोपाय : पैनल की रिपोर्ट

8.216 जहाँ तक जाँच में घरेलू उद्योग की स्थिति में परिवर्तन के विश्लेषण में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की गई तुलनाओं पर लगभग पूर्ण भरोसा किए जाने का संबंध है, हमारी भी वही चिंता है जैसी कि "संवर्धित आयातों" के विश्लेषण के बारे में ऊपर नोट किया गया है। यहाँ हम इस बात को खासतौर पर नोट करते हैं कि यदि मध्यवर्ती रूझानों पर क्रमबद्ध ढंग से विचार नहीं किया जाता है और उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी "समस्त संगत कारकों" का विश्लेषण करने के बारे में अनुच्छेद 4.2(क) की अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णरूप से आकलन नहीं होता है । उदाहरणार्थ, ऐसी किसी उद्योग की स्थिति, जिसका उत्पादन एक वर्ष में काफी कम हो जाता है परंतु उसके बाद उसमें लगातार सुधार होता है यद्यपि कुछ स्तर तक यह शुरूआती स्तर से कुछ कम रहता है तो यह स्थिति तर्कसम्मत ढंग से ऐसे किसी उद्योग की स्थिति से अलग होगी जिसके उत्पादन में विस्तारित अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है । एक छोर से दूसरे छोर तक का विश्लेषण दोनों मामलों में एक समान होना चाहिए जबकि वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों एवं रूझानों पर विचार करने से पूर्णतः विपरीत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ।

हमारा मानना है कि विभिन्न क्षतिकारकों में जाँच अवधि के दौरान परिवर्तनों पर विचार करना इस बात के निर्धारण हेतु अनिवार्य है कि क्या किसी उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का आसन्नवर्ती खतरा उत्पन्न हो गया है । मध्यवर्ती रूझानों पर विचार किए बिना एक छोर से दूसरे छोर तक की तुलना से अपेक्षानुसार समस्त संगत कारकों का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान करने की संभावना नहीं है ।

अपीलीय निकाय की रिपोर्ट

नोट 130.

पैनल ने पैनल रिपोर्ट के पैरा 8.166 की पाद टिप्पणी 530 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान काल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें यह उल्लेख है कि "यह प्रतीत होगा कि जांच अवधि का शुरुआती बिंदु कोई भी हो उसे हाल की निकटतम अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए" (जोर दिया गया)। यहाँ हम पैनल से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि संगत जांच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए अपितु उसे हाल की अवधि होनी चाहिए।

332. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो रक्षोपाय करार और न ही डब्ल्यूटीओ के संगत प्रावधानों में जांच अवधि की विशिष्ट परिभाषा या व्याख्या निहित नहीं है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जाँच परिणाम दिया गया है कि संगत जाँच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए; जाँच अवधि हाल की अवधि होनी चाहिए। अतः आवेदन दायर करने के बाद की अवधि की रक्षोपाय जांच में अनदेखी नहीं की जा सकती। तथापि, प्राकृतिक न्याय की जरूरत को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जांच की शुरुआत के बाद प्राप्त या संगृहीत सूचना हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध हो।

333. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि आंकड़ों का विश्लेषण केवल वार्षिक आधार पर किया जाए न कि तिमाही आधार पर, यह नोट किया जाता है कि कानून में आंकड़ों के विश्लेषण के तरीके के बारे में कोई विशिष्ट निर्धारण अथवा नुस्खा नहीं है। इसके अलावा गैट के अनुच्छेद-XIX में अप्रत्याशित घटनाक्रमों तथा संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आयात में वृद्धि की शर्तें लगाई गई हैं। इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण आयात में कोई वृद्धि हुई है या नहीं, यह आवश्यक है कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के बाद आयातों की तुलना अप्रत्याशित घटनाक्रमों से पूर्व हुए आयातों के साथ की जाए। अतः सभी मामलों में और खासकर तब जब अप्रत्याशित घटनाक्रम वर्ष के बीच में जन्म लेते हैं और न कि लंबी अवधि तक बने रहते हैं, कैलेंडर वर्ष या एक वित्त वर्ष के आधार पर आंकड़ों की तुलना और उनका विश्लेषण उचित नहीं हो सकता।

334. इसके अलावा, जांच अवधि के विस्तार को कानून में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, इसे इतना कम नहीं होना चाहिए जिसे अस्थायी परिदृश्य माना जाए।

335. चूँकि जाँच की शुरुआत वर्ष के बीच में की गई है, अतः वार्षिक सूचना अत्यंत अद्यतन सूचना नहीं होगी। अतः विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, त्रैमासिक आंकड़े भी प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक अवधि की भिन्नताओं, यदि कोई हों, के प्रभावों के निराकरण हेतु पूर्ववर्ती वर्षों की समानरूपी अवधि के साथ तुलना की गई है। संक्षिप्त शब्द, ति1, ति2, ति3 तथा ति4 का अभिप्राय क्रमशः अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर तथा जनवरी-मार्च से है।

सूचना की पद्धति एवं स्रोत :

आयात के आंकड़े

336 आयात आंकड़ों के प्रयोजनार्थ वित्त वर्ष 2007-08 हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर और उसके बाद की अवधि के लिए आईबीआईएस के आंकड़ों पर विचार किया गया था । सूचना के सौदेवार ब्यौरे सार्वजनिक फाइल में रखे गए हैं ।

337. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आई बी आई एस के आंकड़ों में कुछ प्रविष्टियां कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित नहीं हैं और एल एंड टी का डी एम टी में परिवर्तन सही तथ्य पर आधारित नहीं है । एएआई तथा मै. वेदान्ता ने अपने दावे के समर्थन में कुछेक दस्तावेजों की 12 फोटो प्रतियां प्रस्तुत कीं जिन्हें प्रवेश बिल की प्रतियां होने का दावा किया । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया कि इस बात की संभावना है कि आई बी आई एस के आंकड़ों एवं उनकी परिवर्तन पद्धति में अन्य प्रविष्टियों में इस प्रकार की त्रुटि हो सकती है ।

338. आयात के आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन करने की पद्धति तैयार करने तथा आयात की सही मात्रा एवं मूल्य को निकालने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें परामर्शदाता तथा हितबद्ध पक्षकार उपस्थित हुए थे । इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई थी ।

1. आई बी आई एस से प्राप्त आंकड़ों का मिलान तथा समाशोधन करने के लिए सॉफ्ट रूप में आई बी आई एस के मूल आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए और एक-दूसरे से तुलना की जानी चाहिए ।
2. एएआई का प्रतिनिधि प्रस्तुत किए गए 12 प्रवेश बिलों के अलावा, मात्रा में कोई असंगति होने की स्थिति में तीन दिनों के भीतर कोई अन्य प्रवेश बिल प्रस्तुत करेंगे । आयात की मात्रा और मूल्य का सत्यापन करने के लिए एएआई द्वारा 12 आयात परेषणों से संबंधित पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे ।
3. याचिकाकर्ता द्वारा आयात के आंकड़ों के बारे में मै. एच एल एल के परामर्शदाता की आपत्ति पर प्रविष्टिवार टिप्पणियां प्रस्तुत की जाएंगी ।
4. चार प्रमुख पत्तनों अर्थात् मुंबई, जे एन पी पी, कांडला तथा विशाखापत्तनम के आयात के आंकड़े जहां से बड़ी मात्रा में आयात होते हैं, प्राप्त कर उन्हें अनुरोध करने वालों में परिचालित किया जाए ।
5. निर्यातकों से बैठक में उपस्थित अपने परामर्शदाताओं के जरिए यह अनुरोध किया गया था कि वे भारत को निर्यातित माह-वार एफओबी मूल्य तथा मात्रा का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

339. तदनुसार आंकड़ा संग्रहण एजेंसियों से प्राप्त आई बी आई एस के कच्चे आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे । आवेदक ने आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी भी उनके पास भेजी थी, जिन्होंने इसका अनुरोध किया था । चार प्रमुख पत्तनों से हुए कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित सीमाशुल्क आंकड़े भी एकत्र किए गए थे । आंकड़ों की प्रतियां भी अनुरोधकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई थीं ।

340. इन सौदा-वार आंकड़ों की छानबीन की गई थी ताकि उत्पाद के विवरण की जांच कर विचाराधीन उत्पाद से असंबद्ध समस्त सौदों को अलग किया जा सके । आंकड़ों से मात्रा की इकाई का पता चला, जिसे मात्रा का पता लगाने की इकाई माना गया ।

341. चार प्रमुख पत्तनों के सीमाशुल्क आयुक्तालयों से प्राप्त आंकड़ों और उक्त चार प्रमुख पत्तनों से भिन्न पत्तनों से कास्टिक सोडा तरल के आयात के आई बी आई एस से प्राप्त आंकड़ों को संकलित किया गया है और अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2009 की अवधि हेतु उन पर विचार किया गया है ।

अन्य आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना

342. भारत के सभी विनिर्माताओं से संबंधित अन्य आर्थिक मानदण्डों को अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) तथा अलग-अलग इकाइयों से प्राप्त किया गया था । आवश्यक सत्यापन भी किया गया है । इसके अतिरिक्त हरिमन केमसल्ट लि. की अध्ययन रिपोर्ट, जो क्लोर-अल्कली उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है, का भी हवाला दिया गया है । यदि किसी और सूचना का इस्तेमाल किया गया है तो उस सूचना के साथ उसके स्रोत का उल्लेख किया गया है । इसके अलावा, इकाई की क्षमता अलग-अलग इकाइयों द्वारा सूचित वास्तविक कार्यात्मक क्षमता है ।

343. **संदर्भित आयात:** निम्नलिखित तालिका में तरल रूप में कास्टिक सोडा से संबंधित आयात के त्रैमासिक आंकड़े दिए गए हैं :-

तालिका 1

तिमाही आयात (डीएमटी){ड्राई मीट्रिक टन}				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	33641	32149	68760	96260
ति 2	15762	18149	28,949	322622
ति 3	45114	59299	6,786	
ति 4	20186	22614	73928	

344. वर्ष 2008-09 की ति 4 और 2009-10 की ति1 तथा ति2 में हुए आयात पिछले तीन वर्षों की इसी तिमाही में हुए आयातों से अधिक हैं। जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान कुल आयात 4,92,810 डीएमटी के हुए हैं जबकि 1,20,323 डीएमटी के आयात हुए थे जिनमें 300% से अधिक की वृद्धि हुई है।

345. अतः अंतिम निर्धारण यह है कि मात्रात्मक रूप में आयातों में तीव्र, अचानक और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

346. आयातों में तुलनात्मक वृद्धि: भारत के बाजार के कुल आकार में आयातों का हिस्सा निम्नानुसार रहा है :-

तालिका 2

बाजार के कुल आकार में आयातों का हिस्सा (%)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	6.71	6.12	12.36	15.17
ति 2	3.23	3.38	4.99	36.16
ति 3	8.46	10.46	1.34	
ति 4	3.90	3.96	12.4	

347. वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही में आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2008-09 की इसी अवधि में 4.99% से बढ़कर 36.16% हो गया जो समूची विचाराधीन अवधि के दौरान सबसे अधिक है। पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के दौरान बाजार हिस्से की तुलना में जनवरी-सितंबर, 2009 की अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में सर्वाधिक 14.04% की वृद्धि हुई है। जनवरी से सितंबर, 2009 के दौरान आयातों का हिस्सा 21.24% रहा है जो भी पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है।

348. अतः अंतिम निर्धारण यह है कि आयातों में तुलनात्मक रूप में भी वृद्धि हुई है।

आयातों का मूल्य

349. तालिका 3 में आयातों का औसत त्रैमासिक सीआईएफ मूल्य दिया गया है।

तालिका-3

आयातों का मूल्य रु./डीएमटी				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	14512	14274	18578	17327
ति 2	14957	14635	22907	12343
ति 3	16109	14954	17005	
ति 4	15622	14066	21582	

350. वर्ष 2009-10 की ति1 और ति2 के दौरान औसत सीआईएफ मूल्य में गिरावट आई। वर्ष 2009-10 की ति2 में मूल्य न्यूनतम स्तर अर्थात् 12343 रुपए/डीएमटी पर पहुंच गया। अतः अंतिम निर्धारण यह है कि आयात कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है।

351. **अप्रत्याशित घटनाक्रम :** हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था में आई वित्तीय मंदी असामानांतर रही है। वैश्विक मंदी से विश्व भर के विनिर्माण क्षेत्र में अचानक ह्रास आया है। यह ह्रास अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहा है और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण कास्टिक सोडा उद्योग भी प्रभावित हुआ है। उत्तर अमरीका तथा यूरोप और एशिया के कई भागों में कास्टिक सोडा की मांग में कमी से कीमतों में भारी गिरावट आई है। उदाहरणार्थ अमरीका में कास्टिक सोडा की मौके पर कीमत उस कीमत से घटकर 10वां हिस्सा हो गई जो सामान्यतः रहा करती थीं।⁶

352. वर्ष 2008-09 की ति3 को छोड़कर विभिन्न देशों में व्याप्त मंदी के बावजूद भारत में कास्टिक सोडा की मांग में वृद्धि जारी रही। उत्तर अमरीका तथा यूरोप में मंदी की वजह से कीमत की प्रवृत्ति निर्धारित हुई क्योंकि उनके पास वैश्विक उत्पादन क्षमता की आधे से अधिक क्षमता है।

353. ये घटनाक्रम अप्रत्याशित हैं और इसलिए ये "अप्रत्याशित घटनाक्रम" हैं। इन घटनाक्रमों से विश्व के विभिन्न भागों में कीमत में अंतर आया है। इससे भारतीय घरेलू कीमत तथा निर्यात कीमत के बीच कीमत में भारी अंतर भी आया है और इससे भारत को होने वाले आयातों में वृद्धि हुई है।

गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे से संबंधित साक्ष्यों का मूल्यांकन

354. **संस्थागत कार्य ढांचा:** "गंभीर क्षति" का तात्पर्य ऐसी क्षति से है जिससे किसी घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति आई हो;⁷ और "गंभीर क्षति के खतरे" का तात्पर्य गंभीर क्षति के स्पष्ट तथा आसन्नवर्ती खतरे से है।⁸

355. रक्षोपाय करार क अनुच्छेद 4.2 (क) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान तथा निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए कुछेक सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन उपबंधों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि ऐसे किसी मूल्यांकन में क्या प्रदर्शित होना चाहिए। इस प्रकार का कोई मूल्यांकन किसी मामले विशेष के तथ्यों तथा संबंधित उद्योग की स्थिति पर निर्भर रहते हुए अलग-अलग मामलों में अलग-देशों के लिए अलग-अलग होगा। प्रत्येक

⁶ स्रोत: www.icis.com तथा हरीमन कैमसल्ट लि.

⁷ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6)(ग)

⁸ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6)(घ)

सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में अनिवार्यतः यह प्रदर्शित नहीं होगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही हो उदाहरणार्थ एक मामले में बिक्री, रोजगार तथा उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट आ सकती है जिससे उद्योग की स्थिति में "पर्याप्त समग्र विकृति" का पता चलेगा और इसलिए इससे गंभीर क्षति का जांच परिणाम न्यायोचित बन जाएगा । दूसरे मामले में कुछेक कारक में गिरावट नहीं आ सकती है परंतु समग्र स्थिति से उद्योग की "पर्याप्त समग्र विकृति" का पता चल सकता है । इस प्रकार समस्त सूचीबद्ध कारकों एवं अन्य किसी संगत कारक की तकनीकी जांच के अलावा यह जरूरी है कि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों के मद्देनजर उक्त उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए ।⁹

356. तदनुसार गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का विश्लेषण करने में नियमों में उल्लिखित सस्त कारकों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण हेतु संगत अन्य कारकों पर विचार किया गया है । किसी भी एक कारक को व्यर्थ नहीं माना गया है । प्रभावित घरेलू उद्योग के लिए संगत समस्त कारकों पर विचार किया गया है जो संगत व्यापार चक्र तथा प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के संदर्भ में आते हैं । गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों के मद्देनजर उक्त उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है ।

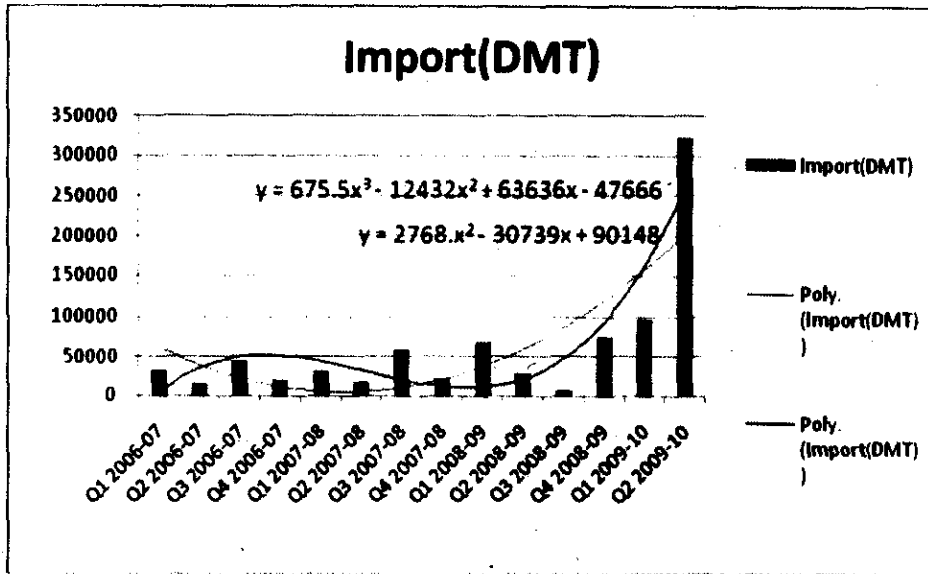
357. संगत कारकों का अभिज्ञान: गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी के निर्धारण हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया है :-

1. आयातों की वृद्धि दर
2. संवर्धित आयातों द्वारा हड़पा गया घरेलू बाजार का हिस्सा
3. बिक्री स्तर में परिवर्तन
4. उत्पादन
5. उत्पादकता
6. क्षमता उपयोग
7. लाभ एवं हानि
8. रोजगार
9. बिक्री लागत
10. घरेलू कीमतों की प्रवृत्ति
11. ईसीयू की लाभप्रदता

358. आयातों की वृद्धि दर : अप्रैल, 2007 के बाद आयातों की वृद्धि दर तथा आयातों की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए क्रम 1 तथा क्रम 3 के बोली नोमियल्स की प्रवृत्ति की रेखाएं खींचकर अध्ययन किया गया है । प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गयी है । प्रवृत्ति की रेखाओं से यह पता चलता है कि आयातों में वृद्धि दर सकारात्मक है और आयात में वृद्धि हो रही है । वर्ष 2009 में वृद्धि दर बढ़ी है ।

⁹ अर्जेंटीना फुटबियर मामले में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित ।

ग्राफ-1



359. संवर्धित आयातों द्वारा हड़पा गया घरेलू बाजार का हिस्सा : निम्नलिखित तालिका में घरेलू बाजार में समस्त घरेलू उत्पादकों का हिस्सा दिया गया है ।

तालिका-4

घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा (%)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	93.29	93.88	87.64	84.83
ति 2	96.77	96.62	95.01	63.84
ति 3	91.54	89.54	98.66	
ति 4	96.10	96.04	87.60	

360. उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि वर्ष 2009-10 की ति2 में घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घटकर 63.84% हो गया है जो विश्लेषण हेतु विचारित समूची अवधि के लिए न्यूनतम है । घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2009-10 की ति2 में आयातों की वजह से 31.17% बाजार हिस्सा तथा जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान 14.04% हिस्सा गंवाया है ।

361. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का यह नुकसान संवर्धित आयातों के कारण हुआ है ।

362. बिक्री के स्तर में परिवर्तन : तालिका 5 में घरेलू उद्योग द्वारा की गई तिमाही समेकित बिक्री दी गई है ।

तालिका-5

घरेलू उद्योग द्वारा समेकित बिक्री (डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	467602	493578	530966	538025
ति 2	472769	519328	550709	569402
ति 3	488394	507671	500116	
ति 4	497873	548682	522022	

363. वर्ष 2008-09 की ति.4 में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है । पूर्ववर्ती वर्ष की समान तिमाहियों की तुलना में 2009-10 की ति1 और ति2 में इसमें मामूली वृद्धि हुई है । पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के तुलना में जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान बिक्री में 908 डीएमटी की गिरावट आई है । यह देखा जाता है कि भारत में मांग में वृद्धि के बावजूद बिक्री नहीं बढ़ी है । यदि आयातों से कम कीमत पर कास्टिक सोडा की आपूर्ति में वृद्धि नहीं हुई होती, जिससे घरेलू कीमतों में गिरावट आई तथा बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो मांग में वृद्धि का बिक्री एवं घरेलू कीमत दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता ।

364. उत्पादन : तालिका 6 में घरेलू उद्योग का तिमाही उत्पादन निहित है ।

तालिका 6

घरेलू उद्योग का घरेलू उत्पादन (डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	409156	513313	553111	559552
ति 2	478836	535274	570672	580567
ति 3	501207	541237	520889	
ति 4	515987	559254	539546	

365. वर्ष 2009-10 की ति.4 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में ति.1 और ति.2 में मामूली वृद्धि हुई। पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान उत्पादन में 3373 डीएमटी की गिरावट आई। यह भी देखा गया है कि मांग में वृद्धि तथा भारत में स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद उपर्युक्त स्थिति रही है। मांग में वृद्धि तथा स्थापित क्षमता में 1.26 लाख डीएमटी की वृद्धि का उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता। आयातों ने लगभग बढ़ी हुई समस्त मांग को हड़प लिया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने निवल बिक्री प्राप्ति को घटकर संबंधित आयातों का मुकाबला भी किया। यद्यपि, उसका लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

366. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि संबंधित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद भी उत्पादन की इस स्थिति का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक चक्रीय प्रभाव पड़ा है।

367. क्षमता उपयोग: तालिका-7 और तालिका 8 में घरेलू उद्योग की क्रमशः तिमाही क्षमता एवं क्षमता उपयोग को दर्शाया गया है।

तालिका 7

घरेलू उद्योग की क्षमता (डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	5,84,316	6,40,359	6,65,598	6,98,649
ति 2	5,86,208	6,43,734	6,72,769	7,18,396
ति 3	5,87,031	6,53,793	6,90,030	
ति 4	5,86,320	6,52,455	6,99,803	

तालिका 8

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग (%)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	80.29	80.16	83.10	80.09
ति 2	81.68	83.15	84.82	80.81
ति 3	85.38	82.78	75.49	
ति 4	88.00	85.72	77.10	

368. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि हो रही है। जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान क्षमता में 1,26,027 डीएमटी की वृद्धि हुई है। क्षमता में वृद्धि की प्रवृत्ति सतत रूप से हुई है क्योंकि जनवरी-सितंबर, 2008 में भी क्षमता में 1,20,409 डीएमटी की वृद्धि देखी गयी है। घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमता में वृद्धि घरेलू मांग में वृद्धि के अनुरूप रही है।

369. वर्ष 2008-09 की ति4 तथा 2009-10 की ति1 और ति2 में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में संबंधित तिमाहियों के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग न्यूनतम रहा है। जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में 84.54% से घटकर क्षमता उपयोग 79.35% हो गया है।

370. क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। तथापि, भारतीय मांग में वृद्धि को देखते हुए भारतीय उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार नैसर्गिक व्यापारिक निर्णय होते हैं। अतः क्षमता उपयोग में गिरावट संवर्धित आयातों के कारण आई है।

371. लाभ एवं हानि : निम्नलिखित तालिका में तिमाही लाभ एवं हानि को दर्शाया गया है। वर्ष 2008-09 की ति2 की तुलना में वर्ष 2009-10 की ति2 में घरेलू उद्योग के लाभ में 17,476 लाख की गिरावट आई और उसमें 6,328 लाख का नुकसान हुआ। जनवरी-सितंबर, 2007 और 2008 के दौरान घरेलू उद्योग ने क्रमशः 17,801 लाख रुपए तथा 16,127 लाख रुपए का लाभ कमाया। परंतु इसी अवधि के दौरान वर्ष 2009 में कुल लाभ में 13,423 की गिरावट आयी।

तालिका 9

घरेलू उद्योग की लाभ तथा हानि (लाख रुपए में)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	4,598	4,712	4,910	2,671
ति 2	5,961	6,022	11,148	(6,328)
ति 3	6,529	4,496	2,409	
ति 4	7,067	68	6,290	

372. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि लाभ में गिरावट आई है।

373. रोजगार : कंपनियां और इकाइयां बहु उत्पाद कंपनियां तथा इकाइयां हैं और इस प्रकार रोजगार से प्रभाव का पता नहीं चलता है। इसके अलावा, रोजगार में वृद्धि क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है। तथापि, विनिर्माता इकाइयों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका 10

कर्मचारियों की कुल संख्या				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	8373	8603	8489	8840
ति 2	8333	8559	8547	8913
ति 3	8319	8570	8686	-
ति 4	8308	8582	8664	-

374. **उत्पादकता:** तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2008-09 की ति4, 2009-10 की ति1 और ति2 के दौरान उत्पादकता में गिरावट आई है। यह गिरावट संवर्धित क्षमता के बाद भी मुख्यतः उत्पादन में गिरावट के कारण आई है।

तालिका 11

उत्पादकता (उत्पादन/कर्मचारी) मी.ट. प्रति तिमाही				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	56.03	59.67	65.16	63.30
ति 2	57.46	62.54	66.77	65.14
ति 3	60.25	63.15	59.97	-
ति 4	62.11	65.17	62.28	-

375. **बिक्री लागत :** तालिका 12 और तालिका 13 में कास्टिक सोडा की क्रमशः निवल बिक्री प्राप्ति/डीएमटी तथा बिक्री लागत की तिमाही सूचना निहित है। ग्राफ-2 को निवल बिक्री प्राप्ति तथा बिक्री लागत से संबंधित मासिक सूचना के बारे में सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। ग्राफ-3 में ईसीयू लागत तथा ईसीयू प्राप्ति दर्शायी गई है। (इलेक्ट्रो कैमिकल यूनिट) (ईसीयू = 1 मी.ट. कास्टिक सोडा की कारखाना कीमत + 0.88 मी.ट. क्लोरीन)।

तालिका 12

कास्टिक सोडा की तिमाही निवल बिक्री प्राप्ति /डीएमटी				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	15,798	16,251	17,673	20,158
ति 2	16,173	16,062	19,692	15,931
ति 3	16,338	15,923	19,720	
ति 4	16,385	15,037	21,681	

तालिका 13

0% लाभ पर बिक्री लागत (रु./डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	**	**	**	**
ति 2	**	**	**	**
ति 3	**	**	**	
ति 4	**	**	**	

तालिका 14

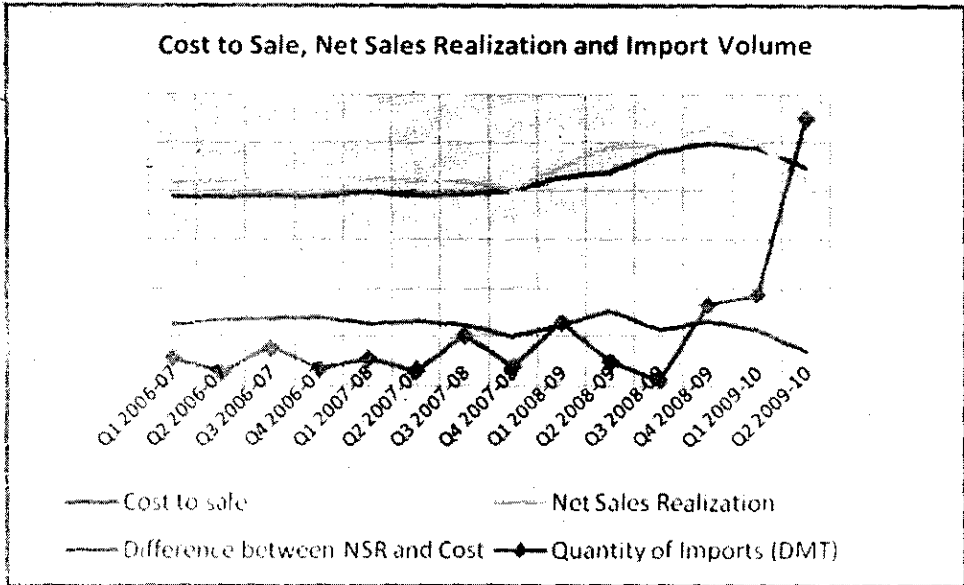
ईसीयू प्राप्ति (रु./डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	19,026	18,821	21,981	20,840
ति 2	19,355	19,922	22,936	19,144
ति 3	19,465	20,012	21,237	
ति 4	19,484	18,565	22,170	

तालिका 15

ईसीयू लागत (रु./डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	**	**	**	**
ति 2	**	**	**	**
ति 3	**	**	**	
ति 4	**	**	**	

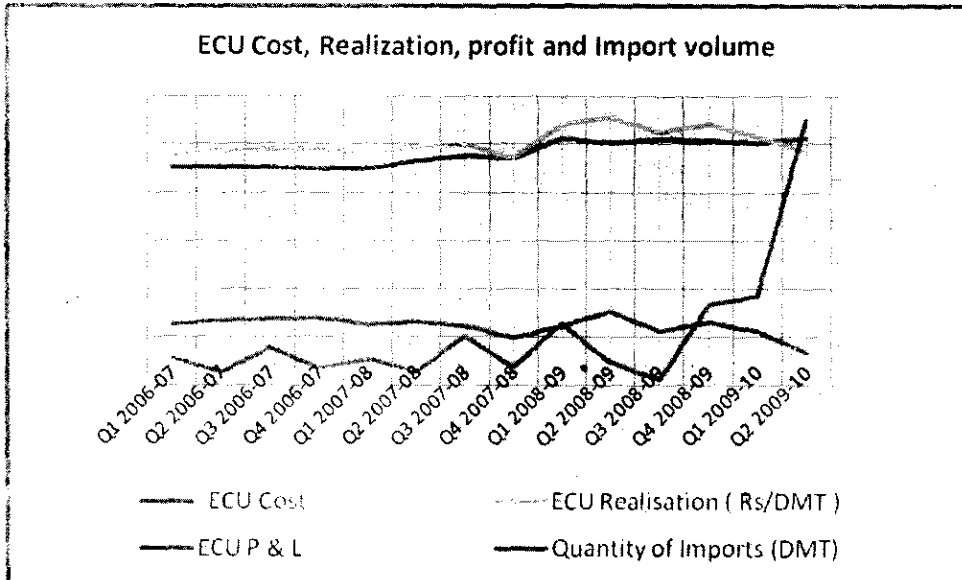
ग्राफ 2

बिक्री लागत, निवल बिक्री प्राप्ति तथा आयात मात्रा



ग्राफ 3

ईसीयू लागत, प्राप्ति, लाभ तथा आयात मात्रा



376. उपर्युक्त तालिकाओं और ग्राफों से स्पष्टतः यह पता चलता है कि वर्ष 2007-08 की ति4 से कार्बोनाट सोडा की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि शुरू हुई परंतु 2009-10 की ति1 में इसमें तेजी से गिरावट आई। वर्ष 2009-10 की ति2 में यह 15931 रूपए/डीएमटी के स्तर पर पहुंच गयी जो पिछले चार वर्षों की ति2 में सबसे कम है।

377. उपर्युक्त तालिकाओं और ग्राफों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कास्टिक सोडा और ईसीयू दोनों के संबंध में निवल बिक्री प्राप्ति तथा बिक्री लागत के बीच अंतर जनवरी, 2009 से कम होता गया और भारत में 2009-10 की दूसरी तिमाही के दौरान यह नकारात्मक बन गया। कास्टिक सोडा की निवल बिक्री प्राप्ति जनवरी, 2009, जब अंतर में कमी शुरू हुई, के बाद को छोड़कर समूची जांचाधीन अवधि के दौरान बिक्री लागत से अधिक रही है। ईसीयू प्राप्ति के मामले में यह प्रवृत्ति देखी गयी है जो ऋणात्मक अंतर के स्तर पर पहुंच गयी है। क्लोर अल्कली का व्यापार तभी व्यवहार्य होता है जब ईसीयू प्राप्ति बिक्री लागत की कम से कम बराबर हो। दूसरी तिमाही में ईसीयू प्राप्ति में आई गिरावट से 1571 रूपए/ईसीयू का घाटा हुआ है। अतः यह देखा जाता है कि कीमतों में इतनी गिरावट आने के कारण भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग अव्यहार्य बन गया है।

378. घरेलू कीमतों की प्रवृत्ति : तालिका 16 में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा घरेलू कीमतों पर इसके प्रभाव के बीच संबंध दर्शाया गया है। ग्राफ 4 में घरेलू उत्पादकों की निवल बिक्री प्राप्ति पर आयात का प्रभाव दर्शाया गया है।

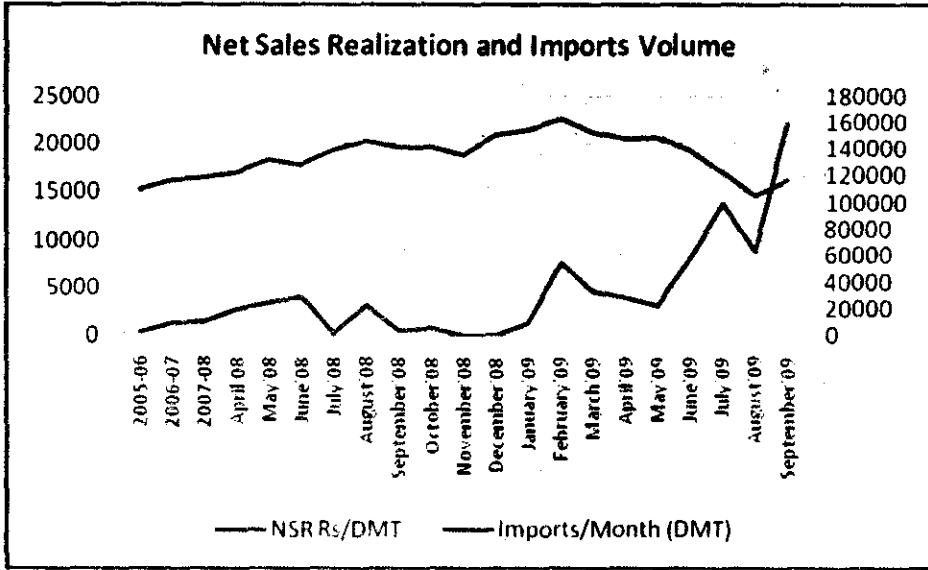
तालिका - 16

अवधि	औसत निवल बिक्री प्राप्ति (रु./डीएमटी)	निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत (अम.डॉ./डीएमटी)		
		ख	ग	घ
	क	नॉर्थ अमरीका	यूरोप	एशिया
	(रु./डीएमटी)			
2005-06	15277	-	-	-
2006-07	16202	-	-	-
2007-08	16479	-	-	-
अप्रैल, 08	16948	550-560	420-440	365-387
मई, 08	18275	580-600	465-485	420-450
जून, 08	17784	-	-	-
जुलाई, 08	19300	830-850	620-650	500-550
अगस्त, 08	20256	830-850	700-740	580-635
सितंबर, 08	19545	830-850	710-750	490-580
अक्टूबर, 08	19600	830-850	710-750	450-470
नवंबर, 08	18769	830-850	620-650	400-470
दिसंबर, 08	20887	830-850	600-640	400-470
जनवरी, 09	21401	830-850	600-640	360-450
फरवरी, 09	22545	820-850	600-640	310-390
मार्च, 09	21114	775-810	540-560	200-310

अप्रैल, 09	20519	225-325	200-250	200-250
मई, 09	20592	130-160	170-200	200-240
जून, 09	19303	90-110	90-120	170-200
जुलाई, 09	16996	35-75	50-60	130-150
अगस्त, 09	14675	40-65	60-80	115-150
सितंबर, 09	16235	125-150	140-170	210-230

ग्राफ 4

निवल बिक्री प्राप्ति तथा आयात मात्रा



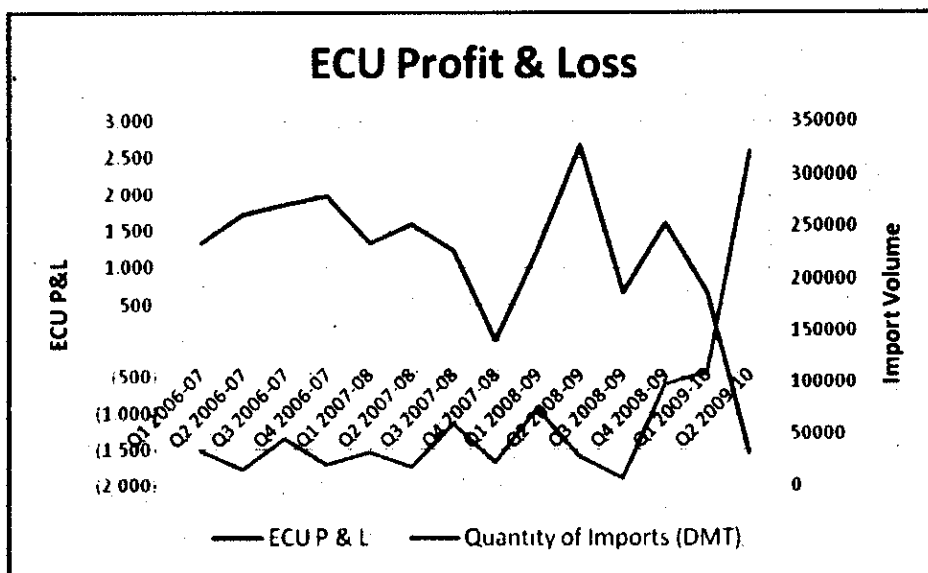
379. उपर्युक्त तालिका से भारत में बिक्री कीमत तथा उस कीमत के बीच कीमत अंतर की मौजूदगी का स्पष्ट पता चलता है जिस कीमत पर अंतराष्ट्रीय बाजार में कास्टिक सोडा उपलब्ध है। मांग में वृद्धि के अनुरूप भारत में कास्टिक सोडा का बाजार बढ़ता रहा। मांग में वृद्धि का निवल बिक्री प्राप्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता। परंतु उपर्युक्त ग्राफ से जनवरी, 2009, जब आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, से कास्टिक सोडा की घरेलू कीमतों में हास का पता चलता है। वर्ष 2008-09 की समान तिमाही में कीमत की तुलना में 2009-10 की दूसरी तिमाही में घरेलू कीमत में 3761 रुपये की गिरावट आई है। इसी तिमाही के दौरान घरेलू बिक्री पिछले चार वर्षों की समान तिमाही के दौरान न्यूनतम रही है।

380. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि आयातों से घरेलू बाजार में कीमतों में हास हुआ है।

381. ईसीयू की लाभप्रदता : निम्नलिखित ग्राफ में रुपये/ईसीयू के रूप में लाभप्रदता दर्शायी गयी है।

ग्राफ-5

ईसीयू लाभ तथा हानि



382. यह नोट किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण कास्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन साथ-साथ होता है। इस अभिक्रिया से लगभग निर्धारित अनुपात में कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन का साथ-साथ उत्पादन होता है। अतः ई सी यू आधार पर भी लाभप्रदता का विश्लेषण किया गया है जिसमें कास्टिक सोडा और क्लोरीन दोनों की कीमत घट-बढ़ पर विचार किया गया है। वर्ष 2008-09 की ति4 के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अधोगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वर्ष 2009-10 की ति2 में यह नकारात्मक हो गई है। जब संवर्धित आयात का पता चला तो लाभप्रदता में गिरावट लगातार और तेजी से हो रही थी।

383. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि आयातों में वृद्धि के बाद ईसीयू प्राप्ति में तेजी से अधोगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

384. **समग्र स्थिति का मूल्यांकन :** उपर्युक्त अलग-अलग मापदंडों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एक प्रमुख संकेतक अर्थात् ईसीयू प्राप्ति और 0% लाभ पर बिक्री लागत वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के बाद कम होने के बाद नकारात्मक हो गया है। अतः क्लोर अल्कली उद्योग अव्यवहार्य बन गया है। इसके अलावा, निर्यात हेतु कास्टिक सोडा की कीमत में तीव्र गिरावट के कारण निकासी द्वार खुल गए हैं जिसके परिणामस्वरूप आयातों की गति

तीव्र हो गई है । इस तथ्य को इस बात से भी बल मिलता है कि आयात में वृद्धि दर भी बढ़ रही है ।

385. जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान भारतीय उद्योगों का क्षमता उपयोग घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे स्पष्ट तौर पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलता है । घरेलू कीमतों में भारी गिरावट आई है । ति2 , 2009-10 में लाभप्रदता घटकर नकारात्मक बन गयी है । इन सभी मापदंडों से क्षति की मात्रा का पता चलता है ।

386. उपर्युक्त के आधार पर अंतिम निर्धारण यह है कि आयात में अत्यधिक वृद्धि, आयात के कारण घरेलू उद्योगों के बाजार हिस्से के नुकसान, बिक्री लागत से कम कीमत पर कास्टिक सोडा के आयात के कारण घरेलू उत्पादक ई सी यू बिक्री लागत से कम कीमत पर ईसीयू प्राप्ति के लिए बाध्य हुए हैं । इसके अलावा, घटते हुए क्षमता उपयोग, लाभ एवं लाभप्रदता में गिरावट की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिनसे स्पष्ट तथा आसन्नवर्ती गंभीर क्षति के खतरे का पता चलता है ।

अन्य कारक:

387. कास्टिक सोडा की मांग और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उत्पादकों की क्षमता : तालिका 17 में भारत में कास्टिक सोडा की मांग और तालिका 18 में भारत में कास्टिक सोडा की स्थापित क्षमता दर्शायी गई है । जनवरी-सितंबर, 2009 के दौरान कुल क्षमता 21,16,848 डीएमटी की थी और कुल मांग 2120479 डीएमटी की थी । कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग 88% की न्यूनतम क्षमता पर पहुंच सकता था और इस प्रकार वे इसी अवधि के दौरान 21.2 लाख डीएमटी की मांग की तुलना में अधिकतम 18.63 लाख डीएमटी का उत्पादन कर सकते थे । इसके उत्तर में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसे कई मामलों में विगत में रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है जिनमें घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था । वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग की पूर्ति हेतु उत्पादन करने की क्षमता है क्योंकि 100% से अधिक की क्षमता पर काम करना इस उद्योग में असामान्य बात नहीं है । वस्तुतः ऐसी कई इकाइयां हैं, जिन्होंने विगत में 100% क्षमता उपयोग के स्तर को पार किया था । इसके अलावा, समुचा आयातित कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि भारी क्षमता अभी भी स्टॉक में अथवा भांडागारों में पड़ी हुई है ।

तालिका-17

भारत में कास्टिक सोडा की मांग डीएमटी में				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	501244	525727	605852	634285
ति 2	488531	537477	579635	890244
ति 3	533507	566970	506902	
ति 4	518059	571296	595950	

तालिका 18

घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता (डीएमटी)				
तिमाही	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति 1	5,84,316	6,40,359	6,65,598	6,98,649
ति 2	5,86,208	6,43,734	6,72,769	7,18,396
ति 3	5,87,031	6,53,793	6,90,030	
ति 4	5,86,320	6,52,455	6,99,803	

388. इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। पूर्व में वर्तमान क्षमता प्रयोग हेतु क्या उत्पादन किया गया है, इस पर निर्भर होना एक सही नीति नहीं है। आयातों में प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अत्यधिक गिरावट आने के कारण निकासी द्वारा खुलने की वजह से हुई है।

389. निर्यात : भारत द्वारा वर्ष 2006-07 में किए गए वार्षिक निर्यात 17183 डीएमटी के रहे थे, जो कुल घरेलू उत्पादन का 0.86% है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में निर्यात 19311 डीएमटी तथा 11573 डीएमटी के हुए थे जो घरेलू उत्पादन का क्रमशः 0.89% और 0.53% है। वर्ष 2009-10 की ति 1 में 1785 डीएमटी का निर्यात हुआ जो कुल घरेलू उत्पादन का 0.3% है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात इतने कम मात्रा में हुए हैं, जिसका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

तालिका 19

वर्ष	निर्यात मात्रा (डीएमटी)	कुल उत्पाद के % के रूप में निर्यात
2006-07	17183	0.86
2007-08	19311	0.89
2008-09	11573	0.53

390. मांग एवं आपूर्ति में क्षेत्रीय असंतुलन: हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षेत्रीय आधार पर मांग एवं घरेलू आपूर्ति असंतुलित है। पश्चिमी जोन घरेलू उद्योग की ओर से अधिक आपूर्ति का सामना कर रहा है और पूर्वी जोन के पास कम क्षमता है परंतु मांग अधिक है क्योंकि लगभग समस्त एल्युमिनियम उत्पादक पूर्वी जोन में स्थित है। एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनुरोध किया है कि 3.85 लाख डीएमटी वार्षिक मांग की तुलना में पूर्वी जोन में स्थापित क्षमता केवल 2.85 लाख डीएमटी की है।

391. इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया था। अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2009 के दौरान कोलकाता पत्तन से प्रति माह औसत आयात केवल 299 डीएमटी प्रतिमाह के हुए

हैं जिससे यह पता चलता है कि कोलकाता से कोई खास आयात नहीं हुआ है । वित्त वर्ष 2008-09 में विशाखापत्तनम पत्तन से औसत मासिक आयात 7021 डीएमटी के हुए थे । अप्रैल से सितंबर, 2009 के दौरान औसत मासिक आयात बढ़कर 15,761.67 डीएमटी के हो गए । जहां तक मांग-आपूर्ति में अंतर का संबंध है, उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि यह पूर्वी जोन में विद्यमान है । पश्चिमी जोन से पूर्वी जोन में कास्टिक सोडा को ले जाना महंगा है परंतु वर्ष 2009-10 की ति.2 में आयात की मात्रा का दोगुना होना मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण नहीं हुआ है क्योंकि एल्युमिनियम उद्योग द्वारा कास्टिक सोडा की खपत की पद्धति से यह पता चलता है कि इसने आयातित कास्टिक सोडा के उपयोग को बढ़ाया है । पत्तनवार आयात के विश्लेषण से भी पत्तन की स्थिति पर ध्यान दिए बिना समस्त पत्तनों पर वृद्धि का पता चलता है । अतः आयात में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण हुई है ।

392. **भारत में क्लोरीन की मांग तथा कीमत :** क्लोरीन सर्वाधिक सक्रिय तत्व है और इसकी ढलाई करना काफी कठिन है । अतः इसका नगण्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है । इस प्रकार क्लोरीन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कारकों की अपेक्षा स्थानीय कारकों से अधिक प्रभावित होती हैं । क्लोरीन की अंतर्राष्ट्रीय तथा भारत में खपत की पद्धति निम्नानुसार है:-

तालिका -20
क्लोरीन की क्षेत्रवार वैश्विक मांग:

क्र.सं.	प्रयोक्ता उद्योग	क्लोरीन की कुल खपत में % हिस्सा
1.	विनायल	36
2.	क्लोरोमीथेन	5
3.	क्लोरोईथेन	1
4.	प्रोपीलीन ऑक्साइड	7
5.	एलीलिक्स/एपीक्लोरोहाइड्रिन	4
6.	फॉस्जीन/पॉलीकार्बोनेट	10
7.	अन्य (सीबी, सीपीआर, सीपीएफ)	5
8.	इनऑर्गेनिक्स, अन्य	32

स्रोत: टेक्नान आर्बीकेम (सी-12 व्युत्पत्तियों के विकास पर एएमएआई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, मई, 2008, मुंबई)

तालिका-21

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में क्लोरीन की क्षेत्रवार खपत की पद्धति

क्र. सं.	अंतिम प्रयोक्ता	प्रतिशत खपत		
		2005-06	2007-08	2008-09
1	विनायल (पीवीसी सहित)	17.11	17.59	16.58
2	ऑर्गेनिक्स	26.56	20.27	27.36
3	इनऑर्गेनिक्स	23.90	23.25	10.51

4	लुग्दी एवं कागज	10.29	8.27	8.32
5	सीपीडब्ल्यू	7.00	11.12	14.46
6	जलशोधन	2.75	2.02	2.39
7	कीटनाशक / जीवाणुनाशक / खरपतवारनाशक	1.50	4.74	5.92
8	भेषज	0.53	0.53	1.17
9	रंजक एवं स्याही	0.55	0.39	0.53
10	वस्त्र	0.44	0.58	1.01
11	अन्य	9.38	11.25	11.76

393. खपत की वैश्विक पद्धति की तुलना में भारत में क्लोरीन की अलग खपत की पद्धति के परिणामस्वरूप कीमत में अंतर आता है। अतः उत्तरी अमरीका तथा यूरोप में क्लोरीन की कीमतें भारतीय बाजार की कीमतों से अलग होती हैं।

394. विभिन्न देशों में क्लोरीन की कीमतों में भारी अंतर होता है। क्लोरीन की यह अलग-अलग कीमत उसकी व्यापार योग्यता तथा इन देशों में क्लोरीन के प्रयोक्ता उद्योग की प्रकृति में अंतर्निहित समस्याओं के कारण होती है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कुछेक देशों के उद्योग कास्टिक सोडा की कीमत घटा सकते हैं और अभी भी वे क्लोरीन की कीमत बढ़ाकर व्यवहार्य बने हुए हैं। भारत में क्लोरीन खपतकर्ता उद्योग की अलग प्रकृति के कारण क्लोरीन की कीमत में इतनी अधिक वृद्धि करना संभव नहीं है। एक निश्चित स्तर से अधिक क्लोरीन की कीमत बढ़ाने से क्लोरीन की व्युत्पत्तियों की कीमत बढ़ जाती है जिससे क्लोरीन की व्युत्पत्तियों का आयात जरूरी हो जाता है। इन परिस्थितियों में कम कीमतों पर कास्टिक सोडा के संवर्धित आयातों से कास्टिक सोडा की कीमत का ह्रास होता है जिससे ईसीयू प्राप्ति लागत से कम हो जाती है और उद्योग अव्यवहार्य बन जाता है।

395. **कारणात्मक संबंध :** क्षमता उपयोग, लाभ, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट, आयातों में वृद्धि की समसामयिक होती है। कम कीमत पर संवर्धित आयात के कारण भारत में कीमतों में ह्रास हुआ है जिससे लाभप्रदता तथा लाभ में घटा हुआ है। केवल संवर्धित आयात से बाजार हिस्से का नुकसान हुआ है। भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि संवर्धित आयातों ने हड़प ली है।

396. अतः संवर्धित आयात गंभीर क्षति के खतरे का एक प्रमुख कारक है।

हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच का सारांश

397. हितबद्ध पक्षकारों के समस्त अनुरोधों की जांच विश्लेषण करते समय की गई है और उन पर संगत स्थानों पर कार्यवाई की गई है। उठाए गए मुद्दों और उनके विश्लेषण का सारांश निम्नानुसार है :-

घरेलू उद्योग

398. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग नहीं हैं क्योंकि आवेदन केवल 35% घरेलू उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर दायर किया गया है। यूरोपीय संघ ने अनुरोध किया है कि जांच या तो एकल आवेदक अथवा पूर्ण उद्योग की स्थिति के आधार पर की जानी चाहिए।

399. **अनुरोधों की जांच :** हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया गया है और "घरेलू उद्योग" के मुद्दे से संबंधित विस्तृत विश्लेषण पैराग्राफ 321-329 में दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों की सभी चिंताओं पर विचार किया गया है और पूर्ण उद्योग "घरेलू उद्योग" है।

जांच अवधि

400. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जांच अवधि सीमित होनी चाहिए और किसी परवर्ती घटनाक्रम का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया था कि विश्लेषण केवल वार्षिक आधार पर होना चाहिए।

401. **अनुरोधों का विश्लेषण :** इस मुद्दे पर पैरा 330-335 में विस्तार से चर्चा की गई है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क किसी विधिक आधार से रहित हैं। हालिया सूचना पर विचार करना अधिक उचित होता है ताकि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बारे में निर्णय हाल की सूचना के आधार पर लिया जा सके। तिमाही सूचना वार्षिक सूचना से अधिक व्यापक होती है क्योंकि वार्षिक सूचना तिमाही सूचना से प्राप्त की जा सकती है परंतु तिमाही सूचना वार्षिक आंकड़ों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा, तिमाही सूचना से किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रवृत्तियों का भी पता चलता है।

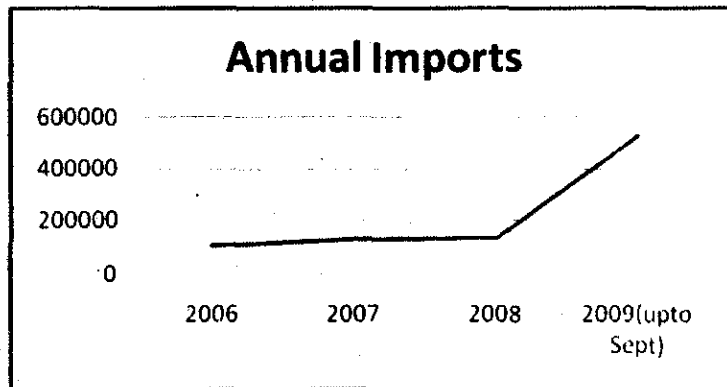
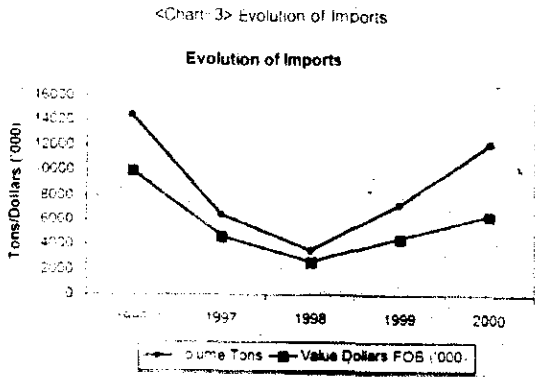
संवर्धित आयात

402. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। कोरिया सरकार ने यह तर्क दिया है कि आयातों में पूर्ववर्ती महीनों के दौरान अचानक गिरावट आने के बाद दिसंबर, 2008 से हाल में और तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसी ही वृद्धि वर्ष 2003 में अर्जेंटीना-पीच सेफ गार्ड के मामले में रक्षोपाय लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई थी।

403. **अनुरोधों का विश्लेषण :** आयात के आंकड़ों और प्रवृत्ति के विश्लेषण से स्पष्टतः यह पता चलता है कि दिसंबर, 2008 तक आयातों में सतत वृद्धि हुई है। उसके बाद आयातों में

ऐसी वृद्धि हुई है जैसी कि विगत में कभी नहीं हुई थी । पूर्ववर्ती वर्ष की समान तिमाहियों की तुलना में वर्ष 2008-09 की ति4 और 2009-10 की ति1 में आयातों में क्रमशः 263% और 71% की वृद्धि हुई है । इस वृद्धि को क्रमिक वृद्धि नहीं माना जा सकता ।

404. जहां तक पूर्ववर्ती महीनों में आयात में हुई कुछ वृद्धि के बारे में कोरिया सरकार के तर्क का संबंध है, आयातों के मासिक विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि मासिक आयात में घट-बढ़ एक प्राकृतिक घटना है । जहां तक अर्जेन्टीना पीच मामले में उल्लिखित संवर्धित आयातों की उद्धृत जांच का संबंध है, दोनों मामलों के बीच समानता का अध्ययन कास्टिक सोडा और डिब्बा बंद पीच के संवर्धित आयातों के ग्राफ की तुलना द्वारा किया गया है ।



405. अर्जेन्टीना पीच मामले और वर्तमान मामले में आयात के ग्राफ की तुलना अलग है । अर्जेन्टीना पीच मामले में हाल की अवधि (वर्ष 2000) में आयात 4 वर्ष पूर्व (अर्थात् 1996) में हुए आयात से कम रहे थे । वर्तमान मामले में आयात में विगत में लगातार वृद्धि हुई और हाल की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई । वर्ष 2009 (जुलाई तक) में हुए आयात पिछले 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष में हुए आयात से अधिक रहे हैं । अतः आयातों में वृद्धि हुई है ।

406. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध:** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयात के आंकड़ों का उपयोग पारदर्शी नहीं रहा है। डीएमटी में आंकड़े बदलने के लिए परिवर्तन कारक सही नहीं हैं। दावे के समर्थन में 12 प्रवेश बिल प्रस्तुत किए थे।

407. **अनुरोधों का विश्लेषण :** इस मुद्दे पर पैरा 336-341 में चर्चा की गई है। प्रमुख सीमाशुल्क गृहों से संग्रहीत सीमाशुल्क आंकड़ों तथा मूल आईबीआईएस आंकड़ों को इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है। इकाई को डीएमटी में परिवर्तित करने की पद्धति त्रुटि की किसी गुंजाइश से बचने के लिए अपनाई गई है। मात्रा की वास्तविक इकाई आयात पत्तन के सीमाशुल्क आंकड़ों से सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा, ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है कि आयातों में वृद्धि नहीं हुई है।

408. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क का अपवंचन करने/उससे बचने के लिए कई आयातक उच्च मूल्य पर आयात प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने निर्यात पत्तन पर एफओबी कीमत तथा प्रचलित भाड़े के साथ भारतीय पत्तन पर आयात कीमत (सीआईएफ) की सूचना प्रस्तुत की। उन्होंने यह तर्क दिया है कि विदेशी बिक्री के नाम पर आयात का अधिक मूल्यांकन भी किया जा रहा है और यह अनुरोध किया है कि रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ आयातकों के घोषित सीआईएफ मूल्य के बजाए प्रचलित भाड़े के साथ निर्यात कीमत पर विचार किया जाए। इस आरोप के उत्तर में संबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि सीमाशुल्क के समक्ष घोषणा अथवा अधिक मूल्यांकन के मुद्दे की जांच करना महानिदेशक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

409. **अनुरोधों का विश्लेषण :** सीआईएफ मूल्य (रूपए/डीएमटी) में भारी अंतर का पता चलता है। यह भी पाया गया है कि उसी आयात पत्तन से आयात उसी समय उद्गम के उसी देश से कीमत में भारी अंतर के साथ हो रहे हैं। यह भी पाया गया है कि कुछ अस्पष्ट अंतर सीआईएफ मूल्य तथा (एफओबी + प्रचलित भाड़े) आयातों के कुछ मामलों में पाया गया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि अलग-अलग प्राधिकारी के समक्ष आयातकों द्वारा की गई घोषणा रक्षोपाय जांच की विषय वस्तु नहीं है।

410. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** एल्युमिनियम विनिर्माताओं ने यह तर्क दिया है कि आयात में वृद्धि मांग तथा आपूर्ति में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण हुई है। एल्युमिनियम उद्योग पूर्वी जोन में स्थित है और अधिकांश कास्टिक विनिर्माता पश्चिमी जोन में हैं। पश्चिमी जोन में अधिक क्षमता के कारण अधिक आपूर्ति होती है। पूर्वी जोन में क्षमता में वृद्धि के कारण उपलब्धता कम है। आयात में वृद्धि भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

411. **अनुरोधों का विश्लेषण :** इस मुद्दे पर पैरा 402-403 में विचार किया गया है। आयात में वृद्धि केवल क्षेत्रीय असंतुलन के कारण नहीं हुई है क्योंकि आयातों में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई

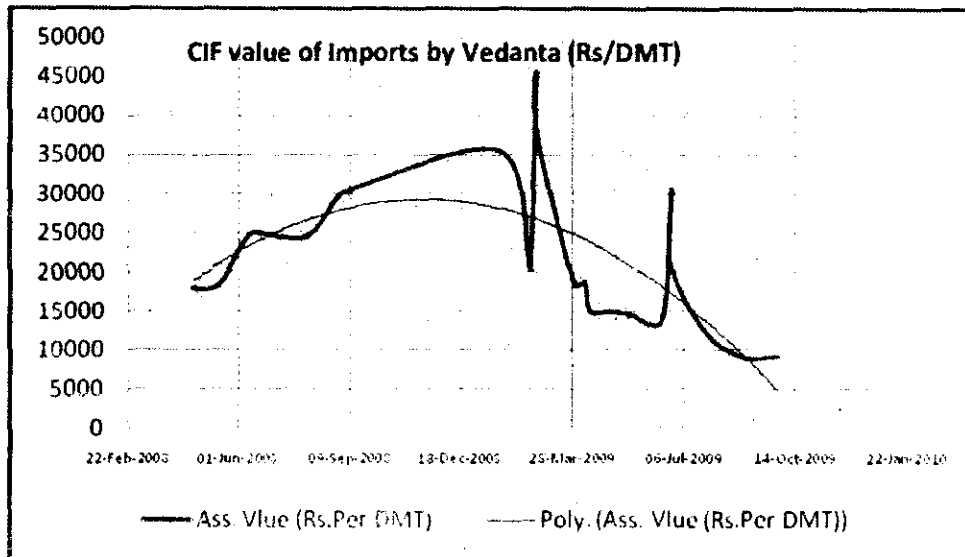
है और आयातों के पक्ष में खपत की पद्धति में परिवर्तन हुआ है । आयात में वृद्धि मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत में गिरावट के कारण हुई है ।

412. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** मै. वेदान्ता ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादक उन्हें आपूर्ति नहीं कर रहे हैं । अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए ई-मेल की प्रतियां प्रस्तुत की हैं और यह अनुरोध किया है कि वे उच्च कीमतों पर आयात कर रहे हैं । उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि आयात की कीमत उनके आयातों का कारण नहीं है ।

413. **अनुरोधों का विश्लेषण :** याचिकाकर्ताओं और कुछेक विनिर्माताओं ने कुछ ई-मेल प्रस्तुत किए हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि उन्होंने विशाखापट्टनम पत्तन जहां आयातित कास्टिक सोडा उतारा जाता है, पर जलयान द्वारा कास्टिक सोडा की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है । ई-मेल और याचिकाकर्ताओं की टिप्पणियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि मै. वेदान्ता को आपूर्ति करने से खेद प्रकट करना वेदान्ता फैक्ट्री को कास्टिक सोडा की ढुलाई में शामिल संभार तंत्र सहित विभिन्न कारकों पर आधारित है । इसी समय कुछ आपूर्तिकर्ता द्वारा खेद व्यक्त करने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी घरेलू आपूर्तिकर्ता ने खासकर तब जब अपने उत्पाद की उन्हें बिक्री करने के लिए घरेलू उत्पादकों की इच्छा प्रदर्शित करते हुए ई-मेल भी मौजूद हों, वेदान्ता और बाल्को को आपूर्ति करने के लिए कभी सहमति व्यक्त नहीं की है ।

414. उनके आयातों के कारण का आकलन करने के लिए विशाखापट्टनम पत्तन पर आयातों के सीआईएफ मूल्य का विश्लेषण किया गया है । विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुछ ऐसे आयात हुए हैं जिनकी कीमत असामान्य रूप से अधिक है परंतु अधिकांश अन्य आयात घटी हुई कीमत पर हुए हैं । निम्नलिखित ग्राफ में 1 अप्रैल, 2008 के बाद पत्तन पर हुए समस्त आयात दर्शाए गए हैं ।

वेदान्ता द्वारा आयातों का सीआईएफ मूल्य (रु./डीएमटी)



415. वेदांता ने निर्यातक देशों में कम कीमत के साथ-साथ थल मार्ग के भाड़े की तुलना में सस्ते समुद्री भाड़े के कारण आयातों को तरजीह दी है ।

416. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू विनिर्माता भारी मुनाफा कमा रहे हैं और इस प्रकार रक्षोपाय कार्यवाही अन्यायपूर्ण है ।

417. **अनुरोधों की जांच :** संचयी रूप में घरेलू उद्योग के वास्तविक लाभ और हानि तथा उसके विश्लेषण पर पैरा 377 तथा 385-395 में चर्चा की गई है । रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (202) ईएलटी 23 (एस सी) के अनुसार अलग-अलग इकाई की लाभप्रदता संगत नहीं है । इस पाटनरोधी मामले में माननीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि क्षति निर्धारण हमेशा समग्र घरेलू उद्योग के लिए होता है न कि अलग-अलग कंपनियों के लिए । वर्तमान मामले में जांच केवल तरल रूप में कास्टिक सोडा से संबंधित है, इसलिए कास्टिक सोडा (तरल) के कारोबार से संबंधित लाभप्रदता एक संगत मापदंड है । तथापि, अलग-अलग इकाइयों के लाभ से लाभ में तेजी से आई गिरावट का पता चलता है ।

418. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन लागत निकालते समय विद्युत की वास्तविक उत्पादन लागत के बजाए विद्युत के बाजार मूल्य, जो कि अधिक है, पर विचार किया गया है ।

419. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (202) ईएलटी 23 (एस सी) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि "हमारी राय में क्षति रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए हमेशा यह अपेक्षित होता है कि वह निविष्टियों की अंतरण कीमत (बाजार मूल्य) पर विचार करे न कि आबद्ध उत्पादन की वास्तविक लागत पर । ऐसा इसलिए है कि समूची जांच, विश्लेषण, संस्तुति और शुल्क अधिरोपण समूचे घरेलू उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु किया जाता है न कि अलग-

अलग कंपनियों तथा आबद्ध रूप से विनिर्मित निविष्टियों के लिए जो उक्त वस्तु के उत्पादन और बिक्री में शामिल हो सकती हैं ।"

420. वर्तमान मामले में लागत निकालते समय विद्युत के वास्तविक बाजार मूल्य पर विचार किया गया है ।

421. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** क्लोरीन की कीमतों में दक्षिण की तुलना में पश्चिम में अधिक गिरावट आई है जिससे यह पता चलता है कि वहां क्लोरीन की आपूर्ति अधिक है जिससे पश्चिम में कास्टिक का उत्पादन सीमित हो रहा है । इसके अलावा, पश्चिम में प्रतिस्पर्धा अधिक है जो पूर्व की तुलना में पश्चिम में कम ई सी यू प्राप्ति से स्पष्ट हो जाती है । इस तर्क के समर्थन में उन्होंने सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

422. **अनुरोधों का विश्लेषण :** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट की जांच की गई थी । दक्षिण जोन तथा पश्चिमी जोन में क्लोरीन की कीमतें निम्नानुसार रही हैं:-

क्लोरीन की कीमत (रुपए/टन में)	जन. 20 08	जन. 09	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
पश्चिमी जोन	8288	2115	2639	2250	1470	1128	4000	8237	9094	6239	2300	2534	3384
दक्षिणी जोन	7500	1500	1200	3500	1500	1500	2250	7500	9000	8500	7000	6000	5500

423. क्लोरीन की कीमत से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्लोरीन की कीमत में घट-बढ़ होती है और कभी-कभी यह दक्षिण की कीमत की तुलना में पश्चिम में अधिक होती है और कभी-कभी यह पश्चिम की तुलना में दक्षिण में अधिक होती है । हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क सर्वथा सही नहीं है कि दक्षिण की तुलना में पश्चिम में क्लोरीन की कीमत में अधिक गिरावट आई है । अतः पश्चिम में क्लोरीन की अधिक आपूर्ति का तर्क कीमत घट-बढ़ पर आधारित है जो सही नहीं है क्योंकि यह आधार ही तथ्यतः सही नहीं है । सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट में ही यह दर्शाया गया है कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब दक्षिण में कास्टिक की कीमत में गिरावट आई है जबकि पश्चिम में कीमत में वृद्धि हुई है । तथापि, पश्चिम की तुलना में दक्षिण में ईसीयू प्राप्ति अधिक रही है । ऐसा मुख्यतः इस आधार पर हुआ है कि कारखाना द्वार पर प्रमुख कच्ची सामग्री लवण की लागत पश्चिम में लवण की अधिक आपूर्ति के कारण दक्षिण की तुलना में पश्चिम में कम है । यह भी सच है कि पश्चिमी जोन में उत्पादन की अधिक क्षमता है और मांग अधिक है । अलग-अलग स्थानों पर प्रतिस्पर्धा का अलग-अलग स्तर हो सकता है । अलग-अलग स्थानों पर प्रतिस्पर्धा का अलग-अलग स्तर नैसर्गिक बाजारी स्थितियां होती हैं क्योंकि इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि समस्त स्थानों पर समान बाजारी स्थिति होगी । इसके अलावा यह निष्कर्ष निकालना भी काफी कठिन है कि अन्य पत्तन की तुलना में देश के एक पत्तन पर अधिक प्रतिस्पर्धा होने की वजह से देश में आयात अधिक होंगे अथवा इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी । अतः यह तर्क अपुष्टिकृत है कि उत्पादन जांच अवधि के दौरान क्लोरीन की अधिक आपूर्ति के कारण प्रभावित हुआ है । इसके अलावा पश्चिम या किसी भाग में अधिक प्रतिस्पर्धा कोई संगत कारक नहीं है ।

424. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** अधिक क्षमता के कारण पश्चिम जोन में आपूर्ति अधिक होती है । पूर्वी जोन में क्षमता में वृद्धि के कारण उपलब्धता कम है । आयात में वृद्धि भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं ।

425. **अनुरोधों का विश्लेषण :** पूर्वी जोन में पतनवार आयातों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि विशाखापट्टनम पतन को छोड़कर आयात नगण्य हुए हैं । विशाखापट्टनम पतन से मुख्यतः एल्युमिनियम विनिर्माताओं द्वारा कास्टिक सोडा का आयात किया जाता है । वेदान्ता को छोड़कर एल्युमिनियम विनिर्माताओं में से अन्य सभी विनिर्माता घरेलू कास्टिक सोडा पर निर्भर होते हैं । तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान खपत की पद्धति बदलकर आयातों के पक्ष में चली गई है । मै. वेदान्ता ने वर्ष 2008 में केवल दो तिहाई जरूरत की पूर्ति के मुकाबले वर्ष 2009 में आयातों के जरिए 100% जरूरत को पूरा किया है । इसी प्रकार अन्य एल्युमिनियम विनिर्माताओं की खपत में आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है । ऐसा घटती हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण हुआ है । जहां तक वेदान्ता को आपूर्ति का संबंध है, घरेलू कास्टिक सोडा की खरीद में उनकी समस्या संभार तंत्र में कमी की रही है ।

426. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा आयात बिक्री से अधिक है । अतः कोई क्षति नहीं हुई है ।

427. **अनुरोधों का विश्लेषण :** यह पाया गया है कि "गंभीर क्षति" अथवा "गंभीर क्षति के खतरे" के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आयात बिक्री घरेलू उद्योग की बिक्री से अधिक होनी चाहिए । "गंभीर क्षति" अथवा "गंभीर क्षति के खतरे" के लिए संगत समस्त मापदंडों का विस्तृत विश्लेषण जांच परिणामों में किया गया है ।

428. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** एक अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि भारत में आयात में वृद्धि इस वजह से हुई है कि भारत में कास्टिक सोडा के प्रयोक्ता खासकर तरल कास्टिक सोडा की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं । कास्टिक सोडा का उत्पादन पूर्णतः क्लोरीन के उत्पादन और बिक्री मात्रा पर निर्भर है । क्लोरीन ई डी सी, वीसीएम तथा पीवीसी रेजिनों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतिम उपयोग है । अधिकांश भारतीय क्लोर अल्कली विनिर्माता ईडीसी, वीसीएम तथा पीवीसी में समेकित नहीं हैं और इस प्रकार उनके समक्ष कास्टिक सोडा के उत्पादन को बढ़ाने में समस्या है क्योंकि वे ईडीसी, वीसीएम तथा पीवीसी के उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे हैं । भारत में अधिकांश क्लोर अल्कली विनिर्माता मर्चेन्ट क्लोरीन का ही उत्पादन करते हैं, जिसका भारत सहित विश्व भर में अति अल्प अंतिम बाजार है । मर्चेन्ट क्लोरीन का भंडारण अत्यंत कठिन, महंगा और खतरनाक है । परिणामतः कास्टिक सोडा का अधिक उत्पादन करने के लिए क्लोरीन का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता ।

429. **अनुरोधों का विश्लेषण :** क्लोरीन के बाजार और उसकी कीमत पद्धति के मुद्दे का अध्ययन किया गया है। यह सच है कि भारत तथा अन्य देशों में क्लोरीन की पद्धति अलग-अलग है। खपत की पद्धति से अलग-अलग देशों में कीमत की पद्धति अलग-अलग हो जाती है। इस मुद्दे पर पैरा 404-405 में विस्तार से चर्चा की गई है। जहां तक क्लोरीन को खपाने के लिए बाजार की क्षमता का संबंध है, भारत में क्लोरीन को खपाने और उसकी खपत करने की पर्याप्त क्षमता है। मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर क्लोरीन की कीमत पद्धति से यह पता चलता है कि आपूर्ति मांग से अधिक होने की स्थिति में क्लोरीन की कीमत नकारात्मक हो गई थी। परंतु दिसंबर, 2008 के बाद क्लोरीन की कीमत में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है जिससे यह पता चलता है कि आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। इसके अलावा, कई क्लोरोव्युत्पत्तियां हैं जिनका निर्यात बाजार है। यदि क्लोरीन की आपूर्ति बढ़ती है तो नैसर्गिक रूप से कीमत में गिरावट आती है जिससे घरेलू बाजार में क्लोरीन की मांग की पूर्ति हेतु क्लोरो व्युत्पत्तियों का निर्यात प्रतिस्पर्धी बन जाता है। अतः यदि भारत में संवर्धित आयातों के अभाव में बढ़ी हुई मांग की पूर्ति हेतु कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन का उत्पादन बढ़ाया होता तो उसने समस्त क्लोरीन की खपत कर ली होती।

430. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :** विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कोई समायोजन योजना नहीं है।

431. **अनुरोधों का विश्लेषण :** यह देखा जाता है कि आवेदकों ने पुनर्गठन योजना प्रस्तुत की है (अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है)। तथापि, समायोजन योजना का विश्लेषण तभी अपेक्षित होता है जब शुल्क एक से अधिक वर्ष के लिए हो।

432 **संबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुतिकरण** - सितम्बर 2009 से अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है। अस्थायी रक्षोपाय शुल्क प्रधानतः अमेरिका में घटते हुए मूल्य और कास्टिक सोडा के भारत के घरेलू मूल्य और निर्यात मूल्य के मध्य बढ़ते हुए अन्तर पर आधारित है। चूंकि कास्टिक सोडा के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है कास्टिक सोडा का घरेलू बिक्री मूल्य और वह मूल्य जिसमें कास्टिक सोडा अमेरिका में उपलब्ध है उसमें कुछ खास अंतर नहीं रह गया है। अतः आकस्मिक रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का कोई आधार दृष्टव्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयातित कास्टिक सोडा का लैन्डिड मूल्य घरेलू मूल्य से अधिक है। अतः आयातित कास्टिक सोडा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। सीधा कारखाने से खरीद वाले मूल्य से भी अगर आयात मूल्य अधिक है तो भी वह अनिवार्य है। इसका कारण अत्यधिक माल झाड़ा और कास्टिक सोडा के निर्माताओं द्वारा घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल न बिठा पाता है।

अवधि	निर्यात के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य (US\$ /डीएमटी) में		
	A	B	C
रुपये/ डी एम टी	उत्तरी अमेरिका	यूरोप	ऐशिया
अप्रैल 2009	225-325	200-250	200-250
मई 2009	130-160	170-200	200-240
जून 2009	90-110	90-120	170-200
जुलाई 2009	35-75	50-60	130-150
अगस्त 2009	40-65	60-80	115-150
सितम्बर 2009	125-150	140-170	210-230
अक्तूबर 2009	160-170	180-210	200-225
नवम्बर 2009	160-170	200-220	190-210
दिसम्बर 2009	160-170	180-200	190-210
जनवरी 2009	160-170	180-200	190-210
फरवरी 2009	200-220	180-200	180-215
मार्च 2009	220-230	190-200	200-220

433 प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण - यह मुद्दा मौजूदा तथ्य और घरेलू उद्योग द्वारा भेजे गए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया। यह सच है कि सितम्बर 2009 में कास्टिक सोडा US\$ 100 के मार्क को पार कर लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रारम्भिक जांच, जुलाई 2009 तक के आँकड़ों पर भरोसा कर बनाई गई थी। संयोग से, जुलाई 2009 में कास्टिक सोडा का न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मूल्य दर्ज किया गया और धीरे-धीरे मार्च 2010 में अप्रैल 2009 के स्तर पर पहुंचा। यह देखा गया कि अप्रैल 2009 में शुरू हुई तिमाही में लाभ में कुछ गिरावट आई परन्तु फिर भी लाभ सकारात्मक था। यह भी देखा गया कि अप्रैल-जून 2009 तिमाही के दौरान कास्टिक सोडा उद्योग काफी व्यवहार्य था चूंकि इसीयू कार्यान्वयन इसीयू मूल्य से अधिक था। फरवरी-मार्च 2009 में उत्तरी अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मूल्य US\$ 200 से भी अधिक था। अतः सितम्बर 2009 के बाद अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के परिदृश्य में काफी बदलाव नजर आया। एक मुख्य घटक जिसके द्वारा घरेलू उद्योग अव्यवहार्य होते नजर आ रहे थे उसमें कमी आई है। इसके अतिरिक्त, एक मुख्य कारण जिसकी वजह से आयात में बढ़ोत्तरी हुई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति में पहुंचाने का कारक अर्थात् उत्तरी अमेरिका में कास्टिक सोडा

तात्कालिक मूल्य, उसमें भी सुधार के लक्षण परिलक्षित है। यह घटक काफी निर्णायक है और रक्षोपाय शुल्क की अवधि निर्धारित करने में सुविचारित है।

434. **सार्वजनिक हित :** क्लोर अल्कली उद्योग कई उद्योगों को निविष्टि उपलब्ध कराता है। कास्टिक सोडा का उपयोग रसायन, कागज, साबुन एवं धातु उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इन सभी उद्योगों के स्वस्थ विकास के लिए यह आवश्यक है कि कास्टिक सोडा की सतत और भरोसेमंद आपूर्ति उपलब्ध रहे।

435. क्लोरीन का उपयोग प्लास्टिक तथा पोलिमर, सोल्वेंट, कृषि रसायन तथा भेषज के रूप में विसंक्रमणकारी एवं शोधक के रूप में तथा अंतिम उत्पाद के रूप में इसका उपयोग न किए जाने पर अन्य पदार्थों के विनिर्माण में एक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। विश्व भर में क्लोरीन का उपयोग जलजनित सूक्ष्म जैविक संक्रमण के खिलाफ अंतिम बचाव के रूप में जन आपूर्तियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। आज के युग में भारत में कॉलरा तथा अन्य जलजनित बीमारियाँ दूषित जल एवं सफाई की खराब व्यवस्था का घातक परिणाम है। क्लोरीन हजारों वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। क्लोरीन के अद्भुत गुणधर्मों पर निर्भर उत्पादों में शामिल हैं : घरेलू रंजक एवं तरंगताल विसंक्रामक जैसी दैनिक घरेलू मर्दें, आत्मरक्षा अंतर्वस्त्र, कंप्यूटर हार्डवेयर, सिलिकॉन चिप्स और आटोमोटिव पुर्जें।

436. इन उद्योगों के लिए क्लोरीन की स्थानीय उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि भारत में अपने आर्थिक विकास हेतु एक व्यवहार्य तथा स्वस्थ क्लोर अल्कली उद्योग हो।

437. इसके अलावा, रक्षोपाय शुल्क का निर्धारण करते समय इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि टैरिफ स्तर उसी सीमा तक रखा जाए जिस सीमा तक आयात अभी भी व्यवहार्य हैं और वे प्रतिस्पर्धा के समान स्तरों पर घरेलू उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क भी लागू है। स्वस्थ क्लोर अल्कली उद्योग की मौजूदगी विनिर्माताओं, अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के हित में है। क्लोर अल्कली उद्योग क्लोरीन आधारित उद्योगों की जीवनरेखा है क्योंकि क्लोरीन की आपूर्ति केवल घरेलू उत्पादक करते हैं। यदि क्लोर अल्कली उद्योग अव्यवहार्य बन जाता है तो क्लोरीन आधारित उद्योगों पर क्लोरीन की आपूर्ति न होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

438. रक्षोपाय शुल्क का आरोपण जब पाटनरोधी शुल्क पहले से आरोपित हो:

इस मुद्दे की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू होने की स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाया जा सकता है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क पाटन माजिन से अनधिक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित है। धारा 8 ख कुछेक परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क लगाने से संबंधित है। जिन परिस्थितियों में दोनों शुल्क लगाए

जा सकते हैं, वे अलग-अलग हैं । इसके अलावा, धारा 8 ख की उपधारा (3) में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत एक ही समय पर कई शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है । उप धारा 3 में निम्नानुसार उल्लेख है :

"इस धारा के अंतर्गत प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत लगाए गए किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।"

तदनुसार, पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने के बारे में कानून ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है ।

439. तथापि दोनों शुल्कों को एकसाथ लागू न करे जाने की आकांक्षा हेतु विभिन्न निवेदन संबद्ध पक्षों द्वारा किये गये हैं। उन्होंने यह भी सुझाव प्रस्तुत किया है कि, दोनों शुल्कों का एकसाथ लागू किया जाना जनहित में नहीं है। इस विषय का विश्लेषण किया गया। यह एक तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क भी, सीमा शुल्क रोक को बढ़ाते हुए, निपात आयातों से हो रही हानि का विरोध एवं उसको निष्प्रभावित करने हेतु एक व्यापार उपाय है। रक्षोपाय शुल्क टैरिफ को बढ़ाते हुए, घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाने हेतु उपाय है। दोनों ही शुल्कों का अन्य प्रकार्यों के अलावा एक परस्पर उद्देश्य आयातों से हो रही क्षति को निष्प्रभावित करना है। अतः उस अवस्था में, जब वर्तमान व्यापार संरक्षण, संबंधी कार्यवाही, जिस भी प्रकार से, यदि घरेलू उद्योग का संरक्षण करने में असफल है, उस अवस्था में यह अनिवार्य है कि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए एवं जारी रखा जाए। यह अंतर्निहित है कि विविध संरक्षण उपाय तब तक प्राप्य नहीं है जब तक उनकी आवश्यकता न हो।

440. वर्तमान केस में, यह तथ्य विदित है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी आयात में बहुविधि बढ़ोतरी हुई। कम मूल्य पर वर्धित आयातों से गम्भीर क्षति की आशंका विदित है।

441. पूर्व परिच्छेदों में किए गए विश्लेषण यह बताते हैं कि विस्तृत अंतर-पणन के प्रभाव ही वर्धित आयात के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान टैरिफ अवरोध जिसमें पाटनरोधी शुल्क शामिल है, वह प्रचुर मात्रा में आयातों के पारगमन को रोकने हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः बहुविधि व्यापार संरक्षण उपाय आयातों से होने वाली क्षति को निष्प्रभावित करने हेतु तर्क संगत है। तथापि, बहुविधि व्यापार संरक्षण उपाय को सावधानी से प्रयोग करने हेतु आवश्यक है कि वह आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए उपयुक्त है जिससे छोर प्रयोज्यता पर लंबित रक्षोपाय शुल्क तर्कसंगत हो।

442. अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का झुकाव-सितम्बर 2009 तक के विश्लेषित आँकड़ों से दृष्टव्य है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कास्टिक सोडा के मूल्यों के गिरने के कारण कास्टिक सोडा के घरेलू मूल्यों में भी गिरावट आयी है। यह भी देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट विशेषकर उत्तरी अमेरिका में घरेलू मार्केट की अपेक्षा अधिक जल्दी पाया गया। इस असमानता के कारण वर्धित आयात और विस्तृत अंतर-पणन की स्थिति उत्पन्न हुई। यह भी देखा गया कि पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद आयात में वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, घरेलू मूल्यों पर प्रभाव आयातित कास्टिक सोडा से पहले देखा गया। संक्षेप में, कास्टिक सोडा का अंतरराष्ट्रीय मूल्य, घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण हेतु एक निर्णायक घटक है।

443. अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की प्रवृत्ति यह दिखलाती है कि उसमें जुलाई 2009 तक तेजी से गिरावट आयी। उत्तरी अमेरिका का तात्कालिक मूल्य, जुलाई 2009 में गिरकर न्यूनतम US\$ 50 तक पहुँचा और तत्पश्चात, पुनः बढ़कर US\$ 100 के आँकड़े को सितम्बर 2009 में पार किया। इसके पश्चात मूल्य नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। जनवरी 2010 में अमेरिकी निर्यात तात्कालिक मूल्य US\$ 160 से US\$ 180 तक पहुँचा और वही घरेलू संविदा (Contract) मूल्य US\$ 200 से ऊपर ही बना रहा। यूरोपिय निर्यात मूल्य US\$ 180 से 210 की रेंज में रहा। तथापि यूरोप का घरेलू मूल्य यूरो 285-295 अचल रहा। फरवरी और मार्च 2010 में उत्तरी अमेरिका में मूल्य US\$ 200 से ऊपर रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कास्टिक सोडा का समग्र ऊर्ध्वमुखी दौर अभी भी जारी है।

444. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्धित आयातों के कारण आयतनम मापदण्डों पर अत्यल्प प्रभाव पड़ा, परन्तु घरेलू उद्योग की असल बिक्री विक्रय और लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण असर हुआ। यह भी गौर किया गया कि अमेरिका के उप US\$ 100 से कम निर्यात मूल्य ने घरेलू उद्योग को अव्यवहार्य बना दिया है। उद्योग, जून 2009 के पहले लाभ की ओर बढ़ रहे थे तब भी जब निर्यात में बढ़ोतरी हुई और अंतरराष्ट्रीय मूल्य US\$ 130 से 160 (एफ.ओ.बी. उत्तरी अमेरिका), US\$ 200 से 240 (एफ.ओ.बी. एशिया) के परिसर में थे। यह देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य इसी परिसर में या इससे ऊपर पिछले चार माह में रह रहे हैं। हैरिमन चेमसुल लिमिटेड रिपोर्ट द्वारा अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया में मांग एवं क्षमता प्रयोग में काफी लाभ हुआ है। हरिमन कन्सलटन्ट का फरवरी अंक सूचित करता है कि US\$ 75/dst, कास्टिक सोडा के बढ़े हुए मूल्य को अमेरिकी बाजार में स्वीकृति मिल चुकी है। द्वितीय बढ़ोतरी की घोषणा ने

+\$75/dst को स्थापित करने में और अधिक बल दिया। कई उत्पादकों ने +\$80/dst को नामांकित किया है, परन्तु एक उत्पादक ने +\$100/dst को चुना है। संविदा मूल्य, उस वक्त के मूल्य से ऊपर बने रहे। अमेरिका के घरेलू मूल्य महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी पर रहे। यह सभी कारक कास्टिक सोडा उद्योग में लाभ की ओर संकेत करते हैं।

445. क्लोरिन का मूल्य - क्लोरिन का जुलाई 2009 में अमेरिका में तात्कालिक मूल्य \$ 475 से 525 मी टन था जो फरवरी 2010 में गिरकर US\$ 240 से 265 मी टन हो गया। हरिमन चैमसुल लिमिटेड यह रिपोर्ट देते हैं कि क्लोरिन के मूल्यों में काफी गिरावट का दबाव देखा गया है। मार्च 2010 में क्लोरिन का मूल्य US\$ 225 से 250 के बीच था। यह सूचक है अमेरिका में गिरते क्लोरिन के मूल्यों का सूचक है।

446. कास्टिक सोडा के मूल्यों पर क्लोरिन के मूल्यों का प्रभाव-साधारणातया कास्टिक सोडा और क्लोरिन की मूल्य संबंधी गतिविधियां विपरित दिशा में पायी जाती है। कास्टिक सोडा के मूल्यों में गिरावट की शुरुवात दो कारणों से देखी गई। पहला, क्लोरिन की मांग में बढ़ोतरी, दूसरा, कास्टिक सोडा की कुल खरीद में कमी आ जाना जिसके फलस्वरूप क्लोरिन के मूल्य में ट्रन गति से बढ़ोतरी देखी गई। तथापि, क्लोरिन के मूल्य में लगभग आधे या लगभग \$ 250 की गिरावट के कारण कास्टिक सोडा के मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ रहा है। एक बार यदि क्लोरिन का मूल्य घट भी जाता है, तो पुराने मूल्यों का पुनः स्थापित करना असाध्य कार्य है चूंकि यह ईसीयू कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और समय लाभप्रदता पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। अतः कास्टिक सोडा के मूल्यों को बढ़ा दिया गया है जिसके क्लोरिन के मूल्यों की कमी को पाटा जा सके। हरिमन चैमसुल लिमिटेड भविष्य में कास्टिक सोडा की मूल्य वृद्धि को दृढ़ी तरह तर्कसंगत बताते हैं। इन परिस्थितियों के चलते और प्रवृत्ति को देखते हुए यह असम्भाव्य है कि मूल्य उप US\$ 100 के परिसर से कम होंगे।

447. इन मूल्यों के रहते, घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ज्ञात हो कि क्लोरो एलकली उद्योग असाध्य है, जब अप्रैल और 2009 के दौरान घरेलू उद्योग लाभ उठा रहे थे। मार्च 2009 में कास्टिक सोडा के अंतरराष्ट्रीय मूल्य काफी अधिक थे और साथ ही उसके निवल बिक्री भी फिर भी, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट की

वजह से जुलाई 2009 में निवल बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार में कुछ हद तक उतार-चढ़ाव साधारण व्यापारिक घटनाक्रम का हिस्सा है, लेकिन जब यह उतार-चढ़ाव उद्योग को असाध्य करने की स्थिति में आ जाता है तो पाटनरोधी शुल्क के साथ-साथ रक्षोपाय शुल्क लागू किया जाना लोक हित में हो सकता है, तब तक जब तक वह उद्योग को व्यवहार्य बनाए रखने में परिसीमित रहे। वर्तमान केस में अस्थायी रक्षोपाय शुल्क द्वारा सीमा शुल्क बढ़ाते हुए आयातों को कम और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में आकस्मिक कमी से घरेलू उद्योग को संरक्षित किया गया है। तथापि, उत्तरवर्ती गतिविधियों के चलते जब पाटनरोधी शुल्क लागू रहते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कास्टिक सोडा के मूल्य में सुधार देखा गया उस स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना बुद्धिसंगत नहीं है। अतः रक्षोपाय शुल्क को शीघ्रता से लागू किया जाना तो जन हित में है परन्तु अधिक समय तक लागू रखने में कोई जन हित नहीं है।

विकासशील राष्ट्र:

448. विकासशील राष्ट्रों से हुए आयातों के प्रतिशत की भी जांच की गई है। चीन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब तथा थाईलैंड, जिनका हिस्सा वित्त वर्ष 08-09 में भारत में हुए कुल आयातों का 46.6%, 22.4%, 10.4%, 6.53% तथा 7.09% बनता है, को छोड़कर अलग-अलग विकासशील राष्ट्रों का हिस्सा भारत में कुल आयातों के 3% से कम है। अतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक के अनुसार चीन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब तथा थाईलैंड को छोड़कर विकासशील राष्ट्रों के मूल के विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

निष्कर्ष एवं सिफारिश :

449. उपर्युक्त जांच परिणाम को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्धारण यह है कि भारत में तरल रूप में कास्टिक सोडा के संवर्धित आयातों के कारण तरल रूप में कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हुआ है। रक्षोपाय शुल्क की उस राशि को निकालने, जो घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति के खतरे के निवारण हेतु पर्याप्त होगी, के लिए तथा सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए बिक्री की भारित औसत लागत तथा लगाई गई पूंजी पर उचित आय और आयात की औसत पहुंच लागत (मूल सीमाशुल्क, उपकर तथा पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए) पर विचार किया गया है। इसके अलावा, संगणित रक्षोपाय शुल्क में अधोगामी संतुलन किया गया है ताकि अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के हित में घरेलू बाजार में आयातों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जा सके। लोकहित पर भी विस्तार से विचार किया गया है। तदनुसार घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए 15% की दर से तीन माह के लिए (दिनांक 4.12.2009 से 3.3.2010 अर्थात् जब से प्रारम्भिक शुल्क लागू किया गया था) रक्षोपाय

शुल्क न्यूनतम अपेक्षा माना गया है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 28151200 के अंतर्गत आने वाले कास्टिक सोडा तरल के आयातों पर लगाने की संस्तुति की जाती है।

450. चूंकि चीन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब तथा थाईलैंड को छोड़कर विकासशील राष्ट्रों का अलग-अलग हिस्सा 3% से अधिक नहीं बनता है इसलिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक के अनुसार चीन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब तथा थाईलैंड को छोड़कर विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

[फा. सं. डी-22011/47/2009]

इन्द्राणी दत्त मजूमदार, महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2010

Subject : Safeguard Duty investigation against imports of Caustic Soda into India—Final Findings

G.S.R. 306(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof;

PROCEDURE

1. An application was filed Under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial Complex, Vikas Marg, New Delhi-110092 for imposition of Safeguard Duty on increased imports of Caustic Soda into India to protect the domestic producers of Caustic Soda against serious injury and continued threat of serious injury caused by the increased imports of Caustic Soda into India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Caustic Soda into India was issued under Rule 6 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 20th August, 2009 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
2. A copy of the notice was sent to the Governments of exporting countries through their Embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

Domestic Producers

SN	NAME OF UNIT	FACTORY ADDRESS
1	Aditya Birla Chemicals (India) Ltd. (formerly Bihar Caustic & Chemicals Ltd.)	Ghanshyam Kunj, Garhwa Road, P.O. Rehla - 822 124 Distt. Palamau (Jharkhand) Ph.: 06584-262211 / 21 / 262488 Fax: 06584-262205 Email: shyam.gupta@adityabirla.com ajay.todi@adityabirla.com

2	Aditya Birla NUVO Ltd.	Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266 (Gujarat) Ph.: 02876-245711 (EPABX) Fax: 02876-243220/243558 E-mail: irilveraval@adityabirla.com ajay.todi@adityabirla.com
3	Atul Ltd.	P. O. Atul - 396 020 Distt. Valsad (Guj.) Ph.: 02632-233261 - 65 Fax: 02632-233619 / 375 E-mail : vasudev_koppaka@atul.co.in ; pradip_pisharody@atul.co.in
4.	Century Rayon (A Div.of Century Txls & Inds. Ltd.)	Murbad Road, P.B. No.22, Shahad - 421 103 Distt. Thane, Maharashtra Ph.: 0251-2733670 / 79 Fax: 0251-2730064 E-mail: cenray@cenrayon.com saluthra@cenrayon.com
5	Chemfab Alkalis Ltd.	Gnanananda Place, Kalapet Puducherry - 605 014 Ph.: 0413-2655111 Fax: 0413-2655125 E-mail: chemfabalkalis@drroholdings.com
6	Chemplast Sanmar Ltd. (Caustic Chlor Divn.)	Factory - I: Plant-III, Mettur Dam - 636 402 Distt. Salem (Tamil Nadu) Ph.: 04298-230381 - 85 Fax: 04298-230394 E-mail: sp1@sanmargroup.com Factory - II: Melavanjore Village Karaikal, Union Territory of Puducherry - 611 002 Ph:04365-256475 / 76 Fax: 04365-256473 E-mail: vr13@sanmargroup.com
7	DCM Shriram Consolidated Ltd. (Kota & Jhagadia)	1. Shriram Vinyl & Chemical Inds. Shriram Nagar, Kota - 324 004 (Rajasthan) Ph.: 0744-2480991-98, 0744-2480011-17 / 2480907-08 Fax: 0744-2481131 E-mail: tejkrishen@dscl.com 2. Shriram Alkali & Chemicals 749, G.I.D.C. Industrial Estate Jhagadia - 393 110 Distt. Bharuch (Gujarat) Ph.: 02645-226021-23 / 224026-27 Fax: 02645-226037 E-mail: scmittal@dscl.com

8	DCW Ltd.	P.O.Sahupuram – 628 229, Thoothukudi Distt. Tamil Nadu Ph:04639-280231 / 439 / 014 / 281288 Fax: 04639-280611 E-mail: ttn_dcwshpm@sancharnet.in ;
9	Durgapur Chemicals Ltd.	Hanemann Sarani Distt. Burdwan Durgapur-713 215 West Bengal Ph.: 0343-2556668 / 2555762 Fax: 0343-2556667 Email: dcldgp@sancharnet.in akupadhyay@durgachem.com
10	GHCL Ltd.	Village Sutrapada Taluka Veraval Distt. Junagadh - 362 265 (Guj) Ph.: 02876-283401 - 3 / 283409-10 / 283551 - 3 / 280206 Fax: 02876-283483 / 283480 E-Mail : tej@ghcl.co.in
11	Grasim Industries Ltd. Chemical Division	P.O. Birlagram Nagda - 456 331 (M.P.) Ph.: 07366-246760-66 Fax: 07366-246176 / 246097 E-mail: ajay.todi@adityabirla.com ; Kailash.jhanwar@adityabirla.com
12	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.	(1) Baroda Unit: P.O. Petrochemicals - 391 346 Distt. Vadodara (Gujarat) Ph.: 0265-2232681 / 701 / 183 / 2230085 / 3061200 / 6540463 Fax: 0265-2232130 / 2230032 E-mail: general@gacl.co.in marketing@gacl.co.in (2) Dahej Unit: P.O. Dahej, Taluka Vagra Dist. Bharuch –392 130 (Gujarat) Ph: 02641-256315 - 17 Fax:02641-256220 Email: mktdahej@gacl.co.in
13	Gujarat Flouro Chemicals Ltd.	12/A, G.I.D.C. Dahej Industrial Estate, Vagra Taluka, Bharuch Distt. – 392 130 (Gujarat) Ph.: 02641-308062 Fax: 02641-308012 E-mail: jsbedi@gfl.co.in

14	Hindustan Heavy Chemicals (Prop. Kesoram Industries Ltd.)	19, Barrackpore Trunk Road, Khardah P.O. Balaram Dharma Sopan Kolkata-700116 Ph.: 033-25532879/5183, 25839545 / 77 Fax: 033-25533860, 25839218 E-mail: hhcl_fac@vsnl.net hhc_ho@vsnl.net factory@hhckil.com
15	Hindustan Organic Chemicals Ltd.	Harchandrai House, 81, Maharshi Karve Road, Mumbai – 400 002 Ph.: 022-22014269 - 71 Fax: 022-22059533 E-mail: ravimadangeri@hoclindia.com
16	Hindustan Paper Corporation Ltd.	Factory – I: Nagaon Paper Mill, P.O. Kagaznagar Dist.Morigaon – 782 413(Assam) Ph.: 03678-245900 – 10 Fax: 03678-245911 – 13 E-mail: himanish@hindpaper.in adhikari@hindpaper.in Factory – II: Cachar Paper Mill, P.O. Panchgram - 788 802 Distt. Hailakandi (Assam) Ph.: 03845-273080 / 273086 / 273214-6 Fax: 03845-273130 E-mail: kacharya@hindpaper.in
17	HJI – Division of Orient Paper Mills (Prop: Orient Paper & Inds. Ltd.)	P.O. Amlai Paper Mills Distt. Annupur - 484 117 (M.P.) Ph.: 07652-286563 / 178 / 179 Fax: 07652-286290 E-mail: hjigmmco@sancharnet.in hukum_113@rediffmail.com
18	Jayshree Chemicals Ltd.	P.O. Jayshree Distt. Ganjam - 761 025 (Orissa) Ph.: 06811-254319 / 20 / 36 / 254170 Fax: 06811-254384 E-mail: jclgm@jayshreechemicals.com
19	Kanoria Chemicals & Industries Ltd.	Chlor-Alkali (Works): - Renukoot P.O. Renukoot - 231 217 Distt. Sonbhadra (U.P.) Ph.: 05446-252044 / 55 / 75 Fax: 05446-252088 Email: renukoot@kanoriachem.com
20	Lords Chloro Alkali Ltd.	Sp-460, Matsya Industrial Area Alwar - 301 030 (Rajasthan) Ph.: 0144-3202817 / 19 / 2881056 Fax: 0144-2881360 E-mail: jagtar.singh@lordschloro.com

21	Meghmani Finechem Ltd.	CH 1 & 2, GIDC Dahej, P.O. Dahej - 392 130 Distt. Bharuch, Gujarat Ph.: 02642-238025 Fax: 02642-238026 E-mail: mhania@meghmani.com dhruv.joshi@meghmani.com
22	Nirma Ltd.	Chemical Complex Village: Kalatalav Taluka & Distt. Bhavnagar - 364 313 Ph.: 0278-2885301 - 4 Fax: 0278-2885309 - 19 Email: nirma_kalatalav@nirma.co.in
23	NRC Ltd.	Mohone - 421 102 Near Kalyan Distt. Thane (Maharashtra) Ph.: 0251-2270312-5 (9251 from Mumbai) Fax: 0251-2270316 (9251 from Mumbai) E-mail: nrcworks@vsnl.com ; nrcworks@bom7.vsnl.net.in ; dbsjindani@hotmail.com
24	Punjab Alkalies & Chemicals Ltd.	Nangal-Una Road Nayanangal - 140 126 Distt. Ropar (Punjab) Ph.: 01887-220750-53 Fax: 01887-220742 E-mail: paclngl@sify.com
25	Reliance Industries Ltd.	P.O. Dahej, Taluka Vagra Distt. Bharuch - 392 130 Gujarat Ph: 02641-282301 Fax: 02641-283081 E-mail: chappidi.babu@ril.com Jyotindra.m.shah@ril.com
26	Saurashtra Chemicals Ltd.	P.O. Birlasagar Porbandar - 360 576 (Guj) Ph.: 0286-2242479-81 (3 lines) 0286-2205242 (Sales Deptt.) Fax: 0286-2245431 E-mail: gmmrkt@saukemindia.com sales@saukemindia.com
27	SIEL Chemical Complex (A Unit of Mawana Sugars Ltd. - Formerly known as Siel Ltd.)	Charatrapur, Village Khadauli, Sardargarh, P.O. Rajpura, Dist. Patiala, Punjab-140 401 Ph.: 01762-228540 - 48 Fax : 01762-225403 E-mail: info@sielchemical.com
28	Solaris Chemtech Industries Ltd. (Chlor-Alkali & Phosphates Business)	Unit: Karwar, Binaga Karwar - 581307 Distt. Uttara Kannada Karnataka Ph: 08382-230535 / 230638 Fax: 08382-230468 E-Mail: umesh.shenoy@solarischemtech.com

29	Sree Rayalaseema Alkalies & Allied Chemicals Ltd.	Gondiparla Kurnool - 518 004 (A.P.) Ph.: 08518-280006-8, 280053 Fax: 08518-280098 E-mail: sraacmktg@tgvmail.net sraacengg@yahoo.co.in sraaclab@rediffmail.com
30	Tamilnadu Petroproducts Ltd.— (Heavy Chemicals Div.) (Formerly : SPIC Ltd.)	Manali Express Highway, Manali Chennai - 600 068, Tamil Nadu Ph.: 044-25941870 Fax: 044-25941332 Email: tplisd@sancharnet.in ravindran@tnpetro.com
31	Tata Chemicals Ltd.	Mithapur - 361 345 Distt. Okhamandal, Jamnagar (Gujarat) Ph.: 02892-665991-98 Fax: 02892-223361
32	The Andhra Sugars Ltd. (Kovvur/Saggonda)	Saggonda - 534 318 Dist. West Godavari (A.P) Ph.: 08811-253418 / 28 Fax: 08813-231218 E-mail: info.kvr@theandhrasugars.com
33	The Travancore Cochin Chemicals Ltd.	Post Bag No.4004 Udyogamandal P.O. Kochi - 683 501 (Kerala) Ph.: 0484-2545011-20 / 2545583 Fax: 0484-2546564, 2545583 E-mail: salestcc@vsnl.net marketing@tcckerala.com mail@tcckerala.com
34	Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilisers Ltd.	Harbour Construction Road SPIC Nagar Tuticorin - 628 005 Ph.: 0461-2355612 - 13 / 2355615 - 16 Fax: 0461-2355376 Email: ttn_ank@sancharnet.in headworks@tacfert.com
35	United Phosphorus Ltd.	750 G.I.D.C., P.B. No. 9 Jhagadia - 393 110 Distt. Bharuch (Gujarat) Ph.: 02645-226011 - 15 Fax: 02645-226017

IMPORTERS

- Abhay Chemicals Limited ,150 Gayatri Chambers, RC Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390005, Gujarat
- Albright Wilson Chemicals Limited, Pheonix House, "A" Wing, 4th Floor, 462x,x xSenapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai- 400013

- c. Arvind Mills Limited, Naroda Road, Ahmedabad 380025, Gujarat.
- d. Birla Cellulose Limited , Birla Dham, Kharach, Kosamba, R.S-374120, District Bharuch, Gujarat
- e. Central Pulp Mills Limited Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi – 110002
- f. Deepak Nitrite Limited, 4/12, GIDC Chemicals Complex Nandesari 391340 Gujarat
- g. Godrej Sopas Limited Eastern Express Highway Vikhroli (East), Mumbai 400049
- h. Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited .P O Narmadanagar 392015 Bharuch, Gujarat
- i. Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited ,P O Fertilizer nager ,Vadodara Gujarat
- j. Indian Farmer Fertilizer Coop. Limited ,P O Kasturinagar 382423
- k. Indian Oil Corporation Limited, Gujarat Refinery, P O Jawaharnagar Vadodara – Gujarat
- l. Jaysynth Dyechem Limited ,301, Sumer Kendra, Pandurang Budhkar Marg Worli, Mumbai 400 018
- m. Link Pharma Ltd, B-2, 6th Floor, Ramakrishna Chambers ,Productivity Road , Alkapuri ,Baroda 390005, Gujarat
- n. Meghmani Organics Limited, 188/184, Phase II, GIDC Industrial Estate, Vata , Ahmedabad 382445 ,Gujarat
- o. Narmada Chemature Petrochemicals Limited, 2nd Floor, Skyline Building ,Near Bharuch Railway Station ,Bharuch Gujarat
- p. Nirma Limited ,Nirma Bhavan, Ashram Road Ahnedabad Gujarat
- q. Pab Chemicals (P) Limited, Surya Kiran Complex, 1st Floor, Old Padra Road, Post Bag No. 4059, Baroda –390005, Gujarat
- r. Rama News Prints & Papers Limited, Village : Barbodhan – 395005 Taluka Olpad Distt: Surat, Gujarat

- s. Rubamin Limited ,Synergy House ,Subhanpura Baroda – 390023,Gujarat
- t. Sabero Organics Limited,A-302, Phoenix House 3rd Floor ,462, Sanapati Bagpat Marg ,Worli (East) Mumbai 400013
- u. Torrent Gujarat Biotech Limited th Floor, Sri Ram Chamber Opp. Circuit House,RC Dutt Road ,Baroda – 390005 Gujarat
- v. Transpek Silox Industries Limited ,Kalali Atlandra Road,Vadodara – 390012, Gujarat
- w. National Aluminium Company Limited,NALCO Bahvan ,E 37 Site B, Surajpur Industrial Area ,Gautam Buddha Nagar (UP)
- x. Cyanides & Chemicals Company ,Prop. Hindustan Development Cor. Ltd Corporation Limited,65 Free Press House,Nariman Point ,Mumbai 400021
- y. Demosha Chemicals Limited ,105 A Mittal Towers ,210 Nariman Point Mumbai 400021
- z. Hitsu Industries Limited,Plot No. 306/2, Phase II,GIDC, Vapi Gujarat
- aa. Shri Ramchandra Straw Products Limited, Village Vijaypur ,Tahsil Bellari Moradabad (UP)
- bb. Libra Foams ,Div of S B Distributors Limited,E 37 Site B, Surajpur Industrial Area ,Gautam Buddha Nagar (UP)
- cc. Adani Wilmar Limited ,Navinal Tiand ,Mundra – KATCCHH,Gujarat
- dd. Adani Exports Limited,Adani House, Shrimali Society ,Mavarangpura Ahemedabad ,Gujarat
- ee. Daurala Organics Limited ,Humalaya House ,Kasturba Gandhi Road New Delhi
- ff. Bilag Industries Pvt Ltd ,Plot No 306/3, Phase II,GIDC VAPI, Gujarat
- gg. Shri Ramchandra Straw Products Limited ,Village Vijaypur Tahsil Bellari ,Moradabad (UP)
- hh. Libra Foams ,Div of S B Distributors Limited ,E 37 Site B, Surajpur Industrial Area ,Gautam Buddha Nagar (UP)

- ii. Daurala Organics Limited ,Humalaya House ,Kasturba Gandhi Road New Delhi
.P/L Nayapalli,Bhubaneshwar – 751013,ORISSA
- jj. Harish Kr. & Company ,23- Anant Building 21,S Gandhi Marg, Mumbai 400002
C J Shah & Co,105 Bajaj Bhawan,Nariman Point ,Mumbai 21
- kk. Hindustan Lever Limited,Hindustan Lever House,165/166, Backbay Reclamation
,Mumbai 400 020.
- ll. Hindustan Link & Resins Limited ,Bilakhia House, Muktanand Marg Chala –
Vapi, Gujarat
- mm M/s Vedanta Aluminium Limited, Via Vishvantpur, P.O. Lanjigarh, 766027,
Dist. Kalahandi, Orissa
- nn. Aluminium Association of India, 118, 1st Floor, Ramanashree Arcade, 18, M.G.
Road, Bangalore-560 001 representing Hindalco Industries, NALCO, Vedanta
and Bharat Aluminium Co.

Exporters

- oo. Asahimas Chemicals PT, 9th Floor, Summitmas I, Jl. Jend, Sudirman Kav. 61 –
62, Jakarta, 12190, Indonesia
- pp. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Main Office Building A, Jl. Raya Surabaya –
Mojokerto Km. 44, Mojokerto 61301, Jawa Timur, Indonesia
- qq. PT Sulfindo Adiusaha PT. Sulfindo Adi Usaha 14th Floor, Ratu Plaza, office
Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9 Jakarta Jakarta 10270 Indonesia
- rr. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk .BII Plaza, Menara II, Lantai 7, Jl. M.H.
Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia
- ss. Formosa Plastics Corporation 201, Tung Hwa North Road Taipai Taiwan
- tt. Dow Chemical Dow Hellas SA Lavrion Site Thorikon Lavrion TK 19500 Greese
- uu. Solvey Fluor GmbH Brueningstrasse 50 Zip Code : D-65926 Frankfurt am Main
Germany
- vv. Bayer AG Bayer MaterialScience AG Communications, Building K12 Kaiser-
Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Germany

- ww. BASF AG ZOI - D 100 D-67056 Ludwigshafen Germany
- xx. Enichem SpA Piazzale Mattei, 100144 Roma – Italy
- yy. Qatar Vinyl Company Q.S.C. Post Box No. 24440 Doha, Qatar
- zz. Hanwha Chemical Corporation 100-797, Hanwha Building, 1, Jung – Ku, Seoul Korea RP
- aaa. DC Chemicals Limited Oriental Chemical Building 50, Sogong – Dong Jung – Gu Seoul Korea RP
- bbb. Shanghai Chlor Alkali Chemicals Wu-Road No. 4747, Shanghai City 200 122 China-PR
- ccc. Sinopec Qily Petrochemical Co Limited Qilu Office Building, High Tech & Industrial Development Zone, Zibo, Shandong China PR
- ddd. Wuhan Golden Fortune Technology & Trade Co., Ltd. International Enterprise Center, No2# Guanshan Road, Wuhan, Hubei, China
- eee. Tianjin Kaiyi Chemical Factory No. E7-205 Binhai Finance Zone, No. 20, Guangchang East Rd., Teda, Tianjin, China
- fff. Tianjin Xibeier International Co., Ltd 21c Yitingyuan, No 22, 6th Latitude Road, Hedong District, Tianjin, China
- eee. M/s Tricon Energy Limited, 777 Post Oak Building, Suite 650 Houston, Texas, 77056, USA
- fff. M/s Basic Chemical Solutions Far East Pte Ltd, 51 Godhill Plaza, # 21-08/09, Singapore-308900.
- ggg. M/s Vinythai Public Co. Ltd., 14th Floor, Green Tower, 3656/41 Rama IV Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Exporting Nations:

- a. European Union
- b. Germany
- c. Greece
- d. Indonesia
- e. PR China
- f. Qatar

- g. Republic of Korea
- h. Saudi Arabia
- i. Taiwan
- j. Thailand
- k. USA

3. Questionnaires were also sent to all known domestic producers, importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.
4. After taking into account the time limits for completing the investigation within the period provided under law, requests for extension of time were allowed and the parties concerned were accordingly informed.
5. After expeditious conduct of investigation preliminary findings were issued on 15th October 2009. The Director General (Safeguards) recommended safeguard duty at the rate of 20% (twenty percent) ad-valorem to be the minimum required safeguard duty to protect the interest of domestic industry and is recommended to be imposed on imports of Caustic Soda classified under sub-heading Nos. 2815 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975” into India. Based on the preliminary findings a safeguard duty was imposed @ 15% on 4th December, 2010 vide notification no. 131/2009-Cus dated 4.12.2009. The preliminary safeguard duty is valid up to 3rd March, 2010 unless revoked, superseded or amended earlier.
6. A public hearing was held on 8th December 2009, notice for which was sent on 30th October, 2009. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties.
7. Another Public Hearing was held on 28th January, 2010. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties.
8. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

9. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places without referring to specific name of the interested party for the sake of brevity.
10. The information presented by domestic producers was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers and by the records maintained by them, to the extent considered necessary. Further, the cost data has also been verified and certified by cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

Views of the domestic producers and other interested parties:

Views of Applicants

11. The combined capacity of the Indian producers is more than sufficient to meet the present and potential demand of the product and there is no basis in the allegations that the imports were necessitated due to lack of sufficient production in the country. On the contrary, the sole reason for the current spurt in imports is materially lower prices.
12. It has been established that the product is being dumped by the foreign producers from a number of country because of Anti Dumping Duty on more than 11 countries.
13. Large numbers of importers and exporters have not filed any questionnaire response. The import from the countries from where the foreign producers have filed exporters' questionnaire response merely contributes to 14% of the total imports. Vedanta has not filed questionnaire response whereas they have made allegations regarding non supply of material to them by Indian producers leading to taking recourse to imports. These allegations are simply baseless in absence of any evidence.
14. The surge in imports and decline in import prices has been so significant that the Indian producers have been forced to resort to unprecedented price reduction. Further due to surge in low priced imports of caustic soda, domestic industry is suffering from severe decline in profitability.
15. The analysis of spot Vs. Contract sale of domestic producers shows that the increase import has affected the spot sale of DI. There is not much effect on the Contractual sale.
16. Import price reported to Customs authorities are not the real price at which goods has been exported.
17. There is huge surplus capacity in North America, Europe and China as per Harriman Chemsult Ltd..
18. Unprecedented increase in import. The average monthly import between April to Sep.' 09 is 51586MT/month.
19. The expected import arrival will impact the domestic market. They submitted data from Chlor-Alkali periodical Harriman Chemsult Ltd.

20. Unforeseen circumstances happening around Sep-Dec. 2008 leading to decline in global demand of the product. There was sudden increase of C.U. in USA without increasing demand of Caustic due to increase in chlorine demand. This resulted into fall in prices of Caustic.
21. The goods produced by the domestic industry are identical to the goods imported in respect of all essential characteristics viz. physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.
22. Profile of Indian producers of caustic soda is well depicted in the table below:

	Production(MT)	Share in Indian production(%)	Production per company(MT)
5 companies	590627	36	118125
13 companies	1114397	68	85723
Rest of the industry	544746	32	24761
Total Industry	1659143	100	47404

23. From the above table, it is evident that 5 companies accounted for about 36%.

These were those companies whose individual production was significant and whose collective production amounted to 36% of Indian production. That is why the petitioner provided information about them. However, Director General (Safeguards) desired information in respect of more companies and accordingly information was provided in respect of those remaining companies whose individual production was significant. The collective output of all the companies was thus 68% of Indian production. Remaining companies are those companies whose individual production is quite low.

24. Imports have increased in relation to sales of the domestic industry. Further, imports have increased in relation to production in India and also consumption in India. It is evident from the corroborative data furnished that imports of caustic soda have shown increase in absolute terms and the increase is sharp & significant enough and covers the most recent period. The increase in import with respect to sale, production and consumption is in Q4 of 08-09 and Q1 and Q2 of 09-10.
25. The relevant factors for determination of existence of serious injury or threat of serious injury are rate of increase of imports, share of the domestic market taken by increased imports, change in level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits & losses and employment. It is evident from the Quarterly data submitted that the market share of the Indian producers and demand in India has steeply declined & consequently market share of the imports and demand in India has steeply increased. Further, market share of the domestic industry has declined

in a situation where its capacity utilization has also declined. All these factors reflect serious injury to the domestic industry.

26. The sales of the domestic industry were showing an increase. Sales however declined steeply in Q3 of 2008-09. Even when the same have been increasing thereafter, they are still substantially lower than the corresponding previous levels. Production of the domestic industry has declined. Whereas, production was increasing till Q2 of 2008-09, the same is much lower than the levels registered in Q2, 08-09. This is in spite of the fact that the demand for the product has shown significant increase.
27. While decline in profitability in Q3, 08-09 can be attributed to recession and global decline in prices and profitability, the subsequent decline in profitability to such an extent that the domestic industry posted financial losses in Q2 of current year is clearly due to increased imports.
28. Employment when compared with installed capacities shows that the employment has declined whereas capacities have increased. Productivity of the domestic industry has improved. Even when the domestic industry is making all efforts to improve productivity, the profitability, which was improving till Q2 of 08-09, has declined severely thereafter.
29. Foreign producers are having significant surplus capacities. These surplus capacities are not expected to decline, given significant investments in this product and capital intensive nature of the product under consideration. Thus, the only option available to the foreign producers is to produce and sell as much as possible. This has resulted in excessive exports by them to India at abysmally low prices. This fact is evident from the significant fall in the prices of caustic soda from above US \$ 1000 to below US \$ 75 per MT.
30. Comparison of cost of production with the selling price shows that barring one instance in Q4 of 2007-08, whereas the cost of production has always remained lower than the selling price, the selling price has now declined even below cost of production. Further, even when the selling price was above cost of production even at the peak of recession, now when the demands are increasing globally and domestically with industry improving worldwide, so significant has been decline in the caustic soda prices for the Indian producers that the same have gone below the cost of production levels.
31. The serious injury is not caused due to other factors. The product is already attracting antidumping duties & the domestic industry is already protected against unfair dumping to the extent the dumping and injury earlier established. Further, factors like changes in the patterns of consumption, productivity, developments in technology and export performance etc are not causing any injury. In view of this, the only logical conclusion that can be drawn is the injury to the domestic industry has been caused by the increased imports at low prices. The causal link between increased imports and consequent serious injury is well established.
32. So far as endeavors towards a viable adjustment plan are concerned, the domestic industry plans conversion of mercury cells to membrane cells resulting in reduced power consumption, reducing salt prices through increasing yield/productivity of the salt producers, reduction in freight cost, productivity improvement,

optimization of production capacities, increased use of chlorine/effective disposal of chlorine, capacity expansion etc. The allegations by various interested parties that the adjustment plan is not a viable one, are baseless. In number of cases, the DG(SG) has ruled that an adjustment plan encompassing the above mentioned characteristics is a viable plan.

33. Imposition of even 20% safeguard duty will not cause any adverse impact on the user industry viz aluminum & paper & pulp industry as is evident from the data provided. Therefore, it can be deduced that public interest will not be adversely impacted even after imposition of safeguard duty on caustic soda. The claim that the conditions of user-industry would deteriorate on imposition of safeguard duty, is without substance and wholly unsubstantiated.
34. As regards the question, that imposition of both anti-dumping and safeguard duty simultaneously implied addressing the same injury twice, is concerned, all that is required is to impose/administer the two duties in such a manner that the relief is not given twice. This principle has already been applied by the DG (SG) in several other cases.

Response of Applicants to the points raised by interested parties

35. **Country self sufficient**— The combined capacity of the Indian Producers is more than sufficient to meet the present and potential demand of the product in the Country.
36. **There has been previous history of dumping** --.The current injury to the domestic industry is in spite of this anti dumping duty as they are making sells below the bench mark and by reporting the imports from a number of new sources. Large numbers of importers and exporters have not filed any questionnaire response. Those who have filed merely contribute to 14% of the total imports! Due to the surge in import and decline in import prices that Indian producers have been forced to resort to unprecedented price reduction. Due to surge in low priced imports of caustic Soda, domestic industry is suffering from severe decline in profitability.
37. **Spot vs Contract price**: Increased imports are actually being consumed by those customers who are buying caustic soda on spot basis. The increased imports were so far not causing significant price injury in respect of contract sales. The impact of increased imports at that time was being felt more in spot market. The market share of imports is substantially higher in the spot market.
38. Petitioner submits that prices of Caustic Soda in major global markets, including but not restricted to US, Asia, and Europe declined suddenly and too sharply.
39. The alarming difference between the price at which material is being exported from various countries and the price at which material is being reported for customs clearance in India is wholly unexplained by any associated expenses and profits.
40. The volume of imports into India is unprecedented not only in terms of imports in the most recent period, but also in terms of historical levels.
41. The expected/potential imports of caustic soda in India as reported in Hariman Chemsult reports for the months August and September 2009, were higher in

volume as compared to imports which had already been reported. Also, majority of the shipments were from USA

42. Unforeseen Circumstances:

43. Oct 2008: Showing increase in capacity, Less exports creating more spot demand for caustic soda, Surplus inventories from China heading towards US, Upward pressure on prices, Due to plant maintenance, drop in production and inventories in UK, low Chlorine demand.
44. Nov 2008: Flat demand for Caustic Soda, lower off take from Vinyl, Pulp & Paper and PVC sector, Coastal market oversupplied with Asian imports, UK also witnessing fall in Chlorine demand, production cutoff in chlor-alkali plants, North America also experiencing increase in PVC exports due to less demand in domestic market.
45. Feb 2009: Caustic production goes to the lowest record level in USA, Down ward pressure on prices tank owners eager to move their higher priced inventories before the fall in price, increase in imports and decrease in exports, UK witnessing higher caustic supply due to lifting up of force majeure, Increase in inventories in US due to improvement in caustic soda production.
46. Mar 2009: Oversupply of caustic soda more than demand, world wide, lower off takes of Caustic Soda from consuming sectors, Very less demand of US produced caustic in export market, fulfilling their demand by lower priced solid caustic from Asia.
47. Apr 2009: Further fall in Caustic Soda demand and excess supply of Caustic Soda in European market, Increase in caustic inventories in UK, Drastic fall in Chlorine demand.
48. May 2009: Chlorine price increase announcements, North East experiencing Very low caustic soda demand, downward pressure on prices, In spite of the reduced production, caustic soda stocks remain at a historically high level, highlighting the significant drop in demand. Although demand is on the weaker side, and pricing remains under pressure, there has been an increase in export activity over the past month, Fall in Chlorine production.
49. Jul 2009: July has seen no reversal in market fundamentals; consumption is low compared with the same time last year, while inventories remain at a high level, as a result of which UK producers becoming active in export market, Supply continues to exceed demand in most of the caustic soda markets all over the world, In the West Coast, domestic prices have declined marginally to INR 17000-18000/dmt excluding tax and delivery due to intense competition from lower priced import material. It is reported that several imported parcels amounting to 50,000 lmt from US is arriving in July, priced at \$170-190/dmt cft. The parcels are destined for alumina and soap producers and for general distribution. Imports from China and Middle East have virtually disappeared.
50. The application in the present case has been filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of Indian Producers. Information with regard to serious injury was provided by DSCL, Jhagadia; DSCL, Kota; Grasim Industries Ltd.; Gujrat Alkalies, Baroda; Gujrat Alkalies, Dahej. Upon filing of petition, the Director General directed information for more companies. Hence Kanoria; Indian Rayon; Bihar Caustic; DCW; SIEL; Gujarat Fluorochemicals

- Ltd.; IPCL and PACL also filed the required information. . The collective output of all these companies is thus 68% of Indian production.
51. Imports of Caustic Soda has increased in absolute terms, from 1,86,347 in 2008-09 to 309,333 in 2009-10. Imports have increased in relation to sales, production and consumption in India.
 52. Domestic Industry is suffering serious injury as the rate of increase in the imports is quite significant, Market share of the Indian Producers in demand in India has steeply declined and that of imports has steeply increased. Domestic Industry is witnessing steep decline in sales, production, Capacity Utilization, Profitability, Employment.
 53. Presence of Freely disposable production capacities with the foreign producers. [Source: Harriman Chemsult Ltd. and Chlor Alkali monthly report published by CCAON]
 54. Imports of caustic soda in the Indian market are causing significant price undercutting to the domestic industry.
 55. Net sales realization of the domestic industry has declined, the selling price has now declined even below cost of production. The reasons for these declines can be seen in the decline in the import price in India and the decline in the prices of caustic soda in the global market.
 56. Even when ECU costs were declining after March 2009, the profitability steeply deteriorated to such an extent that the domestic industry suffered significant financial losses.
 57. The return on capital employed also showing deterioration.
 58. Causal link gets established in the light of the fact that no injury has been caused to the Domestic Industry on the basis of factors other than increased imports. As far as Commissioning of new capacities in surplus areas is concerned, it has been submitted by the petitioner that Indian Producers are selling caustic soda in East and South from plants located in West. Caustic soda is now being shipped by rail and sea. Therefore, locational issues are now longer preventing the Indian Producers from selling caustic soda throughout the Country.
 59. **Adjustment Plan:** the Petitioner has provided a viable adjustment plan which focuses on Cost reduction, Optimum Utilization of existing production capacity, Capacity Expansion to cater the growing demand, Effective disposal of Chlorine.

Point wise Reply to issues raised by the user industry

60. Anti dumping duty is already in force and therefore safeguard duty cannot be imposed : An analysis of Sec. 8(b) and 9A(1) of the Customs Tariff Act nowhere provides for non-imposition of anti-dumping duties or safeguard duty when the other duty is in place. Even in the case of phenol, safeguard duty was already in force and anti dumping duty was imposed above it.
61. Alleged Deficiencies in the petition: The Director General has, in notice of Initiation, found that the petition was duly documented and justified initiation of investigations.
62. The petition contained sufficient information with regard to volume, value and price of imports.

63. LMT and DMT: the petitioner has assessed import volumes by considering that all those unclear import transactions possibly relates to import volumes in lye form only and were not converted into DMT. even the modified data shows significant surge in imports. It is submitted that the Director General should satisfy herself with regard to accuracy of information, for which necessary verifications may be conducted. Such verifications need not be limited to Indian parties and can extend to foreign suppliers as well.
64. Information on adjustment plan is relevant and necessary for determining the nature and quantum of relief. It is not relevant and necessary for a decision on whether to conduct safeguard investigations.
65. Petitioner has not provided complete information regarding Chlorine, hence making it difficult to assess the true position of Indian industry:
66. The statement is factually incorrect. Full information has been provided. Without prejudice, should any further information to be required; the petitioner will provide the same.
67. Careful examination of import data is required as in most of the transactions, the import data do not classify the product type: The petitioner provided best available information.
68. Different data at different places as to increased imports, change in level of sales and production: The Director General may consider the most appropriate information, having regard to various information on record. The Director General is not an adjudicating authority. The Director General has called information from several sources and is required to come to their own conclusion.
69. Costing information for chlorine has not been supplied: Sufficient information has been provided.
70. Petition does not contain any information as to the ECU. However, Domestic Industry has submitted inaccurate data, when the interested parties raised this issue: There is no reasonable justification in the arguments. Further, even if it is assumed that the domestic industry has provided ECU data on being pointed out by the interested parties, it is not understood should the same vitiate factual and legal position. Further, the mere fact that information has been provided subsequently does not establish that the same is inaccurate.
71. "Revenue realized per ECU" should be considered. Caustic soda price alone is incorrect: The domestic industry has in fact, provided information with regard to selling price, cost of production and profit/loss for caustic soda as also ECU cost of production, ECU sales realization and ECU profit/loss.
72. Price is not a consideration in the rules: Price is the consideration in so far as the question of increased imports is concerned.
73. No consolidated verification data for the industry as a whole, in the public file: There are no such legal requirements.
74. Authority has taken selective resort to the post POI data (like on ECU sales realization, but has excluded recent data showing improvement in the position of Domestic Industry): The argument is without basis. Firstly, there is nothing like period of investigation in a Safeguard case. Secondly, the Authority has considered first quarterly data and thereafter-monthly data. Such consideration is consistent in the finding and is consistent with the law.

75. Reference to US lamb case: competent authority cannot rely exclusively on data from most recent past but must assess that data in the context of the data for the entire investigative period.
76. It is not the petitioner's case that the Authority should rely upon only on most recent data. In fact, if data is considered for the entire period, it clearly establishes a surge in import and serious injury being caused to the domestic industry.
77. The counsel for the AMAI has admitted that data on volume and price of imports is incorrect: Bill of entry is a legally admissible evidence hence can be relied upon to determine the import volume and price. Mere production of bill of entry is insufficient to establish that the goods were indeed imported at these prices. The importer must establish genuineness of the prices by establishing how these prices compared with the prevailing market prices.
78. Decrease in capacity utilization is due to severe chlorine inventory constraints: The domestic industry has not been forced to curtail production due to lower offtake of Chlorine in its past history. In fact, in general Chlorine price gets governed by caustic soda prices and in general has inverse relationship. However, in the current period, the prices of both caustic soda and chlorine suffered.
79. Price undercutting is based upon inaccurate data. Correct data for cost of power is Rs. 4.705 per KWH in 2008-09: Cost of power is not related to price undercutting. Price undercutting is related to domestic industry selling prices and import price, whereas cost of power is relevant to determination of cost of production.
80. Abnormal power restriction imposed by Punjab Electricity Board is responsible for reduction in Capacity Utilization: PACL, financial results sep. 09: The argument is without basis. comparison of Grasim production over the period shows that the change in production of Grasim is far insignificant as compared to the change ;due to increased imports pointed out by the petitioner
81. Capacity Utilization has been lower due to factors other than imports otherwise units near the coast should have lower Capacity Utilization: The argument is factually incorrect. Capacity in DCM Sriram has suffered, where no capacity additions took place. If the argument of these parties was true, the prices of Caustic Soda should have never declined in Northern India. Imports of Caustic Soda occurs primarily at coastal region. However, prices of Caustic soda increases and declines even in North India with the changes in the import and in the international prices.
82. In order for increase in imports to be the cause of injury, the increase ought to have preceded the decline and not vice- versa: Imports have in fact, preceded the decline as would be seen from the trend of month wise volumes.
83. NALCO has a huge pending import order, which is well above the benchmark anti-dumping rates, imposition of safeguard duty would lead to payment of an additional sum of approximately Rs. 4,768 PDMT. Thus affecting the Public interest: Information of the above established lack of public interest. On the contrary, sky rocketing profitability of the Aluminium industry over the past, clearly establishes insignificantly adverse impact on the Aluminum industry.

Indian producers have seen profitability position of NALCO, HINDALCO and Vedanta.

84. The trend of increased imports did not coincide with the declining trend of the relevant injury period: The argument is factually incorrect. Firstly, increased imports and declining trends in the performance of the domestic industry have happened in the same period. Secondly, given the volume of imports per consignment, it is natural that some impact of the imports would be felt in the immediate succeeding period.
85. Loss in chlorine should not be attributed to the injury in caustic: It is an admitted fact that chlorine is a by-product and profitability of caustic soda operations must be determined after making allowance/credit for chlorine. The same has been followed in the present case as well.
86. Decrease in profit is due to decline in capacity utilization: There is indeed an admission by the interested parties that capacity utilization of the domestic industry declined. However, as the information on record would show and as the preliminary findings notified by the Director General recognizes, the decline in profitability is primarily due to decline in selling prices of caustic soda.
87. Vedanta mail issue: In its arguments Vedanta has referred to certain e-mails sent to Domestic Industry however, has not disclosed the name of the company to whom enquiry was sent, nor has Vedanta provided any information with regard to replies received by the company from some of the Indian suppliers, even at the insistence by the DG safeguards in this regard.
88. In view of the approach adopted by Vedanta, the petitioner Association wrote to the Indian producers who could have been approached by Vedanta. Since the Indian producers contacted by Vedanta are not known to the petitioner, the request was sent to those Indian producers whom petitioner Association could imagine having received an enquiry from Vedanta.
89. Problems faced by Indian Producers: Despite of an agreed date of supply company delayed opening of Letter of Credit. There are instances when in spite of having placed an order for firm quantity the company had delayed procurements of material, or has simply cancelled a confirmed purchase order.
90. In spite of such a large requirement, Vedanta has not made any significant efforts in procuring the raw material from domestic sources. On the contrary, the entire approach of Vedanta appears extremely casual as is evident from the enquiry received by the company itself.
 1. Orders at short notice.
 2. Evidence showing that Vedanta has been bargaining hard on prices with the domestic producers, in the pretext of cheaper imports.
 3. Evidence showing that even after seeking offers through written communications, Vedanta has either not responded at all to the offers made by the Indian Producers, or kept prolonging the decisions, that too in a volatile market like the present.
91. Import price: On the analysis of month-wise data of Korean customs, it would be seen that even when volumes match, there are too significant difference in the prices. Petitioner is aware that one price is FOB and other is CIF. However, the difference is far higher than the associated freight.

92. Increased imports and Data for updated period – In the light of Argentina Footwear case, it becomes essential to submit data for the updated period in order to show most recent position.
93. CRISIL Report: Imports of Caustic Soda had witnessed significant increase during the relevant period;
94. Domestic prices were adversely impacted because of import price;
95. At some point in time, producers have restricted production – in this regard petitioner submits that production of Caustic Soda (or any other commodity for that matter, in general) is governed by two factors – (i) confirmed orders from the customers; and (ii) production in anticipation of order (also known as “production to inventories”). Petitioner submits that the ratio of production against confirmed orders vs. and anticipated orders varies from period to period. While Indian producers have never allowed production to suffer in case of confirmed orders, production of Caustic Soda made without confirmed orders naturally gets regulated depending on market situations.
96. Published results not showing decline: Petitioner submits that published results cannot be relied for the present purpose as:
- Published results are in respect of a particular segments, whereas the investigation is in respect of product under consideration;
 - Even in Caustic Soda, the product under consideration is only in lye form. Caustic Soda in solid form is beyond the scope of the present investigation.
97. The allegation made by the domestic Industry regarding misdeclaration of value based on five alleged transactions cannot be raised before the DG, Safeguard who has no jurisdiction to determine the veracity of the said allegation: Petitioner has not asked Director General to investigate the matter. Petitioner has merely drawn kind attention of the Director General to establish that the correct volume and price of imports, as the same is directly relevant to the present determination.
98. Chlor-alkali business globally has been historically following a cyclical path of 5 stages over a 2-3 year time frame : Unlike the present situation, as stated in the submissions made before, imports of caustic soda have never seen the kind of surge as has been seen now. While the Indian Producers have to face the normal market situations, the concern of the Indian Producers is about the sudden & significant surge in imports, which has threatened serious injury to the domestic industry.
99. Out of the 13 manufacturers referred to in the Initiation Notification, confirms that only three of them have suffered any losses: The Director General is required to consider “domestic industry as a whole” for assessment of serious injury. The Director General is not required to consider individual units. Even if it is admitted that one company has done quite well, it implies that rest of the domestic industry has done worse than what the aggregated data shows.
100. Out of the 130 import consignments of Caustic Soda Lye imported during the period April 2008 to June 2009, the proof submitted by respondent’s clients shows that:
- Approx. 10% of the 130 entries have been manipulated and are incorrect.

- ii. Import quantity was lower by 22% as compared to figures submitted by petitioner.
- iii. Import prices were higher by 28.80% as compared to figures submitted by petitioner.

101. Petitioner has since obtained a clarification from IBIS, which has been made available to all. This makes it evident that the petitioner has not withheld any information. This further makes it evident that the petitioner is with clean hands before the Director General and the interested parties are attempting to mislead the Director General without doing sufficient exercise at their end.
102. Data of Annual Reports which are non-confidential have been considered as confidential: Petitioner has not claimed any confidentiality on annual reports. In fact, interested parties have repeatedly referred to annual reports.
103. Imports are routine in nature for filling the demand-supply gap: information provided by the petitioner shows that the Indian Producers are having sufficient capacities, which are lying underutilized.
104. Opportunistic cost and profit determination : Treatment of Chlorine as a by-product and Co-product: The fact that Caustic and Chlorine are co-produced is well known to the Authority. In fact, the information provided by the petitioner clearly establishes this fact. Further, since both selling price of caustic soda and ECU realization has been considered, nothing more is left out in this regard.
105. Reliance upon IBIS Data: The IBIS data is a reliable data and has been used extensively by the various domestic industries in safeguard duty investigations. The data is also being used and relied upon by Designated Authority on Anti Dumping. In order to make the entire process transparent the original IBIS data as well as calculated data had been made public and provided to all the parties.
106. Regarding method of normalization incase of 12 BOE : Even though we have submitted import data as per the logic given by interested parties, we submit that data needs to be normalized as per statistical methodology as these shows abnormal deviation.
107. caustic- manufacturers are not able to supply to end users: As per the preliminary findings, pulp and paper industry is the industry which has more share in consumption of Caustic Soda. However, they have decided not to participate/oppose the investigations. Had it been a case where Caustic Soda manufacturer were not able to supply to these segments at competitive prices, they would have joined the investigations and opposed imposition of safeguard duty. Similar is the case for all other sectors, which constitute around 80% of the consumers of Caustic Soda.
108. Most of the Aluminium factories are located in the same region. Hindalco meets its requirement of Caustic Soda from domestic procurement. Nalco also meets most of its requirement through domestic procurement. Vedanta claims, it meets most of its requirements from imports (it is relevant to point out that BALCO and MALCO were meeting their requirements from domestic sources only). These patterns of procurement of Caustic Soda had been in place from past few decades. The pattern changed only now when the international prices drastically fell down. When international prices declined, the domestic consumers shifted to imports

which led to lowered sale and downward production even after increased production capacity. Hence, the contention that the domestic industry is not able to supply is not correct.

Comments of Arab Republic of Egypt

109. The share of Egyptian imports of the product is negligible. The Egyptian imports should not fall within the scope of any safeguard measure that may be imposed.

Comments of the European Union

110. The investigation should not have been initiated given that safeguards affect all imports, irrespective of their origin, and especially because contrary to anti-dumping and anti-subsidy they target fair imports, the WTO standards required to impose measures are extremely high. This investigation was initiated without sufficient evidence of serious injury and no causal link could be established with the increase of imports.
111. Preliminary findings are not based on objective evidence.
112. The Article 4 of the WTO Agreement on Safeguards as well as the Indian Law defines the domestic industry for the purpose of a safeguard investigation to mean the producers as a whole or those whose collective output constitute a major proportion of the total domestic production whereas the complainant industry only represent 35% of the Indian production.
113. The commission requested that the investigating authorities to base the analysis either on the situation of the sole complainant or on the totality of the Indian producers.
114. The Indian investigating authority analyses imports and injury data on quarter basis "in order to obviate effects of seasonal variation, if any". However, no justification has been provided as to the investigating authority's decision to replace the analysis based on years in application to one based on quarters.
115. There is no serious injury as the share of domestic market taken by the increased imports was barely above 1% i.e. from 61.98% in 2005-06 to 60.79% in 2008-09.
116. The price of 14,574Rs./DMT of imports for the quarter 2009-10 is in line with average for previous year.
117. Sales and production increased between January and June 2009 for both the domestic producers and the 13 selected domestic producers.
118. Capacity utilization at the end of period of investigation is still very high.
119. The average profit considered on annual basis in 2007-08 as compared to 2008-09 shows a dramatic increase.
120. The no. of employees as well as productivity is stable and productivity slightly increased in the period Jan-Jun'09.
121. There is no causal link analysis. Overall Indian producers still hold more than 90% of the domestic market share and it is difficult to see how it could be demonstrated that imports representing only 10% of market share could cause any serious injury.

122. Factors other than imports like increase in production capacity must have had an important bearing on the economic situation of the domestic industry but its impact was not carefully analyzed.
123. Interest of parties concerned other than the applicants must also be investigated as per WTO Rules.
124. The conditions to impose provisional measures are very strict and required the existence of critical circumstances which need to be duly justified.
125. Import from various EU countries are already subject to anti-dumping duties and any 'double remedy' should be excluded

Comments of Indonesia

126. The antidumping duty is in force so Safeguard measure is an act of over protectionism.
127. The market share of Indian domestic industry is already 90-93% in total consumption. Therefore, imports can be considered as a minor irritant.
128. No unforeseen development as the imports has increased due to decrease in import duty (from 20% in 2004-05 to 7.5% in 2008-10).
129. No serious injury or threat of serious injury as injury determination by DGSG based on selective analysis of data. Production increased in Q1 and Q2 of 2008-09 over the preceding period and remained stable for the balance of the year.
130. Capacity increased more than demand during the period 2006-07 to 2008-09.
131. Domestic sales of both domestic industry and the 13 producers have been consistently increasing during the period 2006-07 to 2008-09.
132. The imports from Indonesia is below 3% and hence it should be excluded from safeguard measure.

Comments of Republic of Korea

133. The increase in imports is not sudden but the result of a continuous trend.
134. The quantitative analysis is required for V curve since April, 2008.
135. The fall in capacity utilization is not a recent change but a trend that has been occurring since 2005.
136. There has been no actual damage inflicted on employment.
137. The relationship between capacity and demand lacks logical evidence.

Comments of Mexico

138. Mexican imports are less than 0.1% of the total imports in any of the period concerned.
139. The joint participation of imports from the developing countries that are members of the WTO does not represent more than 9 percent of the total imports in each of the five periods analyzed, as well as in the period as a whole.

Comments of Taiwan

- 140. Taiwan may be considered developing nations and the exports of Taiwan should be excluded as the export from Taiwan constitutes small proportion.
- 141. There is already anti-dumping duty on imports if imported from some countries.
- 142. There is no sufficient evidence for imposition of safeguard duty on imports from Taiwan.

Comments of Thailand

- 143. The data related to a period after the notice of initiation cannot be taken into account and therefore, investigation period can only run until June 2009.
- 144. There is no injury because most of the injury indicators (production, sales, production capacity) show a positive development and other injury factors (such as profitability and market share) have either remained positive or stable over the entire period. The DG(SG)'s findings of serious injury based on selective analysis of available data.
- 145. There is no causal link as injury is not due to increase in imports as share of imports in total consumption in below 10% between 2006-07 and 2008-09.
- 146. The serious injury cannot be said to be the consequence of increased imports of Caustic Soda Lye generally, or from Thailand particularly.

Submissions of M/s. Basic Chemical Solutions Far East Pte Ltd. & Hindustan Uniliver Ltd. and others

- 147. Applicants must be domestic industry as defined under the Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B(6)(b)) which inter-alia defines domestic industry as that whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India. The present petition has been filed by the 5 applicants who collectively accounted for a meager 34% of the total production of the subject goods in India which by no means can be said to constitute major share of the total production. In order to overcome the threshold requirement for filing the petition, the DG(SG) suo moto collected data for thirteen manufacturing units who constitute 65% of the total domestic production. The DG, by acting in aforesaid manner, has subrogated into the shoes of the so called domestic industry and such action is not recognized under law. DG, based on its own finding in Hot Rolled Coils/sheets/strips investigation, ought to have rejected the Application.
- 148. The applicants have failed to submit any information/evidence on unforeseen developments leading to claimed increase in import.
- 149. Whether or not an industry is self-sufficient is no factor determining the appropriateness of a safeguard measures.
- 150. There is serious geographical imbalance between the demand and supply of the subject goods in India. The major consumers of caustic soda are located on east

coast of the country whereas the suppliers are operating on west coast. The table below shows the production capacity region wise

Region	Total Capacity (TPD)	Capacity Distribution (%)	No. of Plants	Capacity Range (TPD)
EAST	1147	13	8	40-365
WEST	4615	52	16	40-800
NORTH	1171	13	4	235-335
SOUTH	1943	22	9	110-375

151. It is evident from the Table above that the installed capacity on the east coast of the country is the lowest among four regions even when the demand is maximum there due to the operation of major aluminum mining firms. Hence, in spite of a higher total Indian capacity, the domestic industry is not able to cater to the needs of major consumers of caustic soda located on east coast at competitive prices.
152. In the instant case, it is evident that factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry. The data submitted by the applicants clearly shows that 92% of total imports of subject goods in 2008-09 were subject to anti-dumping duties. Therefore, given the volume of imports subject to anti-dumping duties, it is obvious that the root cause for alleged injury is dumping of the goods and not increased imports.
153. There is no economic rationale in imposing the anti-dumping duty and safeguard duty simultaneously on same product. In both the cases, injury or threat of injury to the domestic industry should exist. In addition, in both cases the investigating authority is obligated to consider almost same economic parameters to come to a conclusion of injury. In the instant case, the anti-dumping measures imposed by DGAD have already eliminated the injury caused by dumped imports. There is no warrant to impose safeguard duty in addition to the existing antidumping measures. If both the duties are imposed, it would amount to excess protection to the applicants for one & same injury.
154. The import data provided by the applicants in the petition suffers from grave discrepancies. In order to convert quantity of goods imported in LMT units into DMT units the applicants have chosen conversion factors at their whim and fancy without providing any explanation.
155. The preliminary findings dated 15 Oct 09 do not meet the requirements of Rule 8 and 9 of the Safeguard Duty Rules.
156. On the basis of the data maintained by DGCIS, there is no significant and sharp increase in imports. An analysis of market share taken by increased imports would show that the total domestic industry (taking the entire Indian production into account) has lost a meager 2% of market share in 2008-09 compared to 2007-

08. A meager loss of 2% in market share cannot be said to be serious injury within the meaning of Article 4.1(a) of the Agreement read with Section 8B(6)(c).
157. The total sales of the 13 selected units and entire domestic producers have seen significant increase in 2008-09 compared to 2006-07 levels. The increase comes to 14%. According to table 24 of the PF, the demand for subject goods has only increased by 2% during the same period i.e. 2008-09 vis-à-vis 2006-07. Therefore, when demand has increased only 2%, the domestic industry has seen an increase of 14% in its level of sales, there is no question of injury.
158. The production of selected 13 units has increased by 19% in 2008-09 compared to that of 2006-07.
159. There is no adverse impact on capacity utilization. The domestic industry (13 units) has increased their capacity by 21% in 2008-09 from that of 2006-07 level where as the demand increased only by 13% during the same period.
160. It is well known fact that caustic soda industry is cyclical in nature. The fall in profits in Q1 of FY 09-10, thus, cannot be determinative of the trend of the profitability of the industry. The industry has seen drastic fall in profits in past also when there was no alleged increase in imports.
161. There is no adverse impact on employment as it can be seen that the total number of employees has increased from 2135 employees in 2007-08 to 2166 employees in Q1 of 2009-10. Hence there is no injury on this account also.
162. The causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof is missing.
163. The claim regarding surplus export capacities in other countries is completely unsubstantiated. Even with the increase in the surplus capacity in North America, Europe and China post August 2008, the imports have shown a substantial fall in the following months. In fact the volume of imports has fallen to zero level in Nov-Dec 2008. Hence, there is fall in the imports of the product concerned even when there is increase in the surplus capacity.
164. Electro Chemical Unit Realization (ECU Realization) have increased. The prices of chlorine are showing upward trend. In fact, in July 2009 the prices of chlorine are more than the price level of Oct 2008. Based on ECU realization there is no injury to domestic industry.
165. The adjustment plan submitted by the domestic industry is nothing but just over enthusiastic statements without any concrete evidence as to how they are going to achieve the same. Since 95% of units are already operating on membrane cells process, there is virtually no possibility of further decrease in the cost of production and also power consumption as membrane cells technology consumes minimum power.
166. Assuming *arguendo* that imports are low priced leading to price undercutting, the anti-dumping law takes care of both the increased volume of imports and the subsequent price effects. It is for this reason that investigating authorities globally, especially those of USA, Canada, Jamaica etc. decline to apply both measure simultaneously. The European Commission's practice is to repeal, amend or suspend the existing anti-dumping or anti-subsidy measure in case safeguard duty is also proposed to be applied. The Anti-dumping and Subsidies

Commission of Jamaica only applies the higher of the two duties in case both the duties are in effect.

167. The domestic industry provided tabulated figures for aluminium and paper and pulp industry to show that there would be no impact on prices of end products of these sectors even if 20% safeguard duty on imports of caustic soda is imposed. Interestingly, once again, the domestic industry does not provide any evidence supporting the whimsical figures in these Tables. Secondly, the domestic industry has conveniently ignored the impact on prices in soap industry.
168. If safeguard duties are levied on caustic soda, that would amount to double penalty to the importers and users of the product concerned. This, in turn, will increase the prices of caustic soda based products for the general public. Caustic soda is used in chemical, paper, soap and metal industry. It is necessary for all of these industries to have supplies of caustic soda at economical prices to serve the general public. Imposition of safeguard duty would, thus, be against public interest.

Submission of M/s Tricon Energy Ltd, USA ; Hanwha Chemical Corporation Korea RP , Ferosa Plastic Corporation Taiwan and others

169. The applicants are habitual users of Trade Remedy measures. There is already Anti-Dumping Duty on the import of Caustic Soda from 11 countries. Hence Safeguard measures are not warranted. At best the review of existing Anti-Dumping Duty measures can be done.
170. The China and Indonesia accounts for 60% of all imports. The applicants could have moved to DGAD for revision of ADD from these two countries only instead of Safeguard measure.
171. There are very few integrated units of Caustic and chlorine in India. The Indian producers have not provided any data regarding operations of their Chlorine sales without which the injury analysis is not feasible.
172. There is no reason for the Director General of Safeguards ("Director General") to recommend the imposition of provisional safeguard duty as the Applicants have not suffered any injury and there are no critical circumstances justifying imposition of provisional duties.
173. The demand for Caustic Soda is expected to grow at CAGR of 4.9% from 2.27 MT in 2007-08 to 2.90 MT in 2012-13. Caustic Soda capacity is expected to increase at CAGR of only 3.9% from 2.74 MT in 2007-08 to 3.317 MT in 2012-13. However, Caustic Soda production, which is constrained by Chlorine demand, is expected to increase from 2.16 MT in 2007-08 to 2.75 MT in 2012-13. The mismatch in supply and demand is expected to be supplemented by imports.
174. The Preliminary Findings have ignored the principles of Natural Justice and the principles governing investigation contained in Rule 6 Proceeding expeditiously with the conduct of investigation in case of Critical Circumstances as contained in Rule 9 still requires DG to follow the Principal of natural justice as expeditiously is merely defined as "marked by or acting with prompt efficiency".
175. Director General being quasi judicial authority is bound by the principle of Natural Justice.

176. The applicants have not disclosed the methodology applied to the IBIS data to show that how the data has been collected. The applicants should be put to strict proof for their import detail submission particularly the conversion of LMT to DMT.
177. The application with mere 35% of Indian Production should not have been accepted for the purpose of initiation. The reference quoted in the Preliminary Findings i.e. Argentina- Poultry case is of Anti-Dumping Duty. The standard of evidence for Safeguard is much higher.
178. Director General himself in the final findings of HR Coil case dt. 08.12.2009 has observed that the definition of domestic industry does not recognize the concept of supporters. However in this case the Data of supporters have been provided after initiation of investigation and hence the same does not satisfy the definition of D.I. as per the Act and the Rules. The DG should have asked the DI to redefine the scope of DI rather than introducing the ad hoc supporters with no standing to file the application.
179. The applicant association as deliberately included only those industries whose state of affair can magnify the injury in the Domestic Industry.
180. The interpretation of Argentina –Footwear case to include the period after filing of application in the Period of Investigation is not correct. The DG must examine trend of import over the period of investigation up to the most recent point of time i.e. just before the period of investigation as held by the Appellate Body in the US- Steel Safeguards case. The Director General himself in Carbon Black case has refused to accept new evidence after initiation of investigation. The similar stand has been taken by DG Safeguards in Flexible Slab stock polyol case. Hence in this case the DG has wrongly extended the period of investigation beyond that established in the application.
181. The price of the goods is not a factor in safeguard investigation as per the relevant rules. If any factor other than increased import like lower price is the reason of serious injury than the case should be referred to DGAD.
182. The global meltdown which affected all the industries across the world cannot be considered as unforeseen development for the purpose of safeguard. The panel in Argentina Footwear case has excluded the Tequila Effect (Latin American Economic slowdown) from consideration of the potential injury.
183. The Domestic Industry has not suffered any serious injury as it has exhibited positive trend in most of the factors listed in Art 4.2(a) of the SG Agreement.
184. The existence of surplus capacity in exporting country is not the relevant factor in SG investigation.
185. The total import is only 9% of the market in 08-09 and hence cannot be treated as threat to domestic industry.
186. The market share of DI has not changed much. The DI is selling 100% of Chlorine and is regulating the production of Caustic as per the chlorine output.
187. The Capacity Utilization has come down in 08-09 due to global economic slowdown and not because of the increased imports. Further the DI has increased its capacity.

188. The DI has not been suffering from any substantial loss in profit. The profits in Q 1 of 2009-10 are down but the state of industry cannot be judged by the result of one quarter.
189. The DI has not suffered any injury in terms of employment and productivity.
190. The excess capacity in foreign countries is not valid consideration in determining injury. Further the excess capacity is in US, China and Europe, but the blanket safeguard measure has been recommended for all the countries.
191. The average quarterly net sale realization in 09-10 is higher than the average quarterly net sale realization in 2007-08. This shows that the cyclical nature of business is the cause rather than increased import. The economy is expected to improve September onwards.
192. The low chlorine price in India should be investigated. The reason appears to be captive use of Chlorine. The low price of Chlorine is inflating the cost/ price of Caustic Soda which is sold in the market.
193. The downward trend in ROCE owing to difficult economic circumstances and is not limited to the Chlor-Alkali sector.
194. The price is just one of the factor for consideration in determining injury and it cannot be taken for injury analysis. For that the correct authority is DGAD. The downward sale after Jan'09 is because of global meltdown and not increased import. Further the annual production in 08-09 is highest compare to 07-08 and 06-07.
195. The production by Domestic Industries is limited to the demand of Chlorine which is not sufficient for end user.
196. The DI should furnish costing of Chlorine and it should be taken into consideration while determining the costing of Caustic Soda and NIP.
197. There is no Causal link between increased imports and serious injury. The examination of injury factors reveals that DI's sales, production, Capacity Utilization, Profit and profitability has not been affected by increased imports. The injury to DI is attributed to :-
198. Low demand and price of chlorine in Indian market.
199. Setting up of new Al. plant has been deferred thus likely demand was not there in 09-10.
200. Production curtailed in June due to water shortage.
201. Chlor-Alkali has cyclical demand. Right now the cycle is not favorable.
202. The users are located in the East coast of India whereas the D.I. on the west Coast. The transportation cost is driving the users towards import.
203. There is no critical circumstances for provisional duty as most of the economic factors are showing positive trend.
204. The applicant's claim of conversion of Mercury cell to membrane cell is misleading and wrong as 93% of installed capacity in India has Membrane Cell. Reduction of freight cost is not in the hand of DI. The improved realization claim of DI is misleading as despite of 10 years protection from DGAD they have not done anything for consumption of chlorine.
205. Applicants have emphasized on importance of chlorine but neglected to deal with importance of Caustic to the public at large. The effect of SG duty on Caustic will affect the large workforce of Caustic industry.

206. Further the application of Safeguard measure and ADD measure on same product is not as per the policy of Central Government.
207. As per CRISIL report (CRISIL Research May 2009), the imports are set to grow because of demand – supply mismatch in the Domestic Industry. This shows the inability of the DI to cater to market demand.
208. The applicant themselves have submitted that there has been steep fall in Caustic Price, the import price declared is not real, there is difference in contract and spot price and there has been historical dumping. The allegations suggest that the injury suffered by DI is because of unfair trade practices such as dumping and circumventions. The Safeguard Rules clearly provides that if factors other than increased import are causing injury than the injury to DI cannot be attributed to increased imports and such cases must be referred by DG to the concerned authority like DGAD as appropriate.
209. Various data submitted in the written submissions, applications and preliminary findings are at variance.
210. The capacity has gone up by 25 % comparing 2nd- Quarter of 09-10 with the 1st- Quarter of 06-07. Thus the Capacity utilization has decreased because of the increase in Capacity of DI and limited use of Chlorine or viable means of its disposal. The decline in Capacity Utilization has nothing to do with the imports.
211. The Net Sale realization shown by the domestic industry in post hearing written submission is absurd. The sale price is as high as Rs. 25,000/ ton in Delhi in Dec. 2009.
212. The adjustment plan is not viable and does not justify the imposition of safeguard duty.

Submissions of PT Sulfindo Adiusaha and others

213. Overall examination of the petition and preliminary findings reveals that they lack the required objective and quantifiable detailed analysis on the basis of objective evidence of elements of increased import, serious injury, critical circumstances, unforeseen development, restructuring plan, causality and public interest as required by Article XIX of GATT 1994 and WTO Safeguard Agreement (“SGA”) which have been affirmed by WTO jurisprudence in a number of Reports. Also there were a large no. of procedural errors regarding the initiation and preliminary findings of the case.
214. The annualized data of the Indian domestic industry as well as 13 selected companies shows and confirmed their perfect healthy performance in all economic parameters.
215. There is no serious injury or significant overall impairment in terms of sales and production (even on quarterly basis data) suffered by the domestic industry as a whole or the selected 13 companies.
216. The selective analysis of the data on a quarterly basis is non representative. It misrepresents and exaggerate any injury to domestic industry.
217. There was no causal link between the increased imports and the serious injury or threat of serious injury as alleged by domestic industry because the increase of imports did not coincide with a decline in the relevant injury factors.

218. There has been no analysis on non-attribution in relation to the long lasting existence of anti-dumping duty.
219. There is no impact on employment.
220. There was improvement in productivity.
221. There was no significant impairment in capacity utilization.
222. The installed capacity of both domestic producers and the 13 selected domestic producers have increased for almost 20%-25% from 2006-2007 to 2009-2010 while the decrease capacity utilization is only 2-6% and it happened only in 2008-2009 and Q1 2009-10.
223. The domestic industry has maintained profit . It may be seen from the Annual Report of DSCL (Management Discussion and Analysis) for the year ended 31.03.09 (which represent part of the alleged period of surge in imports), one of the top three producers of the subject good, which jointly have one-third of total domestic production, it is evident that ECU prices reached up to 650 USD till October, 2008. In the last quarter of 2008, the price slashed, but domestic demand has not seen any significant decline. The prices bounced back in the first quarter of 2009 ending 31.03.09. The Performance of this activity of the company during 2008-09 has been impressive.
224. The Indian domestic industry managed to control the market through its persistent dominant position.
225. The domestic producers still held the majority of market share ranging from 81.71%-98.63% from 2006-2009. The share of domestic producers from 2006-2009 where still relatively above 90% (except on Q3 2007 -08 and Q2 2008-2009). In fact in Q3 of 2008- 2009, the domestic producers reached their highest point of domestic market share up to 98.63%.
226. The domestic producers increase their production capacity in a significant rate for almost 20%-25% from 2006-2007 to 2009-10.
227. There was no causal link between the increased imports and the serious or threat of serious injury as alleged by the Indian Domestic industry.
228. The 5 of the domestic industry accounted for 36% of the total domestic industry accounted for 36% of the total domestic industry was the applicant. Upon filing of petition, DG Safeguard directed information for more companies which 8 other companies agree to do so. The total 13 companies accounted for 68% of the total domestic industry. However, there is no proof of letter of support from the 8 companies supporting the initiation of the investigation. A mere statement that the 8 companies provide information to be used by DG Safeguard is not sufficient to prove that the 8 companies give its supports in the initiation of the investigation.
229. Public Interest and Critical Circumstance have not been properly analyzed It is important for the DG Safeguard to consider that of the total production of the 13 domestic industry, more that 30% are captive consumption for flakes or other value added products.
230. The arguments of low priced imports used repeatedly in the post hearing brief of the domestic industry as the main reason the domestic industry does not hold good as the low price imports have been addressed by the imposition of price

- reference in their imposition of antidumping measures applied to most of the exporting country.
231. The domestic industry has used the wrong instrument to handle the problem. The landed price in that annex still has not included the antidumping duty, handling charge, and other import related charges.
232. Historic Imports of Caustic Soda in India. DG Safeguard should assess this fact by comparing also with the growing demand and should not read this fact in isolation.
233. Expected import arrivals impacts market .About expected import arrival for the months of August and September 2009. The date should be ignored by DG Safeguards since it is beyond IP and submitted after the conduct of investigation has been started.
234. Loss in chlorine should not be attributed to the injury in caustic soda.
235. The domestic sale and production has been understated in the compiled data put up in the public file as is evident from the production per employee i.e. productivity data.
236. The demand of caustic has grown in 2009-10. The domestic industry does not have the capacity to meet the market demand. Hence the increased imports were only to meet the demand and supply gap. There is no injury to the domestic producers due to increase in import.

Submissions of Vedanta Aluminium Limited (VAL)

237. Domestic Producers are incapable of meeting domestic demands. Imports are not the cause for injury to domestic industry rather imports are caused on account of demand supply gap in India in Caustic Soda Lye market.
238. We have already submitted that an independent agency CRISIL in its Annual review has already reported that the incidence of import will be due to the demand-supply mismatch projected in the industry.
239. The VAL has contacted Domestic Producers for supply of Caustic but they did not fulfill the requirement. To substantiate this claim they have enclosed a no. of electronic correspondences entered with domestic manufacturers proving that domestic industry is running to the best of their capacity and not in a position to manufacture a single MT extra.
240. The capacity shown in application and admitted as it is in notice of initiation and Preliminary Findings are highly exaggerated and are not real.
241. In the case of Safeguard investigation concerning imports of Oxo Alcohols, Board on Safeguards rejected the recommendation of the DGSG for imposition of duty on the sole ground that Domestic Industry is incapable of taking care of domestic demand of Oxo Alcohol.
242. For every 1 MT of Caustic Soda produced, 0.89 MT of Chlorine is also produced. The demand of Chlorine is not consummate with the demand of Caustic Soda. The relatively low Chlorine demand forces producers to cut down production levels as they do not have safe storage facilities for chlorine and it cannot be discharged in the air.

243. Initiation of investigation is ab initio void. The domestic producers who have filed the application constitute only 1/3rd of domestic production. A case of initiation based on a written application of applicant under Rule 5(1) of SG Duty Rules, 1997, the data in respect of 60% of total domestic production must come from the application filed by applicant. Admittedly on the written application data in respect of only 1/3rd of domestic producers were contained. Therefore initiation of the case is faulty and beyond the scope of applications filed by applicants.
244. The adjustment plan of domestic industry must be something which is internal to the domestic producers on which they can exercise control. The adjustment plan of DI is focusing on external factors on which they have no control.
245. Precedent of adjustment plan. In the case of an application filed by United Phosphorous in 1999 for imposition of SG Duty on imports of Phosphorous for which investigation was initiated on 15.9.99, the para 21 of final findings of DGSG is reproduced for clarity
246. "It is observed from the data furnished by UPL/SCIL that with all the proposed efforts to be made by them in reducing the cost of power and achieving higher production efficiencies, they may not be cost-competitive as compared to the imported yellow Phosphorous, even after three years, the period for which imposition of SG duty has been requested"
247. If the duty is imposed, it is not in the interest of user industry as they will be either forced to reduce the scale of operations or buy the imported product on payment of SG duty.
248. DG Safeguard is not the proper authority to reject or question the transaction price of Caustic and to investigate the allegation of overinvoicing of Caustic Soda by the importers. The correct authority is DRI or FEMA.
249. There is a sharp increase in demand of Caustic Soda Lye in the Alumina industry due to expansion. The DI is not in position to met with the requirement of Al. Industry.

Submissions of Aluminium Association of India

250. A more rigorous standard of investigation (than an anti-dumping investigation) has to be adopted while determining a need for imposition of safeguard duty. As the only remedy is to challenge the decision in the High Court.
251. Safeguard duties impermissible unless effect of anti-dumping duties on imports from 25 member countries of the European Union (EU) and 10 other countries are factored out.
252. There is no mention in the preliminary finding regarding the manner in which the DG has taken into account the anti-dumping duties in place against imports of Caustic Soda from around 35 countries. AAI had pointed this fact in its response dated October 5, 2009.
253. Moreover, the DG could not have concluded that there was serious price-based injury on account of an adverse price-effect of these imports on the Net Sales Realisation of the DI when the actual landed value of imports from these countries after imposition of anti-dumping duties was significantly higher than the Net Sales Realisation.

254. For purposes of its Preliminary Findings, the Authority ought to have limited itself to information pertaining to the “domestic industry” and not other Indian companies.
255. Despite continuous shifts in AMAI’s position with respect to the definition of the “domestic industry”, it is clear from the Preliminary Findings that the Authority has not been able to render a positive findings of serious injury even based on six additional domestic producers included in the “domestic industry” at the time of initiation notification dated 20.08.09.
256. Selective resort to facts after period of investigation is not permissible. The authority have chosen the period of investigation (the “POI”) as January-June 2009 in the Initiation Notification. But has selectively taken into account information for the month of July’ 2009 and August’ 2009 in one graph on ECU sales realization.
257. Shift from actual “serious injury” to the domestic industry to “threat of serious injury” shows weakness of case on injury.
258. ECU concept selectively deployed. The preliminary findings now have taken this aspect into account in a selective manner, without reflecting, however, the reality that, prices of Chlorine and Caustic Soda bear an inverse relationship. The preliminary findings have ignored the fact that the annual reports for FY 2008-09 and quarterly reports for the first two quarters of FY 2009-10 of the 13 companies representing the DI both reflect this reality and that they all show healthy profits for the chlor-alkali segment including both Caustic Soda and Chlorine on an “electro-chemical unit” (“ECU”) basis.
259. No AMAI submission given to the Authority on “unforeseen event” as required under Article XIX of the GATT and under WTO agreement on safeguards.
260. Petition must be dismissed outright because AMAI misled the authority and submitted inaccurate and incorrect data.
261. The contention of AMAI that profitability has declined and domestic industry is suffering financial losses is wrong and 12 manufacturers out of 13 manufacturers referred to in the initiation notice, confirms only three of them have suffered any losses after taking into account interest and depreciation.
262. Preliminary findings vitiated by non-consideration of AAI submissions.
263. Sudden surge in imports. The surge is not sudden. Import of caustic soda have been on increase since 2003-04. Imports as a percentage of total consumption, also increased from 4.1% in 2003-04 to 6.8% in 2007-08.
264. The figures pertaining to employment in the domestic industry have shown an increasing trend which is possible only if there was an increase in production and profitability of the domestic industry.
265. Cost to Sell : The finding that low ECU realization in India has rendered the Caustic Soda industry unviable in India is not correct. The authority has completely brushed aside in this regard the CRISIL Report produced by AAI with its response to the Initiation Notification.
266. The low return on employed capital is not on account of any increase in imports. Rather, it is the result of increased interest and depreciation cost.

267. The authority has failed to take into account the effect of anti-dumping duties in force on imports of caustic soda from 35 exporting countries on finding that the import prices have depressed the domestic prices till August 2009.
268. Factors other than increased imports causing injury.
269. No Causal link between imports of caustic soda and the alleged threat to the domestic industry
270. There are no critical circumstances in the present case.
271. The authority has completely brushed aside AAI's submission that imposition of safeguard duty would harm the prospects of the aluminium industry which is a sunrise industry in India.
272. There is no Restructuring Plan of DI. Any imposition of safeguard duty will help in subsidizing the inefficiencies of Chlor Alkali manufacturers at the cost of actual users of Caustic Soda Lye. The capacity of Mercury Cell Plants is less than 9% of the total installed capacity and even if all these plants convert to membrane Cell technology, the impact would be marginal.
273. The increase in import of Caustic Soda is not because of any Unforeseen development but for low demand of Chlorine in India leading to low production of Caustic. There is no unforeseen development in this case which is must requirement for SG as per WTO appellate body ruling
274. The accuracy of import data is questionable in view of the incorrect quantity of 12 B/Es submitted by them on 05.10.2009. Hence issuance of Preliminary Finding on 15.10.2009 w/o verification of import data of DI is improper and provisional Duty Notification dt. 04.12.2009 has been issued in great haste.
275. The letter dt. 31.12.2009 of DGSG office clearly shows that the discrepancy pointed out by the AAI in import data was correct. Hence other discrepancies should also be thoroughly examined.
276. The AAI vide letter dt. 05.10.2009 and objection to Preliminary Findings has submitted Annual Reports of 12 out of 13 participating companies which shows that they have posted healthy profit in 2008-09 and in Q1, Q2 of 2009-10 also they are in Profit. But the submission shows that DI is facing losses. Hence the data provided on Profitability, ROEC and ECU realization should be verified properly before issuing any Findings.
277. In the initiation Notice it was shown that M/s GACL is in losses but the AAI has produced Annual report of GACL for 08-09 and Q1 of 09-10 which shows profit. Hence the same is incorrect.
278. Some of the participating companies of DI have themselves attributed decline in profitability to factor other than increased imports like Aditya Birla Chemicals, Grasim Industry and SEIL Chemical complex have stated that the performance is effected due to low demand of chlorine. M/s PACL has attributed the same to availability of power., Grasim again to water shortage in their Annual Reports.
279. The average cost of power shown as Rs. 4.705 per Kwh in 2008-09 which is incorrect. As per CRISIL report the cost of power in 2007-08 was Rs. 3.10 per Kwh and as per its report of Oct. 2009 wherein they have analysed 5 Caustic Companies, the cost of captive power is Rs. 2.70Kwh and that of purchased one is Rs. 3.40 per Kwh.

280. As per Annual report of 9 out of 13 participating companies, the average cost of power is only Rs. 3.5 per Kwh.
281. The weighted average landed value of import should be compared with weighted average Net sale realization or cost of sale to arrive at the loss suffered by the domestic industry.

Other Submissions

282. For a safeguard measure to be applied, an applicant needs to prove sudden, sharp, recent and significant increase in imports of subject goods; unforeseen developments; existence of serious injury or threat thereof to the domestic industry; and causal nexus between the increase in imports and serious injury or threat thereof.
283. The self-sufficiency of the domestic industry in itself is no ground under safeguard law to apply a measure.
284. The major consumers of caustic soda are located on east coast of the country whereas the suppliers are operating on west coast. The installed capacity on the east coast of the country is the lowest among four regions even when the demand is maximum there due to the operation of major aluminium mining firms. Hence, in spite of a higher total Indian capacity, the domestic industry is not able to cater to the needs of major consumers of caustic soda located on east coast at competitive prices.
285. The domestic industry here mainly contends that due to reference price-form of anti-dumping duty exporters are able to sell at very low prices while Indian importers report prices at above the reference price level. This again is no ground to be examined by the DG under the safeguard law. In such a case the domestic industry may move appropriate forum under the Customs Act.
286. The fact that there are already anti-dumping duties in force on imports of caustic soda leaves little room for the DG to further proceed in the present investigation in the light of paragraph 2 of Annex to Safeguard Duty Rules.
287. The WTO decisions quoted by the domestic industry relate to AD cases and not relevant in a Safeguard investigation.
288. The price decline per se is not sufficient to levy safeguard duty. The price decline should have been caused by a sudden surge in imports which in turn was caused by unforeseen developments. Merely because there is a price decline, no protection can be given.
289. The domestic industry claims that the surge in low priced imports of subject goods has caused severe decline in profitability. In order to support and illustrate this claim, the domestic industry has provided data for some selected companies. That these claims are bald, unsubstantiated and false would be proved by our analysis as follows. At the outset, we object to this selection of five companies out of the total 13 companies for data analysis. The Petitioner cannot select five companies just to simulate injury when 13 companies together constitute domestic industry.

290. The data submitted by DI prove that there is no relation between the volume and value of imports and the profits of the domestic industry
291. The domestic industry claims that spot prices of the subject goods have significantly declined and imports are mostly on spot basis. The claim is bald, unsubstantiated and without any evidence in support.
292. The domestic industry has failed to provide any concrete and coherent evidence on unforeseen developments which is a pre-requisite for application of any safeguard measure. The domestic industry, at page 19 of the submission, mainly claims the following two points as the unforeseen development:
 - a. unforeseen circumstances happening around Sep-Dec. 2008 leading to decline in global demand of the subject goods
 - b. due to sudden increase in Chlorine demand surplus in caustic soda in the US market
293. That the aforesaid claims are insufficient is obvious from the fact that a surplus in US market alone cannot be an "unforeseen development" for the purposes of global safeguard measure. Secondly, most of the extracts as cited by the domestic industry contradict its own claim.
294. The domestic industry has not submitted anything with regard to the selection of Period of Investigation.
295. The import figures reported by the domestic industry are grossly erroneous.
296. The domestic industry has provided information on various economic parameters in order to claim "serious injury". We reiterate that the standard of injury under safeguard law is "very high" and "exacting" as held by Appellate Body in *US – Lamb case*.
297. The domestic industry has provided quarterly figures with regard to its share in the domestic market. For FY 09-10, now the figures for first two quarters have been provided. We request the DG to freeze the POI till July 2009 and all subsequent data may be rejected.
298. Secondly, the figures for Q1 FY 09-10 are not indicative of the trend for entire year. The data till 2008-09 would show that there is only a meager loss of 1.87% in the share of the domestic industry as compared to 2007-08.
299. This marginal loss of 1.87% in the market share, with no figment of imagination, can be said to satisfy the very high standards of serious injury within the meaning of Article 4.1(a) of the Agreement and Section 8B(6)(c) of the Act.
300. The domestic industry has provided data relating to sales of all domestic producers as well as that of 13 selected producers in separate Tables at page 54 of the submission. At the outset, we highlight that the figures for all domestic producers is significantly different from that recorded in Table 6 at page 30 of the Preliminary Findings. The Preliminary Finding shows an increase of 9% in sales by all domestic producers in 2008-09 as compared to 2007-08. But the new figures submitted by the domestic industry in its written submission shows a fall of 2% for the same period.
301. The sales, production, capacity utilization and other parameters show healthy growth.

302. There is no decline in levels of employment. On the contrary employment has increased in first two quarters of FY09-10 both in absolute and average terms when compared to 2008-09.
303. At paragraph 136 of the Preliminary Findings, the DG notes that the productivity has increased in Q1 2009-10. Hence there is no injury on this account too.
304. The domestic industry claims that the surplus capacity available with foreign producers is an issue of great concern as it would lead to further increase in imports. Firstly, this claim is wholly unsubstantiated as there is no relationship between surplus capacity and imports
305. The domestic industry claims that there is significant price undercutting due to low priced imports. This claim is bald, illogical and unreasonable for reasons as follow. Except Thailand and Egypt, imports from all countries are subject to anti-dumping duty which is in reference price form. Hence no imports have landed in the country below the non-injurious price fixed by the DGAD.
306. Hence, an evaluation of all the above factors does not show any injury let alone "serious injury". Further, marginal decline in market share cannot be said to have caused serious injury whose standard is "very high" and "exacting".
307. The DG is obligated to examine the other factors which may have caused injury to the domestic industry and injury thus caused shall not be attributed to imports. Here, we reiterate that injury, if any, has been caused by the dumping of goods and for that DGAD is appropriate authority to provide suitable remedy.
308. On the issue of other factors, it is pertinent to mention the chlorine-inventory constraints faced by a major portion of the domestic industry. In fact, a Report from Harriman Chemsult Ltd suggests that demand for caustic soda has remained flat even in the first quarter of FY 2009-10.
309. In India, caustic soda market remains sluggish during the monsoon season, especially on India's west coast.
310. The imposition of safeguard is not in public interest.

Findings of the DG:

311. The case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nations have been analysed. Submissions made by the various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.

The Indian Market for Caustic Soda: A snap shot

312. **Nature of Industry:** The caustic Soda is manufactured by electrolysis of common salt. The production of caustic soda is always accompanied with production of Chlorine in fixed proportion. Both Caustic Soda and Chlorine have commercial utilities and are used in different industries. Caustic soda (sodium hydroxide) is a versatile alkali. Its main uses are in the manufacture of pulp and paper, alumina, soap and detergents, petroleum products and chemical production. Other applications include water treatment, food, textiles, metal processing, mining, glass making and others. Caustic soda is also a basic feedstock in the

manufacture of a wide range of chemicals. It is used as an intermediate and a reactant in processes that produce solvents, plastics, synthetic fibres, bleach, adhesives, coatings, herbicides, dyes, inks and pharmaceuticals. It is also used to neutralise acidic waste streams and the scrubbing of acidic components from off-gases. It is used in the petroleum and natural gas industries to remove acidic materials from hydrocarbons and off-gases. In the textile sector, it is used in the chemical processing of cotton and the dyeing of synthetic fibres. If caustic soda is in surplus, it can be stored if sufficient capacity is available.

313. Chlorine is an essential input to the chemical industry. Of all the halogens, chlorine is by far the most abundant in nature and is the easiest to produce. More than 85% of all pharmaceuticals and more than half the products of the chemical industry depend on chlorine chemistry. These products are used in most industrial and economic sectors including:

1. Healthcare;
2. Agro-food;
3. Building;
4. Textiles;
5. Transport;
6. Leisure activities;
7. Cosmetics.

314. Chlorine, by its nature, is difficult to store and transport, so it is mainly used at the site where it is produced in a variety of downstream units such as those for VCM (Vinyl chloride monomer, the building block for PVC), and the plastic PVC (Polyvinylchloride). There is negligible international trade of chlorine.

315. As production of Caustic Soda cannot be delinked with the production of Chlorine, the industry is known as Chlor-Alkali industry. The demand, supply and price dynamics of both Chlorine and Caustic Soda affect health of the Industry.

Indian Caustic Soda Industry in the International market:

316. Caustic Soda has general uses in a large number of industries. The growth of caustic soda industry is largely dependent on overall growth of manufacturing sector. Approximately 7% of domestic demands were met by imports in past. China, Indonesia, Europe, Thailand, Qatar and USA are the main exporting nations to India. India does not have significant presence in export market of Caustic Soda. Indian producers have been exporting around ½% of their production.

317. The installed production capacity in India is about 20% of installed capacity of North America, 22 % of Europe and 12% of China. The market size in India has been growing and to meet the growing demand the installed capacity has also grown at the same pace leading to gradual increased production in past years. Even after gradual increase in capacity and production in past years, the Indian Caustic Soda market is less than 5% of the World Caustic Soda market.

Need for Safeguard Investigation:

318. The Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) filed an application for imposition of Safeguard Duty on imports of Caustic Soda into India to protect the domestic producers of Caustic Soda against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Caustic Soda into India. They have also submitted that the increased import has made their industries unviable and that the industry has been running on losses. The loss in profitability and market share are causing irreparable loss and thus provisional safeguard duty should be imposed to protect domestic industry. The evidences produced by them had shown prima-facie case of threat of serious injury/ serious injury. Hence, the investigation was initiated on 20th August, 2009. During the course of investigation the applicants produced detailed evidences relating to critical circumstances and requested for imposition of provisional safeguard duty.

Provisional Safeguard Duty on Caustic Soda:

319. The Preliminary Finding, recommending imposition of provisional safeguard duty at the rate of 20% for 200 days, was issued on 15th October, 2009. The Central government imposed provisional safeguard duty at the rate of 15% for three months vide notification number 131/2009-Cus dated 4.12.2009

The product under investigation:

320. The product under investigation is "Sodium Hydroxide also known as Caustic Soda in lye form". Caustic Soda is classified under sub-heading No. 28151200 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975. Caustic Soda is chemically known as NaOH. Caustic Soda lye is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is used in manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton etc. There is no contention of any interested party on the issue of product under investigation. The available facts show that the imported Caustic Soda lye and domestically produced Caustic Soda Lye have similar technical characteristics, sold through the same marketing channels and can be used by the user interchangeably. Therefore, the imported Caustic Soda lye is considered to be 'like or directly competitive' article to domestically produced Caustic Soda lye.

Domestic Industry:

321. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

(b) *"Domestic industry" means the producers –
as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*

whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

322. In the instant case the application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial Complex, Vikas Marg, New Delhi- 110092 for imposition of Safeguard Duty on imports of Caustic Soda. The applicant has disclosed the data of certain companies who constitute 35% of Indian production. They have also contended that 'major' does not mean more than 50%. In support of their contention they have referred to the Report of the Panel in the matter of Argentina- Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil. However, without going into legality of the contention made by the applicant, the safeguard investigation was initiated based on 13 (thirteen) manufacturing units of Caustic soda as domestic industry, which constitute more than 60% of the total domestic production of India. The preliminary finding was issued considering the 13 units as 'domestic industry'. These manufacturing units are:

- a. M/s Punjab Alkalies & Chemicals Ltd. (Unit I & II), Nangal Una Road, Naya Nangal, Distt. Ropar, Punjab.
- b. M/s Siel Chemical Complex, (A unit of Mawana Sugars Ltd.), Vill. – Khadauli, Charatrampur, Rajpura, Distt- Patiala
- c. M/s Grasim Industries Ltd., Chemical Division, P.O. – Birlagram,
- d. Nagda (M.P.)
- e. M/s Gujrat Alkalies, and Chemicals Ltd.- Dahej, P.O. – Dahej, TaVagra, Distt - Bharuch.
- f. M/s Gujrat Alkalies and Chemicals Ltd. – Baroda, P.O.Petrochemicals, Ranoli, Baroda – 391346.
- g. DCM Shriram, Shriram Fertiliser & Chemicals, A unit of DSCL, Kota.
- h. Shriram Alkali & Chemicals, 749, GIDC Indl.Estate, Jhagadia, Distt – Bharuch, Gujrat – 393 110
- i. M/s Reliance Industries, Ltd., Dahej, Dahej Mfg Div, P.O. – Dahej, Distt-Bharuch, Gujrat – 392130.
- j. M/s DCW Ltd, Sahupuram, Distt – Tuticorin
- k. Indian Rayon, A unit of Aditya Birla, Nuvo Ltd., Junagarh – Veraval Road, Viraval, distt – Junagarh, PIN – 362012.
- l. M/s Gujrat Fluoro Chemicals Ltd., Plot No.12-A, GIDC, Industrial Area, Dahej, Bharuch – Gujrat
- m. M/s Kannoria Chemicals & Industries Ltd., P.O. – Renukot - 231217, Distt - Sonebhadra.
- n. Aditya Birla Chemicals (I) Ltd., (formerly M/s Bihar Caustic & Chemicals), Garhwa Road, At & PO. Rehla, Distt. Palamu (Jharkhand)

323. Share of these 13 manufacturing units in total production of India has been between 60 to 71% in last three years.

324. The interested parties submitted their comments through written submissions and verbal submissions during public hearing. It was submitted that 35% can not

constitute majority. Majority, ordinarily means, more than half. The findings in Report of the Panel in the matter of Argentina- Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil is not relevant in the instant case, as safeguard laws and anti-dumping laws are different. It was also submitted that the investigation should be either on the basis of situation of sole applicant or the total industry. Some of the interested parties submitted that the Director General should confine to the facts contained in the application.

325. The issue was analyzed. The dictionary meaning of 'major' is 'important, serious, or significant'¹. It is also a fact that the investigation is carried out to determine existence of 'serious injury' or 'threat of serious injury' to the domestic industry. The imposition of safeguard duty is likely to affect all the domestic producers. The Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as all the domestic producers of the product taken together or those domestic producers who collectively constitute major share of domestic production. Therefore, it is necessary that the evidence of the domestic producers being important, serious or significant is accompanied with the claim.
326. The question, whether the Director General has to confine to the facts contained in the application, finds its answer in Section 8B(1) of the Customs tariff Act, 1975, Safeguard Rules and overall scheme of the Agreement on Safeguard. The Section 8B(1) empowers the Central Government to impose safeguard duty, *after conducting such enquiry as it deems fit*. The Safeguard Rules provide for investigation of the existence of 'serious injury' or 'threat of serious injury' by the Director General. The word 'enquiry'² means 'an act of asking for information' and the word 'investigation'³ means a careful search or examination in order to discover facts. The word 'enquiry'⁴ also means a close examination of a matter in

¹ The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995) p.882

² Enquiry (n) an act of asking for information The Concise Oxford Dictionary Tenth Edition (Indian Edition) Oxford University Press

³ **investigation** [ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃən]

n

the act or process of investigating; a careful search or examination in order to discover facts, etc.

investigational *adj*

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged 6th Edition 2003. © William Collins Sons & Co. Ltd 1979, 1986
© HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003

⁴ **inquiry**

n. pl. inquiries also *enquiries*

1. The act of inquiring.

2. A question; a query.

3. A close examination of a matter in a search for information or truth.

Synonyms: inquiry, inquest, inquisition, investigation, probe, research

These nouns denote a quest for knowledge, data, or truth: *filed an inquiry about the lost shipment; holding an inquest to determine the cause of his death; an inquisition into her political activities; a criminal investigation; a probe into alleged police corruption; scientific research.*

- a search for information or truth. The Black's Law Dictionary defines 'Inquiry'⁵ as 'A request for information, either procedural or substantive'.
327. The overall scheme of the Agreement on safeguard as well as safeguard Rules also provide for discovery and examination of facts. Therefore, the contention that the Director General has to confine itself to the facts mentioned in the application is not tenable.
328. In the instant case, the application was filed by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI). The Alkali Manufacturers Association of India is the Association of all the domestic producers of caustic soda. Therefore, Alkali Manufacturers Association of India is competent to file application for imposition of safeguard duty under Rule 5(1) of the Safeguard Rules. However, the contention of the applicant that those domestic producers, who collectively produce 35% of total Indian production, constitute 'domestic industry' cannot be accepted as no evidence to show that these industries have important, serious or significant share could be produced by the applicant. Moreover, there is no evidence on record that these producers could collectively reflect representative state of whole of the industry.
329. The Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 gives two options for definition of the domestic industry, firstly all the domestic producers of the product taken together, and secondly those domestic producers who collectively constitute major share of domestic production. The first option has inherent advantage that it represents the complete state of the affair of the industry of the concerned product. Therefore, when it is practicable to consider whole of the domestic producers as 'domestic industry', treating whole of the domestic producers as 'domestic industry' is a preferred option. Therefore all domestic producers of caustic soda, collectively, are treated as 'domestic industry' within the meaning under Sec 8B (6) (b)(iii) of the Safeguard Duty Rules 1997.

Period of Investigation:

330. It has been contended by some of the interested parties that the period of investigation should be fixed at the time of initiation of investigation and the analysis of data should be done only on annual basis.
331. The issue has been examined. The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard or the relevant Article XIX of GATT does not specifically define what the Period of Investigation should be. However, the issue of period of investigation has been dealt extensively in the panel's report on Argentina

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition
copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by
Houghton Mifflin Company.

⁵ Inquiry: 1. Int'l Law. Fact Finding (2) 2. Parliamentary Law. A request for information, either procedural or substantive.

Footwear as well as Appellate Body Report on Argentina Footwear, which are being produced below;

“Argentina—safeguard measures on imports of Footwear; Report of the Panel

8.216 *Regarding the investigation's almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the “increased imports” analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse “all relevant factors”, and in addition, the situation of the domestic industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions.*

We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required

Appellate Body Report

Note 130:

The Panel, in footnote 530 to para. 8.166 of the Panel Report, recognizes that the present tense is being used, which it states “would seem to indicate that, whatever the starting-point of an investigation period, it has to end no later than the very recent past.” (emphasis added) Here, we disagree with the Panel. We believe that the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past.

332. From the above it is apparent that neither the Agreement on Safeguard nor the relevant provisions of WTO provide specific definition or interpretation of the period of investigation. The Appellate Body Report has given the finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past. Therefore, the period after filing of the application cannot be ignored in safeguard investigation. However, in order to meet the requirement of natural justice, it is imperative that the information received or collected after initiation of investigation is accessible to the interested parties.

333.Regarding the contention that the analysis of data may be done on annual basis only and not quarterly basis, it is noted that there is no specific prescription or proscription in the law on the manner of analysis of data. Further, the Article XIX of GATT imposes conditions of increase in import on account of unforeseen developments and existence of serious injury or threat of serious injury on account of increased imports for imposition of safeguard duty. In order to ascertain, whether there is any increase in import on account of unforeseen developments or not, it is necessary that the imports after the unforeseen developments are compared with imports prior to the unforeseen developments. Therefore comparison and analysis of data based on calendar year or a financial year may not be appropriate in all cases especially when the unforeseen developments happen in mid of the year and not spread over a long period.

334.Further, the size of Period of investigation is not specifically defined in the law. However, it should not be too small to be considered as temporary phenomenon.

335.As the initiation of investigation has been done in the mid year, the annual information may not be very recent information. Therefore, for the purpose of analysis, quarterly figures have been acquired. In order to obviate effects of seasonal variation, if any, the comparison has been made with corresponding periods of preceding years. The abbreviation Q1, Q2, Q3 and Q4 denote April-June, July-September, October-December and January-March respectively.

Methodology and Source of information:

Import Data:

336.For the purpose of import data reliance has been placed on DGCIS figures up to FY 2007-08 and IBIS for the subsequent period. The transaction wise details of the information have been kept in the public file.

337.The interested parties contended that some of the entries of IBIS data are not relating to imports of caustic soda, and the conversion of LMT to DMT is not based on correct premise. The AAI and M/s Vedanta submitted 12 photocopies of certain documents, claimed to be copies of Bills of Entries, in support of their claim. They further submitted that there is a possibility that such errors may be present in case of other entries of IBIS data and their conversion methodology.

338.In order to devise a methodology to verify correctness of import data and arrive at correct import volume and value, a meeting was called, which was attended by consultants and interested parties. After detailed discussion on the issue, following methodology was adopted.

1. In order to match and reconcile the IBIS data received, the original IBIS data in soft form should be exchanged and be compared by each other.
2. The AAI representative to submit within three days any other B/E where there is any discrepancy in quantity beside the 12 B/Es submitted. The AAI would submit complete documents related to the 12 import consignments for verification of import quantity and value.

3. The petitioner would offer entry wise comments on the objection of the consultant of M/s HLL relating to import figures.
4. The import data of four major ports namely Mumbai, JNPT, Kandla and Vishakhapatnam, which constitute substantial portion of imports may be procured and circulated to all who requests for the same.
5. The exporters through their consultants present in the meeting were requested to provide month wise F.O.B. value and quantity exported to India..

339. Accordingly, the raw IBIS data, as received from the data collecting agencies were kept in the public file. The soft copy of data was also sent by the applicant to all those who requested for the same. The Customs data relating to imports of caustic soda from four main ports was also collected. Copies of the data was also made available to all those who requested.

340. The transaction wise data was filtered to remove all transaction which does not pertain to the product under consideration by checking the description of the product. The unit of quantity was found from the data and the same was considered as unit of measurement of the volume.

341. The data of five major ports received from the Customs Commissionerates of those ports and that from IBIS for import of Caustic Soda Lye from ports other than four major ports have been compiled and taken into consideration for period April 2008 to September 2009..

Information relating to other economic parameters:

342. The other economic parameters relating to all manufacturers of India have been sourced from the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) and individual units. Necessary verification of individual units has been conducted wherever found necessary. Further, the study report of Harriman Chemsult Ltd., a widely used journal on Chlor-Alkali Industry has also been referred. If any other information is used the source is mentioned with the information. Further, the capacity of unit is the actual functional capacity reported by individual units.

343. **Increased Imports:** The table below gives the Quarterly import figures relating to caustic soda in lye form.

Table 1

Quarterly Imports(DMT){Dry Metric Ton}				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	33641	32149	68760	96260
Q 2	15762	18149	28,949	322622
Q 3	45114	59299	6,786	
Q 4	20186	22614	73928	

344. The imports in the Q4 of 2008-09, Q1 and Q2 of 2009-10 are more than the imports which took place in any quarter in the past three years. The total imports during January-September, 2009 is 4,92,810 DMT against imports of 1,20,323 DMT showing increase by more than 300%.

345. Therefore, the final determination is that there is a sharp, sudden and significant increase in import in quantitative terms.

346. **Relative increase in imports:** The share of imports in the total market size of India has been as follows:

Table 2

Share of Imports in Total Market Size (%)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	6.71	6.12	12.36	15.17
Q 2	3.23	3.38	4.99	36.16
Q 3	8.46	10.46	1.34	
Q 4	3.90	3.96	12.4	

347. The market share of imports has gone up to 36.16% in the 2nd quarter of 2009-10 from 4.99% in the corresponding period in 2008-09, which is the highest during the entire period under consideration. The market share of imports has sharply gone up during the period January-September, 2009 by 14.04% as compared to the market share during same period of previous year. The share of imports during January to September, 2009 is 21.24%, that is also the highest in last three years.

348. Therefore, the final determination is that the imports have gone up in relative terms too.

Value of Imports:

349. The table 3 gives average quarterly CIF value of imports .

Table-3

Value of Imports Rs/DMT				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	14512	14274	18578	17327
Q 2	14957	14635	22907	12343
Q 3	16109	14954	17005	
Q 4	15622	14066	21582	

350. The average CIF value declined during Q1 and Q2 of 2009-10. The value reached minimum, i.e 12343Rs/DMT in Q2 of 2009-10. Therefore, the final determination is that the import prices have gone down significantly.

351. **Unforeseen Developments:** The financial meltdown and recession faced by the economy is unparalleled in recent history. The global recession caused sudden deceleration in the manufacturing sector all over the world. The deceleration has been different in different countries and for different sectors of economy. The caustic soda industry has also been affected by the slowdown in the manufacturing sector. The slowdown in demand of caustic soda in North America, Europe and many parts of Asia caused steep fall in prices. For example the spot price of Caustic Soda in USA fell to one tenth of what it normally used to be.⁶

352. The demand of caustic soda however continued to grow except in Q3 of 2008-09 in India in spite of slow down witnessed in various countries. The slowdown in North America and Europe, determined the price trend as they have more than half of the global production capacity.

353. These developments are unexpected and are 'unforeseen developments'. These developments caused price differences in different parts of world. It also caused a wide price gap between Indian domestic price and export price, and led to increased imports to India.

Evaluation of evidences relating to Serious Injury or Threat of Serious Injury:

354. **Statutory framework:** "Serious injury" means as an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry;⁷ and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.⁸

355. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show

⁶ Source: www.icis.com and Harriman Chemsult Ltd

⁷ Section 8B(6)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

⁸ Section 8B(6)(d) of the Customs Tariff Act, 1975.

"significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.⁹

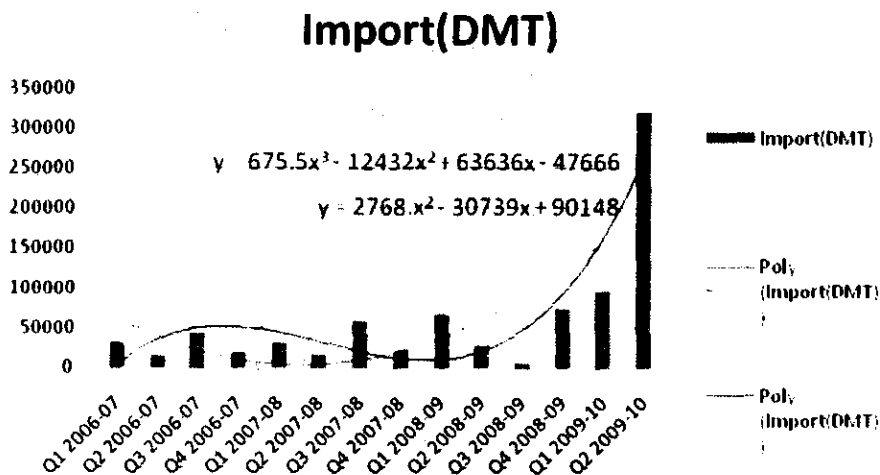
356. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

357. **Identification of relevant factors:** The following factors for determination of existence of serious injury or threat of serious injury has been considered;

1. Rate of increase of imports
2. Share of the domestic market taken by increased imports
3. Change in level of sales
4. Production
5. productivity
6. Capacity utilization
7. Profits & losses
8. Employment
9. cost to sell
10. Trend of domestic prices
11. Profitability of ECU.

358. **Rate of increase of imports:** In order to assess the rate of increase of imports trend of imports since April 2007 has been studied by drawing trend lines of polynomials of order 2 and order 3. The trend is as shown in the chart below. The trend lines show that the rate of increase in imports is positive and the growth in imports is accelerated one. The rate of increase has gone up in year 2009.

⁹ Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

Graph 1

359. **Share of domestic market taken by increased imports:** The table below contains share of all domestic producers taken together in domestic market.

Table - 4

Share of Domestic industry in Domestic Market (%)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	93.29	93.88	87.64	84.83
Q 2	96.77	96.62	95.01	63.84
Q 3	91.54	89.54	98.66	
Q 4	96.10	96.04	87.60	

360. The table above shows that the share of domestic producers in domestic market has gone down to 63.84% in the Q2 of 2009-10, which is the least during the entire period considered for analysis. The domestic producers lost 31.17% of the market share to imports in Q2 of 2009-10 and 14.04% during January-September, 2009.

361. This loss of market share of domestic industry is attributable to increased imports.

362. **Change in level of Sales:** The Table-5 is the table containing quarterly sales by the domestic industry.

Table 5

Sales by domestic industry (DMT)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10

Q 1	467602	493578	530966	538025
Q 2	472769	519328	550709	569402
Q 3	488394	507671	500116	
Q 4	497873	548682	522022	

363. The Sales by the domestic industry has fallen in Q4 of 2008-09. It has slightly increased in Q1 and Q2 of 2009-10 compared to corresponding quarters of previous year. The sales during January-September, 2009 have shown drop of 908 DMT compared to the same period of previous year. It is observed that the sales have not increased in spite of growth in demand in India. The growth in demand would have had positive impact on both sales and domestic prices, but imports increased the supply of caustic soda at low prices, which led to fall in domestic prices as well as no growth in sales.

364. **Production:** The Table-6 contains quarterly production of the domestic industry.

Table 6

Domestic Production of Domestic Industry (DMT)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	409156	513313	553111	559552
Q2	478836	535274	570672	580567
Q3	501207	541237	520889	
Q4	515987	559254	539546	

365. The production by the domestic industry decreased in Q4 but increased marginally in Q1 and Q2 of 2009-10 compared to corresponding quarters of previous year. The production during January-September, 2009 dropped by 3373 DMT compared to the same period of previous year. It is also observed that the above scenario is in spite of growth in demand and growth in installed capacity in India. The growth in demand and growth in installed capacity would have had positive impact on production. The imports took nearly all the increased demand. Further, the domestic industry has also responded to the increasing imports by reduction in the net sale realization, even if it adversely affected the profitability.

366. In light of above, it is noted that there is no increase in production of the domestic industry due to increased imports. This state of production even after increase in installed capacity and growth in domestic demand has negative cyclic impact on the health of domestic industry.

367. **Capacity utilization:** The Table-7 and Table 8 are the tables containing quarterly capacity and capacity utilization respectively of domestic industry.

Table 7

Capacity (DMT) of domestic industry				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	5,84,316	6,40,359	6,65,598	6,98,649

Q 2	5,86,208	6,43,734	6,72,769	7,18,396
Q 3	5,87,031	6,53,793	6,90,030	
Q 4	5,86,320	6,52,455	6,99,803	

Table 8

Capacity utilization of domestic industry (%)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	80.29	80.16	83.10	80.09
Q 2	81.68	83.15	84.82	80.81
Q 3	85.38	82.78	75.49	
Q 4	88.00	85.72	77.10	

368. The installed capacity of the domestic industry is growing. The increase in capacity during January-September, 2009 is 1,26,027 DMT. The trend in increase in capacity is consistent as Jan-Sep 2008 also witnessed increase in capacity by 1,20,409 DMT. The increase in capacity by domestic producers is in tune with the growth in domestic demand.

369. The capacity utilization of the domestic industry in Q4 of 2008-09, Q1 and Q2 of 2009-10 has been the minimum during the respective quarters compared to previous years. The capacity utilization has gone down to 79.35% during January-September, 2009 from 84.54% in the same period in immediately preceding year.

370. There is a fall in capacity utilization. However, the capacity expansions by Indian producers are natural business decisions considering growth in Indian demand. Therefore, the fall in capacity utilization is attributable to increased imports.

371. **Profits & losses:** The table below gives quarterly profits and losses. The profit of domestic industry in Q2 of 2009-10 has gone down by 17,476 Lac compared to Q2 of 2008-09 to reach loss of 6,328 Lacs. The domestic industry had made profit of Rs. 17,801 Lacs and Rs. 16,127 Lacs during Jan-September 2007 and 2008 respectively, but the total profit fell down by 13,494 in 2009 during the same period.

Table 9

Profit & Loss of domestic industry (Rs. In Lacs)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	4,598	4,712	4,910	2,671
Q 2	5,961	6,022	11,148	(6,328)
Q 3	6,529	4,496	2,409	
Q 4	7,067	68	6,290	

372. In light of the above it is noted that there is a fall in profit.

373. **Employment:** The companies as well as units are multi product companies and units and thus the employment does not reflect the impact. Further the increase in

employment is due to increase in capacity. However, the number of employees engaged by manufacturing units is as below.

Table 10

Total Number of Employees				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	8373	8603	8489	8840
Q 2	8333	8559	8547	8913
Q 3	8319	8570	8686	-
Q 4	8308	8582	8664	-

374.**Productivity:** The productivity has fallen down during Q4 of 2008-09, Q1 and Q2 of 2009-10 compared to the same period in immediately preceding year. The fall is primarily on account of fall in production even after increased capacity.

Table 11

Productivity (Production/employee) MT per Quarter				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	56.03	59.67	65.16	63.30
Q 2	57.46	62.54	66.77	65.14
Q 3	60.25	63.15	59.97	-
Q 4	62.11	65.17	62.28	-

375.**Cost to sell:** The Table 12 and Table 13 contain the quarterly information of Net sales realization /DMT and cost to sale of Caustic Soda respectively. The Graph 2 is the graph plotted based on information about monthly information on Net Sales Realization and Cost to sale .The Graph 3 shows ECU cost and ECU realization. (Electrochemical unit) [ECU = Ex-factory price of 1 MT Caustic Soda + 0.88 MT Chlorine].

Table 12

Quarterly Net Sales Realization/DMT of Caustic Soda				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	15,798	16,251	17,673	20,158
Q 2	16,173	16,062	19,692	15,931
Q 3	16,338	15,923	19,720	
Q 4	16,385	15,037	21,681	

Table 13

Cost to sell at 0% profit (Rs. /DMT)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	**	**	**	**
Q 2	**	**	**	**

Q 3	**	**	**	
Q 4	**	**	**	

Table 14

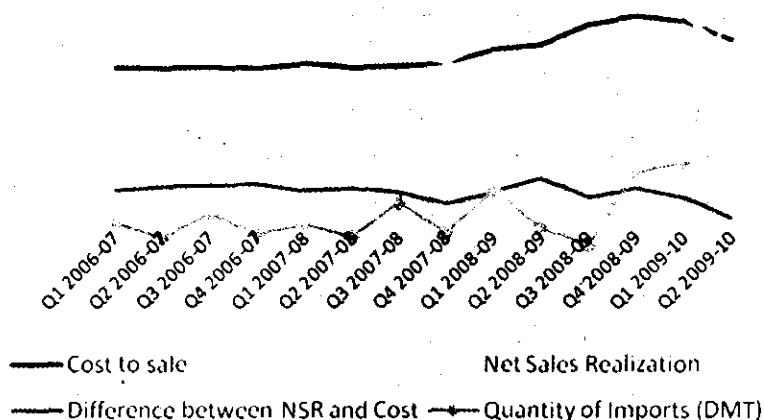
ECU Realisation (Rs/DMT)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	19,026	18,821	21,981	20,840
Q 2	19,355	19,922	22,936	19,144
Q 3	19,465	20,012	21,237	
Q 4	19,484	18,565	22,170	

Table 15

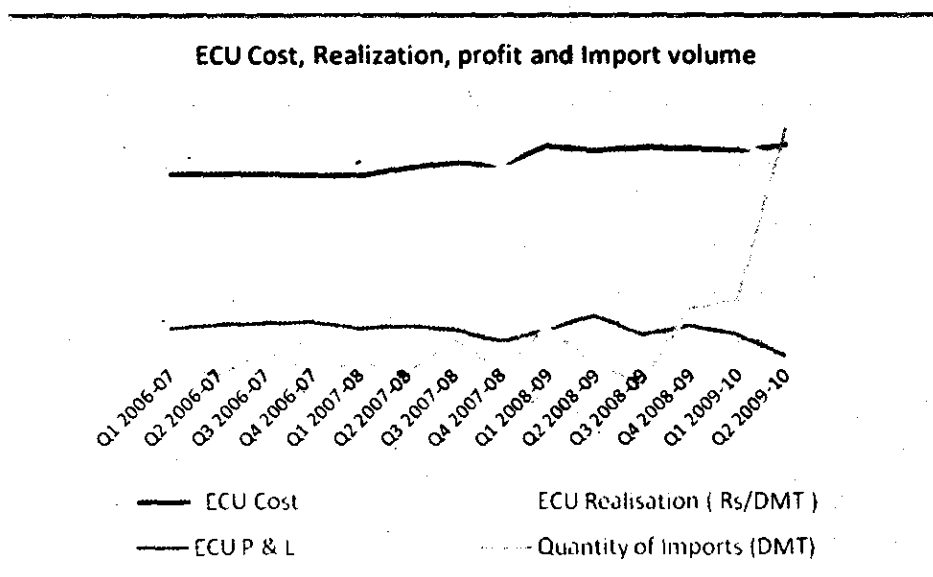
ECU Cost (Rs/DMT)				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	**	**	**	**
Q 2	**	**	**	**
Q 3	**	**	**	
Q 4	**	**	**	

Graph 2

Cost to Sale, Net Sales Realization and Import Volume



Graph 3



376. The above tables and graphs clearly show that Net Sales Realization of caustic soda started increasing from Q4 of 2007-08 but it saw steep fall from Q1 of 2009-10. It reached Rs 15931/DMT in Q2 of 2009-10, which is the minimum in Q2 of past four years.

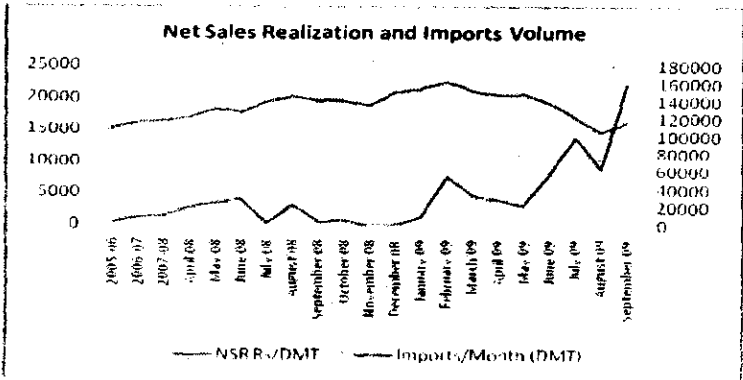
377. The analysis of above tables and graph shows that the difference between net sales realization (NSR) and cost to sale in respect of both caustic soda and ECU has been narrowing down since January, 2009 and turned negative during the second quarter of 2009-10 in India. The NSR of caustic soda has been reasonably higher than the cost of sales during the entire period under examination except after January 2009 when the difference started narrowing down. Similar trend is also noticed in case of ECU realization which went to the level leading to negative difference. The Chlor-Alkali business is viable only if the ECU realization is at least equal to the cost to sale. The fall in ECU realization in the 2nd quarter has led to loss of Rs. 1571/ECU. Therefore, it is seen that Indian Caustic Soda Industry became unviable with fall in prices to such a low level.

378. **Trend of domestic prices:** The table 16 gives the relationship between international prices and its effect on domestic prices. The Graph-4 shows effect of import on Net sale Realization of domestic producers

Table 16

Period	Average Net Sales Realization (Rs/DMT)	International Prices for Export (in US \$/DMT)		
	A	B	C	D
	(Rs/DMT)	North America	Europe	Asia
2005-06	15277	-	-	-
2006-07	16202	-	-	-
2007-08	16479	-	-	-
April'08	16948	550-560	420-440	365-387
May'08	18275	580-600	465-485	420-450
June'08	17784	-	-	-
July'08	19300	830-850	620-650	500-550
August'08	20256	830-850	700-740	580-635
September'08	19545	830-850	710-750	490-580
October'08	19600	830-850	710-750	450-470
November'08	18769	830-850	620-650	400-470
December'08	20887	830-850	600-640	400-470
January'09	21401	830-850	600-640	360-450
February'09	22545	820-850	600-640	310-390
March'09	21114	775-810	540-560	200-310
April'09	20519	225-325	200-250	200-250
May'09	20592	130-160	170-200	200-240
June'09	19303	90-110	90-120	170-200
July'09	16996	35-75	50-60	130-150
August'09	14675	40-65	60-80	115-150
September'09	16235	125-150	140-170	210-230

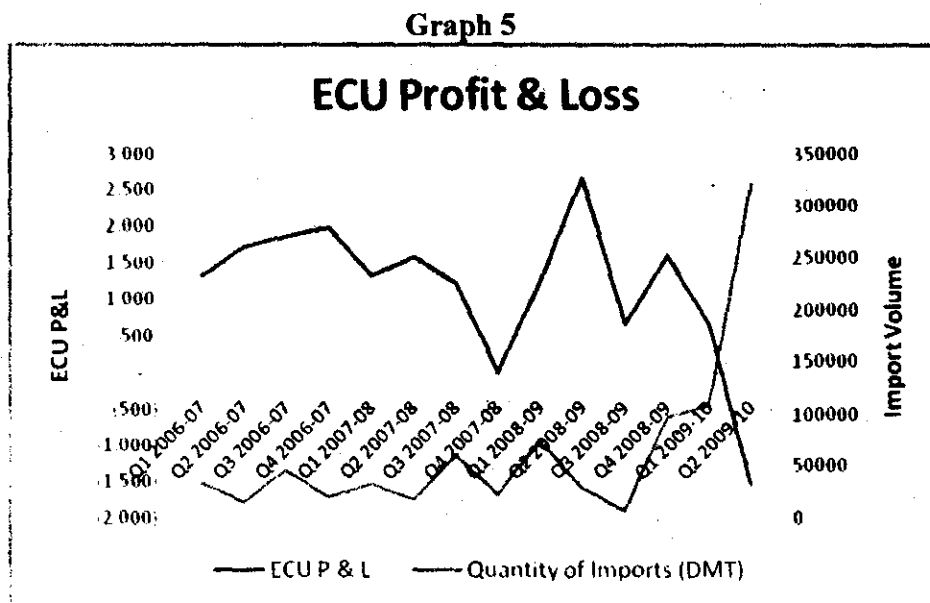
Graph 4



379. The table above clearly shows the existence of price difference between selling price in India and the price at which caustic soda is available in international market. The caustic soda market continued to grow in India fuelling demand. The growth in demand would have had positive impact on net sales realization. But the graph above shows the depression in domestic prices of caustic soda from January 2009 when there is significant increase in imports. The fall in domestic price in 2nd quarter of 2009-10 is Rs.3761 compared to price in same quarter of 2008-09. The domestic price during the same quarter is the minimum during the same quarter in last four years.

380. In light of the above, it is noted that the imports have caused depression in prices in the domestic market.

381. **Profitability of ECU:** The Graph below gives profitability in terms of Rs/ECU.



382. It is noted that the production of caustic Soda and chlorine goes together, by virtue of Chemical reaction, which produces caustic soda and chlorine together in near fixed proportion. Therefore, analysis of profitability has also been done on ECU basis, which takes price movement of both caustic soda and chlorine into consideration. The profitability of domestic industry has seen downward trend

post Q4 2008-09 periods. It has reached negative in Q2 of 2009-10. The fall in profitability has been steady and steep, when increased import was noticed.

383. In light of the above it is noted that there is a steep downward trend in ECU realization after increase in imports.

384. **Evaluation of overall position:** The analysis of individual parameters above shows that an important indicator i.e the difference between ECU realization and cost of sale at 0% profit has turned negative after the same getting narrower since last quarter of 2008-09. Therefore, the Chlor-Alkali industry has become non-viable. Further, the steep fall of caustic soda price for export in exporting nations caused wide arbitrage window, which in turn led to accelerated growth in imports. This fact also gets strength from the analysis of the rate of increase in imports.

385. The capacity utilization of Indian Industries has gone down to the minimum level during January-September, 2009, which clearly shows injury felt by Indian industry. The domestic prices have seen a steep fall. The profitability has reduced and turned negative in the Q2 of 2009-10. All these parameters show the extent of injury.

386. Based on the above, the final determination is that accelerated growth of imports, loss of market share of Indian Industries to import, import of caustic soda at a price below the cost of sales has forced ECU realization by domestic producers, to a level, below the cost of sale of ECU. Also, falling capacity utilization, falling trend in profits and profitability are the factors showing a clear and imminent threat of serious injury.

Other factors:

387. **Demand of Caustic Soda and capacity of Indian producers to meet domestic demand:** The Table -16 shows the demand of Caustic Soda in India and the Table -17 shows the installed capacity of caustic Soda in India. The total capacity during January-September 2009 was 21,16,848 DMT and the total demand was 2120479 DMT. Some of the interested parties have submitted that the domestic industry could reach maximum capacity of 88% and thus they could maximum produce 18.63 Lac DMT against demand of 21.2 Lac DMT during the same period. In response of the same the domestic industry submitted that safeguard duty has been imposed in past in a number of cases where domestic industry was not able to meet the domestic demand. In the instant case, the domestic industry has capacity to produce to meet the domestic demand, as operating at more than 100% of capacity is not unusual in this industry. In fact, there are a number of units who had crossed 100% capacity utilization mark in the past. Further, the entire imported caustic soda has not been put in use, as huge quantity is still lying in stock or warehouses.

Table-17

Demand of Caustic Soda in India in DMT				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	501244	525727	605852	634285

Q 2	488531	537477	579635	890244
Q 3	533507	566970	506902	
Q 4	518059	571296	595950	

Table 18

Production Capacity (DMT) of domestic industry				
Quarter	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q 1	5,84,316	6,40,359	6,65,598	6,98,649
Q 2	5,86,208	6,43,734	6,72,769	7,18,396
Q 3	5,87,031	6,53,793	6,90,030	
Q 4	5,86,320	6,52,455	6,99,803	

388. The issue was analysed. The principle of relying on the maximum achieved capacity utilization in past to ascertain ability of domestic industry to meet the domestic demand is not a correct approach. The imports increased primarily on account of wide arbitrage window caused by stiff fall in international prices.

389. **Exports:** The annual exports by India in 2006-07 were 17183 DMT, which is 0.86% of total domestic production. The export in 2007-08 and 2008-09 was 19311 DMT and 11573 DMT, which is 0.89% and 0.53% of domestic production respectively. The export in Q1 of 2009-10 is 1785 DMT, which is 0.3 % of total domestic production. Thus, it is noticed that the export by domestic industry is quite insignificant to have any influence on performance of domestic industry.

Table 19

Year	Export Quantity (DMT)	Export as % of total production
2006-07	17183	0.86
2007-08	19311	0.89
2008-09	11573	0.53

390. **Regional Imbalance in Demand and Supply:** It has been contended by the interested parties that demand and domestic supply is imbalanced on regional basis. The western zone is facing oversupply from domestic industry and the eastern zone has lesser capacity but higher demand as almost all the aluminum producers are based in eastern zone. The Aluminum association of India has submitted that the installed capacity in east zone is only 2.85 lac DMT against the demand of 3.85 Lac DMT per annum.

391. The issue was analyzed. The average import per month from Kolkata port during April 2008 to September 2009 is only 299 DMT per month, which shows that there is no major import from Kolkata. The average monthly imports from Visakhapatnam port in the FY 2008-09 was 7021 DMT. The average monthly imports increased to 15,761.67 DMT per month during April to September, 2009. As far as demand supply difference is concerned, the information available shows that it exists in eastern zone. Movement of caustic soda from west zone to east zone is expensive, but the more than doubling of import in Q2 of 2009-10 is not on account of demand supply mismatch as the consumption pattern of caustic

soda by aluminum industry shows that it has increased the use of imported caustic soda. The port wise import analysis also shows increase at all ports irrespective of the location of port. Therefore the increase in imports is on account of fall in international prices.

392.**Demand and Price of Chlorine in India:** Chlorine is amongst the most active elements and is very difficult to transport. Therefore, it has negligible international trade. Hence, the prices of chlorine are more influenced by local factors than by the international factors. The consumption pattern of Chlorine, internationally, and in India is as follows;

Table -20
SECTORWISE GLOBAL CHLORINE DEMAND:

S.NO.	User Industry	% share in Total Chlorine consumption
1.	Vinyls	36
2.	Chloromethanes	5
3.	Chloroethanes	1
4.	Propylene Oxide	7
5.	Allylics/Epichlorohydrin	4
6.	Phosgene/Polycarbonates	10
7.	Others(CB,CPr,CPf)	5
8.	Inorganics,Others	32

Source : Tecnon Orbichem (AMAI International Seminar on Growth of Cl2 Derivatives, May, 2008 Mumbai.)

Table 21
SECTORWISE CHLORINE CONSUMPTION PATTERN IN INDIA
DURING LAST THREE YEARS

S. NO.	END USER	PERCENT CONSUMPTION		
		2005-06	2007-08	2008-09
1	Vinyls (incl. PVC)	17.11	17.59	16.58
2	Organics	26.56	20.27	27.36
3	Inorganics	23.90	23.25	10.51
4	Pulp & Paper	10.29	8.27	8.32
5	CPW	7.00	11.12	14.46
6	Water Treatment	2.75	2.02	2.39
7	Pesticides / Insecticides / Weedicides	1.50	4.74	5.92
8	Pharmaceuticals	0.53	0.53	1.17

9	Dyes & Inks	0.55	0.39	0.53
10	Textiles	0.44	0.58	1.01
11	Others	9.38	11.25	11.76

393. The different consumption pattern of Chlorine in India compared to the global consumption pattern, results in its price variation. Hence, the prices of chlorine in North America, and Europe are different from that of the Indian market.

394. There is a wide difference in chlorine prices in different countries. This differential pricing of Chlorine is on account of inherent problems in their tradability and the nature of user industry of chlorine in these countries. As a result a situation is created where industries of certain countries can reduce the prices of caustic soda and still be viable by increasing the prices of chlorine. In India, it is not possible to increase the price of chlorine to a large extent because of different nature of chlorine consuming industry. The rise of chlorine prices above a level may cause increase in prices of derivatives of chlorine forcing imports of chlorine derivatives. Under these circumstances, the increased imports of caustic soda at lower prices cause depression in prices of caustic soda pushing the ECU realization below the cost, making the industry unviable.

395. **Causal Link:** The fall in capacity utilization, profit, profitability, net sales realization coincide with the increase in imports. It is the increased import at lower price which caused depression in prices in India leading to loss of profitability and profit. The increased import alone caused loss of market share. The growth of demand in Indian market has been taken by the increased imports.

396. Therefore, the increased import is the significant cause of threat of serious injury.

Summary of examination of submissions by Interested Parties:

397. All submissions made by the interested parties have been examined and dealt with at relevant places, while doing the analysis. A brief summary of issues raised and their analysis is as below:

Domestic Industry:

398. **Submission by Interested parties:** Most of the interested parties have submitted that Petitioners do not constitute domestic industry as the application is filed only on the basis of data provided by 35% of domestic production. The European Union has submitted that the investigation should be either on the basis of situation of sole applicant or the total industry.

399. **Analysis of submissions:** The submissions by interested parties have been considered and detailed analysis on the issue of 'domestic industry' is mentioned in the paragraph 321-329. All the concerns of the interested parties have been considered and the total industry is the 'domestic industry'.

Period of investigation:

400.Submission by Interested Parties: Some of the interested parties have contended that the period of investigation should be frozen and no subsequent development should be analyzed. It was also contended that analysis should be done on annual basis only.

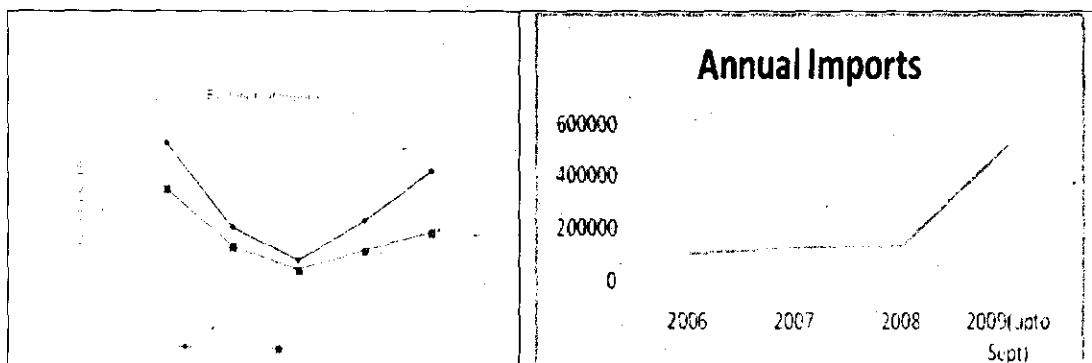
401.Analysis of submissions: This issue has been discussed in detail in para 330-335. The contentions by the interested parties are without any legal base. It is more appropriate to consider the most recent information available so that the decision about imposition of safeguard duty is based on the most recent information. The quarterly information is more elaborate than annual information, as annual information can be derived from quarterly information but quarterly information cannot be obtained from annual figures. Further, the quarterly information also exhibits trends during a particular year.

Increased Imports:

402.Submission by Interested Parties: Some of the interested parties have contended that the increase in import is gradual. The Korean Government has contended that imports increased both recently and sharply since December 2008 after sudden decrease during the previous months. Similar increase was not found to be sufficient enough for imposing safeguard measures in the case of Argentina-Peach safeguard in 2003.

403.Analysis of submissions: The analysis of import data and trend analysis clearly shows that there has been steady growth in imports till December, 2008. After that, the imports increased at a pace which never existed in the past. The imports in the Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 increased by 263% and 71% respectively compared to the same quarters of previous year. This increase cannot be termed as gradual increase.

404.Regarding the contention of the Korean Government about some decrease in import in the previous months, it is noted from the monthly analysis of imports that fluctuation in monthly import is a natural phenomenon. As far as the quoted test of increased imports as mentioned in the Argentina-Peach case is concerned, the similarity between the two cases have been studied by comparing the graph of increased imports in Caustic Soda and that of canned peach.

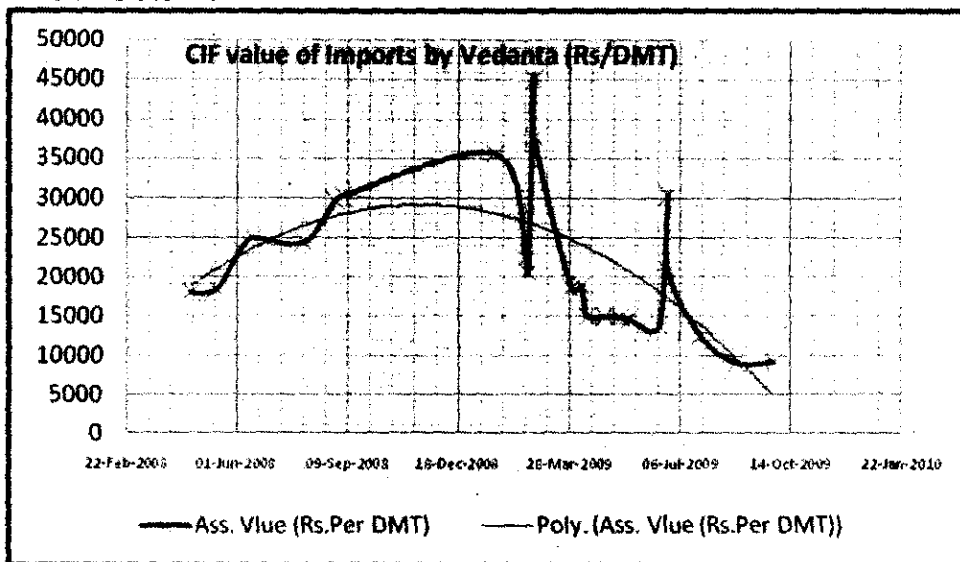


405. The comparison of the graph of import in the Argentina Peach Case and that in the instant case is different. In the Argentina Peach case the import in the recent period (year 2000) was less than the import four years ago (i.e 1996). In the current case, the import increased steadily in the past and saw a sharp increase in the recent period. The imports in the year 2009 (up to July) are more than the imports in any year in the past five years. Therefore, there is an increase in import.
406. **Submissions by Interested Parties:** Some of the interested parties have contended that use of import data has not been transparent. The conversion factor to convert data in DMT is not correct. In support of the claim 12 bills of entries were submitted.
407. **Analysis of submissions:** The issue is discussed in paragraph 336-341. The original IBIS data and Customs data as collected from major custom houses has been provided to those interested. The methodology of conversion of Units to DMT has been dispensed with to obviate any chance of error. The actual unit of quantity was ascertained from the customs data of ports of import. Further, there is no contention that imports has not increased.
408. **Submissions by Interested Parties:** The petitioner contended that many importers are showing imports at higher value to evade/avoid antidumping duty. They submitted information of FOB prices at port of exports and import prices (CIF) at Indian port along with prevailing freight. They contended that the over valuation of import is also taking place in the name of overseas sales and requested that the export prices with prevailing freight may be considered instead of the declared CIF value of importers for the purpose of safeguard investigation. In response to the allegations, the interested parties contended that it is beyond jurisdiction of the DG to go into the accuracy of declaration before the customs or the issue of overvaluation.
409. **Analysis of submissions:** The CIF value (Rs/DMT) shows very large deviation. It is also observed that imports are taking place at same port of import at same time with same country of origin at widely varying prices. It is also observed that there are certain unexplained differences in CIF value and (FOB+ prevailing freight) in case of some of the imports. However, it is noted that investigation into declaration made by importers before different authority is not the subject matter of safeguard investigation.
410. **Submissions by Interested Parties:** The Aluminum manufacturers have contended that the increase in import is on account of regional imbalance in demand and supply. The aluminum industry is situated in eastern zone and most of the caustic manufacturers are situated in western zone. There is oversupply in western zone on account of over capacity. There is lesser availability on account of increase in capacity in East Zone. The rise in import is to meet the growing demand in India, as domestic industry is not able to meet the demand..
411. **Analysis of submissions:** The issue has been dealt in para 390-391. The increase in import is not on account of regional imbalance only as, the imports increased at all regions and there is change in consumption pattern in favor of imports. The increase in import is mainly on account of fall in price in the international market.

412.Submissions by Interested Parties: M/s Vedanta has contended that domestic producers are not supplying to them. In support to the contention they submitted copies of e-mails showing regret and submitted that they are importing at higher prices. They further contended that the price of import is not the reason of their imports.

413.Analysis of submissions: The petitioners and some of the manufacturers submitted some e-mails showing where they have agreed to supply them caustic soda by ship at visakhapatnam port, where imported caustic soda land. Analysis of the emails and comments of petitioners shows that the regret to supply to M/s Vedanta is based on various factors including the logistics involved in transportation of caustic soda to Vedanta's factory. Regret by some of the supplier at some time does not imply that no domestic supplier has ever agreed to supply Vedanta and Balco, especially when there also exist e-mails showing willingness of domestic producers to sell them their product.

414.In order to assess the reason of their imports, the CIF values of imports at Visakhapatnam port have been analyzed. The analysis shows that there are certain imports, which are at abnormally high price, but most of the other imports are at falling prices. The graph showing prices of all imports at the port since April, 1st 2008 is as below:



415.Vedanta may find imports preferable on account of cheaper sea freight than land route freight coupled with low price at exporting countries.

416.Submissions by Interested Parties: Some of the interested parties have contended that the domestic manufacturers are making huge profits and thus the safeguard action is unjustified.

417.Analysis of submissions: The actual profit and loss of domestic industry in cumulative terms as well as its analysis has been discussed in para- 377 and 385-395. The profitability of individual unit is not relevant, as per RELIANCE INDUSTRIES LTD Vs. DESIGNATED AUTHORITY 2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.). The Hon'ble court has observed in the Anti-dumping case that the injury

determination is always for the domestic industry as a whole and not for individual companies. In the instant case, the investigation relates to only caustic soda in lye form, therefore, the profitability relating to the business of caustic soda (lye) is a relevant parameter. However, the profit by individual units clearly shows steep decline in profit.

418.Submissions by Interested Parties: Some of the interested parties have contended that market value of electricity, which is higher, instead of actual electricity production cost, has been taken while arriving at cost of production.

419.The Hon'ble supreme court in the case of RELIANCE INDUSTRIES LTD Vs. DESIGNATED AUTHORITY2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.) has held that *"In our opinion, for the purpose of determination of NIP, the DA is always required to take into consideration the transfer price (market value) of the inputs and not their actual cost of captive production. This is because the entire investigation, analysis, recommendation and imposition are for the product under consideration for the whole domestic industry and not for the individual companies and inputs captively manufactured which may be involved in the production and sales of the goods."*

420. In the instant case the actual market value of electricity has been considered while arriving at the cost.

421.Submissions by Interested Parties: The prices of chlorine have fallen down more in west than south, which shows that there is over supply of chlorine, which is restricting the production of caustic in west. Further there is excessive competition in west which is evident from lower ECU realization in west than east. In support of the contention they have submitted CRISIL report.

422.Analysis of submissions: The CRISIL report, as submitted by the interested party was examined. The chlorine prices in south zone and west zone are as follows:

Price of Chlorine in (Rs/ton)	Jan 2008	Jan, 09	Feb,	Marc h	April	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
West Zone	8288	2115	2639	2250	1470	1128	4000	8237	9094	6239	2300	2534	3384
South Zone	7500	1500	1200	3500	1500	1500	2250	7500	9000	8500	7000	6000	5500

423. From the prices of chlorine, it is apparent that chlorine prices fluctuate and sometimes it is higher in west than in south and sometimes it is higher in south than in west. The contention of interested party that prices of chlorine has fallen more in west than in south is not universally correct. Therefore, the contention of oversupply of chlorine in west based on the premise of price movement is not correct as the premise itself is not factually correct. The CRISIL report itself shows that there are many occasions when caustic price in south has fallen but the price increased in west. However, the ECU realization has been more in south than west. It is primarily on the ground that the cost of salt, the main raw material at the factory gate is less in west than south on account of abundant salt supply in west. It is also a fact that west zone has higher production capacity and higher demand. There may be different level of competition at different places. The different levels of competition at different places are natural market conditions, as it is inconceivable that all places would have identical market condition. Further, it also very difficult to conclude that higher competition at one part of country

than other part, would lead to increased import in the country or it would cause serious injury to the domestic industry. Therefore, the contention that the production has been affected by oversupply of chlorine during the period of investigation is unsubstantiated. Further, higher competition in west or any part is not a relevant factor.

- 424.Submissions by Interested Parties:** There is oversupply in western zone on account of over capacity. There is lesser availability on account of increase in capacity in East Zone. The rise in import is to meet the growing demand in India, as domestic industry is not able to meet the demand.
- 425.Analysis of submissions:** The analysis of port wise imports in East Zone shows that there is negligible import in ports except Visakhapatnam port. The Visakhapatnam port has imports of caustic soda mainly by the Aluminum manufacturers. Amongst Aluminum manufacturers, except Vedanta, all the other manufacturers rely mainly on domestic caustic soda. However, during 2009-10, the consumption pattern changed in favor of imports. M/s Vedanta met 100% of its requirement through imports in 2009 against about only 2/3rd in 2008. Similarly the share of imports in the consumption of other aluminium manufacturers has also gone up. This is on account of falling international prices. As far as supply to Vedanta is concerned, their problems in procurement of domestic caustic soda are on account of constraint in logistics.
- 426.Submissions by Interested Parties:** Some of the interested parties have submitted that the sales volume of Indian industry is more than import sales, hence there is no injury.
- 427.Analysis of submissions:** It is observed that it is not necessary for 'serious injury' or 'threat of serious injury' to have more import sales than sales by domestic industry. The detailed analysis of all relevant parameters relevant for determination 'serious injury' or 'threat of serious injury' has been done in the findings.
- 428.Submissions by Interested Parties:** Another interested party has contended that the increase in imports in India is due to the fact that users of Caustic Soda in India are facing shortage of supply of caustic soda, especially, for the caustic soda lye. The production of Caustic Soda is fully dependent on production and sale volume of chlorine. Chlorine's biggest end use is in the area of edc, vcm and pvc resins. Most of Indian Chlor-Alkali manufacturers are not integrated to edc, vcm and pvc and thus they have problem increasing their production of Caustic Soda because they are not expanding production to the edc, vcm and pvc. Majority of the Chlor-Alkali manufacturers in India only produce merchant chlorine which has very small end market all over world including India. Merchant Chlorine storage is very difficult, costly and dangerous. As a result chlorine production cannot be increased to support more production of Caustic Soda.
- 429.Analysis of submissions:** The issue of market of chlorine and its pricing patterns has been studied. It is a fact that the consumption pattern of chlorine in India and other countries is different. The consumption pattern, in turn causes different pricing patterns in different countries. This issue has been discussed at length in para 392-394. As far as capability of market to absorb chlorine is

concerned, India has sufficient capacity to absorb and consume chlorine. The price pattern of chlorine, which is dependent on demand and supply, shows that the prices of chlorine were negative when supply became more than the demand. But after December 2008, the price of chlorine is showing upward trends, which shows that demand is more favorable than the supply. Further, there are a number of Chloro-derivatives, which has export market. In case the chlorine supply increases, the natural corollary is fall in price, which makes export of Chloro-derivatives competitive fueling demand of chlorine in domestic market. Therefore, India would have consumed all chlorine had it been produced along with caustic soda to meet increased demand in absence of increased imports.

430.Submissions by Interested Parties: Various interested parties have submitted that there is no adjustment plan.

431.Analysis of submissions: It is seen that the applicants have submitted the restructuring plan, (non confidential version is available in Public File). However, the analysis of adjustment plan is required only when the duty is for more than a year.

432.Submissions by Interested Parties: The international prices have seen upward trend from September, 2009. The international price trend has been as mentioned in the table below. The imposition of provisional duty is primarily based on decreasing prices in USA and widening gap between Indian domestic price and price at which caustic soda is available for exports. As the international prices have steadily gone up leading to reduced gap between domestic sale prices and price at which caustic soda is available in USA, the ground of imposition of provisional safeguard duty does not exist. Further, the landed cost of imported caustic soda is more than the domestic price. Thus, the imported caustic soda can not cause any threat to the domestic industry. The imports even at prices higher than domestic prices at the factory gate are inevitable on account of very high freight and inability of caustic soda manufacturers to supply domestic users as apparent from demand supply mismatch.

Period	International Prices for Export (in US \$/DMT)		
	A	B	C
(Rs/DMT)	North America	Europe	Asia
April'09	225-325	200-250	200-250
May'09	130-160	170-200	200-240
June'09	90-110	90-120	170-200
July'09	35-75	50-60	130-150
August'09	40-65	60-80	115-150
September'09	125-150	140-170	210-230
October'09	160-170	180-210	200-225
November'09	160-170	200-220	190-210
December'09	160-170	180-200	190-210

January'10	160-180	180-200	190-210
February'10	200-220	180-200	180-215
March'10	220-230	190-200	200-220

433. Analysis of submissions: The issue has been analyzed in light of the submissions by the domestic industry and facts available. It is a fact that caustic soda prices crossed US\$100 mark in September 2009 and going up steadily thereafter. The preliminary findings have relied upon the data up to July'09. Incidentally, the July, 2009 witnessed the least international price of Caustic Soda and then moved up steadily to April, 2009 level in March, 2010. It is observed that quarter starting from April, 09 had witnessed fall in profit but still the profit was significantly positive. It is also observed that the Caustic Soda Industry was viable in the quarter i.e April-June, 2009 as ECU realization was more than the ECU cost. The international prices during February-March, 2010 in North America have been more than US\$200. Therefore, there is a complete change in scenario post September, 2009 as far as international prices are concerned. The prime factor, which had made domestic industry unviable, has diminished. Further, the main reason, which had caused imports and threatened to cause serious injury to the domestic industry, i.e sudden fall in spot price of caustic soda in North America is showing strong signs of improvement. These factors are crucial and the same have been considered while determining the duration of imposition of safeguard duty.

434. Public Interest: The Chlor-Alkali industry provides input to a large number of industries. Caustic Soda is used in chemical, paper, soap and metal industry. It is also used as a cleaning agent. For the healthy growth of all these industries it is necessary that steady and reliable supply of caustic soda is available.

435. Chlorine is used as a disinfectant and purifier, in plastics and polymers, solvents, agrochemicals and pharmaceuticals, as well as an intermediate in manufacturing other substances where it is not contained in the final product. Chlorine is used worldwide to purify water supplies as the ultimate defense against waterborne microbiological infection. Modern day cholera and other water borne diseases in India exemplify the devastating consequences of contaminated water and poor sanitation. Chlorine also plays a critical role in the production of thousands of commercial products. Products reliant on unique properties of chlorine include everyday household items such as household bleach and swimming pool disinfectants, bullet-resistant vests, computer hardware, silicon chips and automotive parts.

436. The local availability of chlorine for these industries is crucial. It is necessary that India has a viable and healthy chlor-alkali industry for its economic development.

437. Further, while determining the safeguard duty, care has been taken to ensure that the tariff level is maintained only up to the limit where imports are still viable and can compete with domestic products on a level playing field as the Anti Dumping

duty are also in force. The existence of a healthy Chlor-Alkali industry is in the interest of manufacturers, end users and consumers. The Chlor-Alkali industry is the life line to chlorine based industries, as chlorine is supplied by the domestic producers only. In case, chlor-alkali industry becomes unviable, the chlorine based industries would be adversely affected on account of non supply of chlorine.

- 438.Imposition of Safeguard duty when anti-dumping duty is already in operation:** The issue whether Safeguard Duty can be imposed when Anti dumping duty is already in place was examined. The Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Anti dumping Duty not exceeding the margin of dumping. The Section 8B deals with imposition of Safeguard duty in certain circumstances. This circumstances under which the two duties can be imposed are different. Further, the sub section (3) of Section 8B envisages imposition of a number of duties at the same time under the Customs Tariff Act, 1975 or under any other law for the time being in force. The sub section 3 reads as

“the duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time being in force.”

Accordingly, there is no bar imposed by law on imposition of Safeguard Duty when Anti dumping duty is already in place.

- 439.** However, there have been various submissions from interested parties, who have submitted against the desirability of imposition of both duties simultaneously. They have also submitted that imposition of both duties at the same time is not in the public interest. The issue has been analyzed. It is a fact that anti-dumping duty is also a trade remedy measure to counter and neutralize the ill effects of dumped imports through raising tariff barrier. Safeguard duty is a measure to protect the domestic industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common i.e neutralizing injurious effects of imports, besides other functions. Therefore, it is imperative that the safeguard duty may be imposed and continued only when the existing trade remedies measures, in whatever form, are not able to protect the domestic industry. It is also implied that the multiple protection is available only to the extent it is necessary.
- 440.** In the instant case, it is a fact that imports increased many fold even after the existence of anti-dumping duties. The increase in imports at a very low price threatened to cause serious injury.
- 441.** The analysis done in earlier paragraphs show that the pressure caused by wide arbitrage window was responsible for increased imports. The existing tariff barrier, which included anti-dumping duty, was not sufficient enough to prevent permeation of imports in large quantity. Therefore, multiple trade remedy measures are justified to neutralize the injurious effects of imports. However, the prudence in use of multiple trade remedy measures requires that it is limited to the

period and extent which is necessary, so that the placing of burden of safeguard duty on end users is justified.

442. **Trend of International Prices:** The Analysis of data up to September, 2009 shows that falling international prices of caustic soda caused domestic prices of caustic soda fall. It is also noticed that the fall of price in international market especially North America was much swifter than that in domestic market. This difference caused a wide arbitrage window and increased import. It is also noticed that the increase in import was despite anti-dumping duty. Further, the domestic prices respond faster than the actual arrival of imported caustic soda. In short, the international price of caustic soda is the key factor, which has affected the health of domestic industry.
443. The international price trend shows that it has sharply gone down till July, 2009. The North America spot price reached bottom to the level of US\$ 50 in July, 2009 and started looking up thereafter and crossed US\$100 mark in September, 2009. Subsequently, the prices have been going up steadily. In January, 2010 the US export spot price reached US\$ 160-US\$180 and the domestic contract price reached US\$ 210-250. The Asian export price remained above US\$ 200 after September, 2009. The Europe Export prices are in the range of US\$180-210. However, the domestic prices of Europe remained firm to Euro 285-295. The February and March, 2010 price in North America was above US\$200. Further, the overall upward price trend in international market of caustic soda is continuing.
444. The analysis of performance of domestic industry shows that the increased import had only marginal impact on volume parameters but had significant impact on net sales realization and profitability of the domestic industry. It is also noticed that it was the sub US\$100 export price of USA which had made the domestic industry unviable. The industry was profitable before June, 2009 even when imports increased and international price was in the range of US\$130-160 (FOB North America), US\$170-200 (FOB Europe) and US\$200-240 (FOB Asia). It has been noticed that international prices have been above or in the similar range in at least past four months. The Harriman Chemsult Limited reports improved demand and capacity utilization in USA, Europe, Japan and Korea. The February issue of the Harimman Consultant reports that the \$75/dst caustic soda price increase is gaining further acceptance in the US market; the announcement of a second increase has given greater impetus to the solidification of the +\$75/dst. Several producers have nominated +\$80/dst, but one producer has opted for +\$100/dst. The contract prices remain much higher than the spot price. The domestic prices of USA have also gone up significantly. All these factors show recovery in the caustic soda industry.
445. **Chlorine Prices:** The chlorine spot price in USA was \$475-525/MT in July 2009, which dropped to US\$ 240-265/MT in February, 2010. The 19th February issue of Harriman Chemsult Limited reports that there is mounting downward pressure on prices of chlorine. The March, 2010 price of Chlorine was US\$ 225-250. This shows falling trend of Chlorine prices in US market.
446. **Effect of Chlorine prices on caustic soda price:** Ordinarily, the price movements of chlorine and caustic soda are in opposite direction. The sudden fall

in caustic soda price was triggered by high demand of chlorine and low off take of caustic soda, causing sudden rise of chlorine price. However, with decline in price of chlorine to nearly half or by around \$250 has put upward pressure on prices of caustic soda in international market. Once the Chlorine prices go down, keeping the old low price becomes unviable, as it would adversely affect the ECU realization and overall profitability. Therefore, the prices of caustic soda have moved upward to balance reduction in Chlorine prices. Harriman Chemsult Limited also justifies future rise in Caustic Soda prices. Under these circumstances, the trend shows that, it is unlikely that prices would go down to sub US\$100 range.

447. At such prices, there is no evidence produced by the domestic industry that the Chlor-Alkali industry is unviable, when at such prices the domestic industry was making profit during April and May, 2009. The international prices of caustic soda have been very high till March, 2009 and so the net sales realization. However, the fall in international prices led to fall in net sales realization too after July, 2009. Certain fluctuation in international prices and domestic prices are part of the usual business cycle, but, when the fluctuation in price is such that it makes the industry unviable, the imposition of safeguard duty in addition to anti-dumping duty is in public interest as long as it is limited to keeping the industry viable. In the instant case, the provisional safeguard duty has been able to curtail imports by raising the tariff barrier and provide protection from sudden fall of international price. However, latter developments i.e improvements in prices of caustic soda in the international market do not justify imposition of safeguard duty when anti-dumping duties are already in place. Therefore, it has been in the public interest to impose safeguard duty promptly but it is not in the public interest to continue imposition of safeguard duty for further period.

Developing Nations:

448. The percentage of imports from developing nations has also been examined. Except China, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia and Thailand who constitute 46.6%, 22.4%, 10.4%, 6.53% and 7.09% of total imports in India in F.Y. 08-09, other developing nations individually have less than 3% of total imports in India. Therefore, the import of product under consideration originating from developing nations except China, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia and Thailand may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

Conclusion and Recommendation

449. In view of the findings above, the final determination is that the increased imports of Caustic Soda in Lye form into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Caustic Soda in Lye form. In arriving at the amount of safeguard duty which would be adequate to prevent threat of serious injury to the domestic industry, weighted average cost of sales at reasonable

return on employed capital and average landed cost of import (taking basic customs duty, cess and anti-dumping duty, if any, into account) have been considered. Further, the calculated safeguard duty has been moderated downward to allow imports to maintain competition in domestic market in the interest of end users and consumers. The public interest has also been considered in detail. Accordingly, safeguard duty at the rate of 15% ad valorem for three months (starting from the date of imposition of provisional duty i.e 4.12.2009 to 3.3.2010) is considered to be the minimum requirement to protect the interest of domestic industry. The same is recommended to be imposed on imports of Caustic Soda lye falling under subheading 28151200 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975.

450.As the imports from developing nations except China, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia and Thailand do not exceed 3% individually, the import of product under consideration originating from developing nations except China, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia and Thailand may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No.D-22011/47/2009]

I.D. MAJUMDER, Director General (Safeguards)